चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 06 मार्च– 12 मार्च 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मदरसों की बेजा गतिविधियों के ख़िलाफ़ लखनऊ में बड़ी मुहिम

धर्म का धंधा बहुत ही गंदा

प्रभात रंजन दीन

शरियत ताक़ पर रख कर चला रहे हैं ग़ैर-इस्लामिक गतिविधियां

देश-विदेश से मिल रहे अकूत धन का हो रहा है बेजा इस्तेमाल

मदरसे की छात्राओं ने प्रबंधन के ख़िलाफ़ फूंक दिया विद्रोह का बिगुल

उत्तर प्रदेश में मदरसों का धंधा बेतहाशा चल रहा है. देश-विदेश के विभिन्न स्रोतों से आने वाला फंड धंधेबाजों को मदरसे का धंधा चलाने के लिए आकर्षित करता है. कई भारतीय मध्य-पूर्व के देशों में महज इसलिए बस गए हैं कि वे वहां से फंड हासिल करें और अपने निजी अकाउंट से धन ट्रांसफर करते रहें. इसमें विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. मदरसे का धंधा चैरिटेबल सोसाइटी और चैरिटेबल ट्रस्ट का सहारा लेकर चलाया जा रहा है. मदरसे के धंधे की आड़ में ही तमाम अनैतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुछ बुद्धिजीवियों ने मदरसों की आड़ लेकर चलाए जा रहे धंधे के खिलाफ सामाजिक मुहिम छेड़ दी है.

मदरसों में शरियत को ताक पर रखने, फंडिंग का बेजा इस्तेमाल करने और छात्र-छात्राओं के साथ अश्लील आचरण करने जैसे जघन्य कृत्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर मुहिम चल रही है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उठी मशाल पूरे प्रदेश और देश में ली जगाएगी. शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि धार्मिक शिक्षण के स्थान खुदा की इबादत की तरह पवित्र होते हैं, उसे अपने आचरणों से अपवित्र करना गैर-धार्मिक और गैर-इस्लामिक है. उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना सैयद कौकब मुज्तबा ने भी कहा कि मदरसों के नाम पर धंधा चलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक है. इस्लामिक साहित्य के विद्वान अल्लामा जमीर नकवी के नेतृत्व में कई बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों ने इसका बीड़ा उठाया है और इरान की अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध व कुवैत से फंडेड लखनऊ के दो मदरसों से अभियान की शुरुआत की है.

लखनऊ के सआदतगंज स्थित कश्मीरी मोहल्ले में अल-ज़हरा एडुकेशनल एंड चैरिटेबिल सोसाइटी के तहत चल रहे मदरसा अल-ज़हरा और मदरसा खदीजतुल कुबरा को केंद्र में रख कर अभियान की शुरुआत की गई है. अल्लामा जमीर नकवी कहते हैं कि ये मदरसे छात्राओं को धार्मिक शिक्षण देने के लिए बने हैं. छात्राओं का मदरसा होने के कारण ये अधिक संवेदनशील हैं, इसलिए यहां से अभियान की शुरुआत की गई है. इन मदरसों में सुधार हुआ तो उसका व्यापक संदेश जाएगा और अन्य मदरसे भी सुधरने की तरफ अग्रसर होंगे. अधिकतर मदरसों में देश-विदेश के विभिन्न स्रोतों से धन आता है. इसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा तमाम गैर शरियती गतिविधियां चलती हैं. यह अत्यंत चिंता का विषय है. नकवी कहते हैं कि अल-ज़हरा एडुकेशनल एंड चैरिटेबिल सोसाइटी का संस्थागत अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा की नक्खास शाखा में है, लेकिन देश-विदेश के विभिन्न स्रोतों से आने वाला फंड लखनऊ के नादान महल रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक (अकाउंट नंबर- 000401408949) में जमा होता है. यह एनआरआई अकाउंट है, जो संस्था के अध्यक्ष सैयद शम्स नवाब रिज़वी के नाम है. संस्था के अध्यक्ष विदेश में ही रहते हैं, लेकिन उनके इस अकाउंट को संस्था के उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) सैयद जहीर हुसैन रिजवी लखनऊ में ऑपरेट करते हैं. जबकि उक्त बैंक खाता मूल रूप से आईसीआईसीआई की कुवैत (सऊदी अरब) शाखा से सम्बद्ध है. नकवी इस पर सवाल उठाते हैं कि मदरसे को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशियां आईसीआईसीआई के निजी खाते में प्राप्त की जाती हैं और फिर उसे संस्था के आधिकारिक खाते में स्थानान्तरित किया जाता है. इसके अलावा अलग-अलग छोटी-छोटी धनराशियां मदरसे के खाते में जमा कराई जाती हैं. इसका क्या कारण है? इस तरह की गुत्थियों की वजह से यह सुनिश्चित नहीं होता कि मदरसों के लिए किन-किन स्रोतों से अनुदान राशि कितनी-कितनी और कब-कब प्राप्त हो रही है. जमीर नकवी कहते हैं कि कुवैत के सांसद सालेह अहमद आशूर की तरफ से भेजा गया धन भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी पुष्टि बैंक खातों द्वारा होती है. इन खातों की जांच की कानूनी कार्रवाइयों के लिए भी पहल हो रही है, ताकि यह पता चल सके कि मदरसे की आड़ में काले धन का धंधा तो नहीं चल रहा है! जिस तरह की गतिविधियां सामने आई हैं, उससे इस तरह के संदेह पुख्ता होते हैं.

इन मदरसों के तहत लड़कियों के हॉस्टल और अनाथालय बनाए जाने के लिए हरदोई रोड के निर्जन इलाके में 12 हजार वर्ग फिट जमीन खरीदी गई. नकवी यह सवाल उठाते हैं कि जब जमीन खरीद ली गई, तो वहां हॉस्टल और अनाथालय क्यों नहीं बनवाया गया? क्या कारण है कि बालिकाओं के अनाथालय के लिए शहर से दूर बियाबान इलाके में भूमि खरीदी गई और हॉस्टल के नाम पर एक करोड़ की धनराशि खर्च दिखा कर लखनऊ के शाह नजफ रुस्तम नगर के सामने तीन फिट की संकरी गली में हॉस्टल के लिए एक घर (प्लॉट नं- 565, मकान नं.-390/067 (036) आधी राशि में खरीद लिया गया? हॉस्टल के लिए उक्त घर को 49 लाख 16 हजार रुपये में खरीदा गया, जिसकी रजिस्ट्री (दिनांक-21-12-2015) में 3 लाख 43 हजार रुपये का स्टाम्प लगा, यानि कुल 52 लाख 59 हजार रुपये लगे. लेकिन इस हॉस्टल को एक करोड़ में खरीदा दिखाया गया. स्पष्ट है कि वित्तीय अनियमितता हुई. हॉस्टल के लिए खरीदे गए भवन के रख-रखाव और फिनिशिंग का काम रज़ा कंस्ट्रक्शन वर्क (295/113, अशरफ़ाबाद, थाना- बाजारखाला, लखनऊ) को दिया गया था, जिसके लिए उसे 12-01-2016 को 1 लाख 70 हजार 240 रुपये का भुगतान किया गया. अगर इस राशि को भी जोड़ दिया जाए तो हॉस्टल पर कुल 54 लाख, 29 हजार 240 रुपये ही खर्च हुए. फिर 45 लाख 70 हजार 760 रुपये कहां गए? यह सवाल सामने है.

विचित्र बात यह है कि मदरसे के कर्ता-धर्ता व अल-ज़हरा एडुकेशनल एंड चैरिटेबिल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सैयद जहीर हुसैन रिजवी ने आईसीआईसीआई बैंक के खाते से 01.12.2015 को 50 लाख 50 हजार 439 रुपये 41 पैसे निकाले. फिर 07.12.2015 को 10 लाख रुपये (शेष पृष्ठ 2 पर)

मदरसे के सेक्रेटरी मुज्तबा हुसैन

अध्यक्ष सैयद शम्स नवाब रिज़वी (पुरानी फोटो)

अराजकता के ख़िलाफ़ मुहिम : अल्लामा ज़मीर नक़वी

बिहार : दोस्ती में दरार कैसे होगा बेड़ा पार | P-4

धनबाद : सरकार की बेशर्मी और बेहयाई से लोग नग्न होने पर मजबूर | P-5

क्या कहता है आपका टैरो कार्ड | P-7

धर्म का धंधा बहुत ही गंदा

पृष्ठ 1 का शेष

निकाले. दिनांक 14.12.2015 को फिर से 10 दस लाख रुपये निकाले गए. दिनांक 17.12.2015 को भी 10 लाख रुपये निकाले और फिर दो ही दिन बाद दिनांक 19.12.2015 को फिर पांच लाख रुपये निकाले. यानि संस्था के उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से महज 19 दिन में कुल 85 लाख 50 हजार 439 रुपये 41 पैसे निकाल लिए गए. इतनी बड़ी धनराशि आखिर किस मद में खर्च हुई? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है. अल-ज़हरा एडुकेशनल एंड चैरिटेबिल सोसाइटी से हासिल दस्तेवज बताते हैं कि अनाथ बच्चों, विधवाओं, रोगियों वगैरह की सहायता के नाम पर भी बैंक से अंधाधुंध पैसे निकाले जाते हैं. दिनांक 10.04.2014 को 1 लाख 11 हजार 265 रुपये निकाले गए तो अगले ही दिन 11.04.2014 को संस्था के बैंक ऑफ बड़ौदा के आधिकारिक खाते से 11 हजार 395 रुपये निकाले गए. फिर उसके भी अगले दिन 12-04-2014 को 51 हजार 548 रुपये निकाले गए. तीन दिन बाद 15.04.2014 को फिर 1 लाख रुपये निकाले. उसी दिन कुर्बानी के नाम पर 10 हजार रुपये निकाले गए. दूसरे ही दिन 16.04.2014 को अनाथों के नाम पर 32 हजार 489 रुपये निकले. उसी दिन 7 हजार 850 रुपये और निकले. 17.04.2014 को फिर 21 हजार 709 रुपये निकाले गए. यह कुछ बानगियां हैं. इस तरह बैंक खाते से बेतहाशा पैसे निकाले जाने के तमाम आंकड़े सामने आए, जिनकी जांच हो तो यह पता चले कि फंड में मिल रहा धन आता है, तो जाता कहां और किस तरह है! किन लोगों की सहायता में धन जाता है, इसका पूरा ब्यौरा गहराई से जांच-पड़ताल का विषय है और यह भीषण भ्रष्टाचार का अंदेशा देता है. मदरसे का सालाना खर्च करोड़ में दिखाया जाता है. इसका ब्यौरा देखेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा. इसमें ऐसे खर्चे भी शामिल हैं जो कभी होते ही नहीं. लोग कहते हैं कि इरान के अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध होने के कारण शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन जैसे कई खर्चे तो वहां से आते हैं. हालांकि उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना सैयद कौकब मुज्तबा कहते हैं कि इरान के उक्त यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध बताना भी फर्जीवाड़ा है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का कोई शैक्षणिक कार्यकलाप भारत में है ही नहीं. इस यूनिवर्सिटी का नाम ही फर्जी गोरखधंधों में चल रहा है.

अल्लामा जमीर नकवी कहते हैं कि लड़कियों के मदरसे का सारा प्रबंधन पुरुषों के हाथ में है. मदरसे का अर्थ-सूत्र कुवैत में बैठे सैयद शम्स नवाब रिजवी और कुवैत के सांसद सालेह आशूर के हाथों में है, तो लखनऊ में मैनेजमेंट की बागडोर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सैयद जहीर हुसैन रिजवी और सेक्रेटरी मुज्तबा हुसैन के हाथों में है. लड़कियों के मदरसे में सोसाइटी के सेक्रेटरी मुज्तबा हुसैन के बेटे सिब्तैन हुसैन और नूरैन हुसैन की भी जबरदस्त घुसपैठ है. यहां तक कि सेक्रेटरी के बेटे को भी संस्था से पैसे मिलते हैं. आईसीआईसीआई बैंक से मिले दस्तावेज ऐसे कई अजीबोगरीब लेन-देन का खुलासा करते हैं. मसलन, सोसाइटी में चपरासी रहे अम्बर मेहदी को कुछ ही अंतराल में दो लाख रुपये दिए गए. पैसे प्राप्त करने वाले लोगों की फेहरिस्त में कई नाम ऐसे हैं, जिन्हें बार-बार संस्था की तरफ से लाखों रुपये दिए जा रहे हैं या वे संस्था की तरफ से बार-बार पैसे निकाल रहे हैं, वह भी लाखों में. अम्बर मेहदी संस्था में चपरासी थे. अम्बर की दो बेटियां बेबी फातिमा और जेबा फातिमा उसी मदरसे में पढ़ती थीं. आज बेबी फातिमा उसी मदरसे की प्रिंसिपल बनी बैठी हैं. लेकिन बेबी फातिमा उर्फ फरहा हदीस खान को प्रिंसिपल बनाए जाने के बाद ही अम्बर मेहदी को सोसाइटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

शरियत कहता है कि महिलाओं के लिए बने धार्मिक मदरसों को अगर पुरुष संचालित कर रहा हो, तो उसे इस्लामिक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. लेकिन इन मदरसों में इसका ठीक उल्टा हो रहा है. मदरसा प्रबंधन देखने वाले लोग फिल्मी हस्तियों के साथ उठते-बैठते हैं. क्लबों में शराब पीते हैं, नाचते हैं और पाश्चात्य कपड़े पहन कर डोलते हैं. शरियत का उल्लंघन इस हद तक है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं का हिजाब हटवा कर उन्हें संबोधित करने से कतई परहेज नहीं करते. जबकि छात्राओं को पढ़ाने के लिए मदरसे में महिला शिक्षिकाएं नियुक्त हैं. नकवी इस पर भी सवाल उठाते हैं कि उक्त दोनों मदरसे 10 साल से छोटी उम्र की बच्चियों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए बने थे, लेकिन तीन-चार साल से वहां बालिग लड़कियां पढ़ाई जाने लगीं. उर्दू अखबार नकीब के एडिटर मौलाना असीफ जायसी कहते हैं कि उसूलन तो लड़कियों के मदरसे मौलानाओं द्वारा संचालित होने चाहिए और मदरसे का अंदरूनी प्रबंधन मौलानाओं की बेगमों और अन्य महिला सदस्यों द्वारा देखा जाना चाहिए. मौलाना जायसी कहते हैं, लेकिन इनका क्या है, ये तो धंधे और चंदे के लिए मदरसा खोल लेते हैं, इन्हें शरियत से क्या लेना देना! विडंबना यह है कि मदरसे की कई छात्राओं और शिक्षिकाओं के साथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट सैयद शम्स नवाब रिजवी समेत कई लोगों के व्हाट्स-एप और ई-मेल पर भेजे गए आपत्तिजनक प्रस्ताव और बगैर हिजाब के फोटो भेजने के मेल-संदेश पकड़े जाने के बावजूद उन हरकतों पर पर्दा डाल दिया गया. लड़कियों को पासपोर्ट बनवाने और विदेश

(शेष पृष्ठ 3 पर)

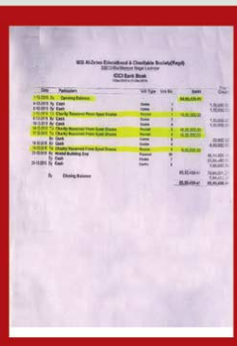

उत्तर प्रदेश के मदरसों को सर्वाधिक चंदा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब से मिल रहा है. इसके बाद कुवैत, ब्रिटेन और कनाडा का स्थान आता है. मदरसों के जरिए ही आईएसआईएस का धन उत्तर प्रदेश लाए जाने का भी खुलासा हुआ है. यूपी के हरदोई में हाल ही में गिरफ्तार हुए आंतकी अब्दुल शमी कासमी उर्फ शमीउल्लाह ने केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बताया कि आईएसआईएस बड़े ही शातिर तरीके से अपने धन की घुसपैठ करा रहा है. शमीउल्लाह के मुताबिक मदरसों और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए आईएसआईएस की रकम यहां आ रही है. शमीउल्लाह 2007 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है.

धन का धंधा करने वाले फ़र्ज़ी मदरसों की बाढ़

पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों की बाढ़ है. विभिन्न स्रोतों से मिलने वाले फंड और आर्थिक सहायता के प्रलोभन में मदरसों का धंधा चल रहा है. उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में तकरीबन दो सौ ऐसे मदरसे पाए गए जो हकीकत में नहीं, केवल सरकारी फाइलों पर चल रहे थे. मदरसों के नाम पर ये सरकार से करोड़ों रुपये प्राप्त भी कर रहे थे. इन फर्जी मदरसों के पतों पर पढ़ाने-लिखाने का काम नहीं, बल्कि अलग-अलग किस्म की दुकानदारी चल रही थी. कहीं कोई चाय की दुकान चला रहा था, तो कोई ब्यूटी पार्लर. किसी के घर का एक कोना मदरसा दिखाया जा रहा था, तो कहीं खाली पड़ा प्लॉट. लखनऊ में भी ऐसे एक घर को मदरसा दिखा कर सरकारी धन को लंबे अर्से से चूना लगाया जा रहा था. जबकि असलियत में वहां मदरसा होने की कोई शिनाख्त ही नहीं थी. कागज पर जिस घर में मदरसा दिखाया जा रहा था, वहां छानबीन करने पर कोई हिंदू किरायेदार पाया गया. उसने वहां मदरसा होने की बात पर गहरा आश्चर्य जाहिर किया. कई मस्जिदों को भी मदरसा दिखाया जा रहा है. मेरठ में करीब 50 मदरसे फर्जी पाए गए थे. इनमें से कई तथाकथित मदरसों में परचून की दुकान या कोई दूसरा धंधा चलता हुआ पकड़ा गया. फर्जी मदरसों का धंधा लंबे समय से चल रहा है. धंधा करने वाले लोग सरकारी नुमाइंदों से मिलीभगत करके सरकार से मिलने वाली धनराशि की बंदरबांट कर लेते हैं. ऐसे कई मदरसों की मान्यता भी रद्द की गई. लेकिन तथ्य यही है कि ऐसे फर्जी मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सम्बद्ध सरकारी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों का संरक्षण मिला हुआ है. ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं कि फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर कुछ दिनों के लिए उन्हें किनारे कर दिया जाता है और कुछ अंतराल के बाद उनका धंधा फिर से चालू हो जाता है. ■

कुवैत के एमपी का लखनऊ में स्वागत

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 01
06 मार्च- 12 मार्च 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

धर्म का धंधा बहुत ही गंदा

पृष्ठ 2 का शेष

बुलवाने के लिए दबाव देने के मेल-संदेश भी पकड़े जा चुके हैं. लड़कियों के मदरसों में हो रही इस तरह की बेजा हरकतों पर उर्दू अखबार नकीब के एडिटर मौलाना असीफ जायसी कहते हैं, सोसाइटी के मालिक शम्स के बारे में ऐसी जानकारियां तो मिलती रही हैं, खुद तो कुवैत में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को यहां रख छोड़ा है. कोई मजहबी व्यक्ति होता तो धार्मिक संस्था के रूप में मदरसे की स्थापना करता. लेकिन वह मजहबी आदमी तो हैं नहीं, वह तो किसी का एजेंट हैं, बहुत चालू किस्म का आदमी है वो, उसका धर्म-वर्म से तो कोई लेना-देना है नहीं. इसने केवल चोला पहन रखा है. मदरसा वगैरह खोलना तो वैसे ही है. इसके पीछे मकसद कुछ और है. उसके खिलाफ बहुत सी खबरें आती हैं. ये आदमी खुद ठीक नहीं है. उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए. शम्स बाहर से बहुत बड़ी रकम लाता है, लेकिन उसके बारे में सरकार को जानकारी देता है या नहीं, यह तो सरकार ही बता सकती है. जायसी यह भी कहते हैं कि इस्लामी विद्वान अल्लामा जमीर नकवी ने मदरसे की आड़ में चल रही करतूतें पकड़ी हैं और उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं. अल्लामा जमीर नकवी ने कहा कि जो लोग पवित्र मदरसों को अपवित्र कर रहे हैं, उन पर धर्मगुरुओं को सख्ती से पेश आना चाहिए. नकवी कहते हैं, यहां तो सोसाइटी के प्रेसिडेंट के साथ-साथ सारे पदाधिकारी अपनी हरकतों में मुब्तिला हैं. प्रेसिडेंट की करतूतों के बारे में आपने सुना. वाइस प्रेसिडेंट सैय्यद ज़हीर हुसैन रिज़वी भी वैसे ही हैं. रिज़वी ने भी मदरसे से ही सम्बद्ध रही एक अध्यापिका से शादी कर ली, जबकि वह पहले से शादी-शुदा था. रिजवी की पत्नियों के लिए मदरसे के पैसों से ही घर खरीदे गए हैं. इसके अलावा भी रिज़वी की कई चल-अचल सम्पत्तियों के बारे में पता चला है. इसीलिए मदरसों के गोरखधंधों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए. जांच का विषय यह भी है कि संस्था के अध्यक्ष सैयद शम्स नवाब रिजवी जब विदेश में ही रहते हैं, तो संस्था के नवीनीकरण समेत तमाम कानूनी औपचारिकताएं कैसे पूरी हो जाती हैं? इसमें जरूर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है.

मदरसे में आतंक का साम्राज्य है. संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, आपत्तिजनक प्रलोभन-प्रस्ताव या गैर वाजिब गतिविधियों के खिलाफ जिसने भी मुंह खोला, उसे फौरन बाहर निकाल दिया जाता है. बर्खास्त होने वालों में कर्मचारी, अध्यापिकाएं और छात्राएं शामिल हैं. प्रबंधन के शीर्ष अधिकारियों की बेजा हरकतों या भ्रष्टाचार के खिलाफ उंगली उठाने वाली कई अध्यापिकाओं और छात्राओं के प्रबंधन को लिखे गए विरोध पत्र, उनसे जबरन लिखवाए गए इस्तीफे, संस्था में व्याप्त अराजकता, आपत्तिजनक व्यवहार और तानाशाही के खिलाफ दिए गए लड़कियों के तमाम बयान चौथी दुनिया के पास उपलब्ध और सुरक्षित हैं. हम उन अध्यापिकाओं और छात्राओं का नाम नहीं छाप रहे हैं. लेकिन यह हकीकत है कि कुछ अध्यापिकाओं और छात्राओं ने अत्याचार-अनाचार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है. संस्था के प्रेसिडेंट व अन्य पदाधिकारियों द्वारा लड़कियों को लिखे गए आपत्तिजनक व्हाट्सएप मैसेज और ई-मेल संदेश वगैरह भी चौथी दुनिया के पास सुरक्षित हैं. इसके भी प्रमाण हैं कि जिसने प्रबंधन के आगे सिर झुका दिए, उसके आगे सारी सुख-सुविधाएं बिछा दी गईं. ऐसे कुछ खास शख्स को मदरसों में अध्यापिकाओं को नियुक्त करने का सर्वाधिकार भी दे दिया जाता है और उसके नाम व फोन नंबर के साथ अखबार में विज्ञापन भी छपने लगता है. इस्लामी बुद्धिजीवी और धार्मिक जमात के लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण और इस्लाम विरोधी आचरण बताते हैं. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास कहते हैं कि औपचारिक रूप से मामला पेश होने पर बोर्ड इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है. बाकायदा कमेटी गठित कर जांच कराई जाएगी और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी. मौलाना अब्बास कहते हैं कि मदरसे जैसी पाक-पवित्र जगहों पर इस तरह की गतिविधियां चलती हैं, तो ऐसे मदरसों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए. बोर्ड में इस मामले को औपचारिक रूप से पेश किए जाने के बारे में पूछने पर अल्लामा जमीर नकवी कहते हैं कि इस मामले को न केवल बोर्ड बल्कि कानून की प्रत्येक दहलीज तक ले जाए जाने की तैयारी है. नकवी कहते हैं, धीरे-धीरे हम लखनऊ और यूपी के सारे मदरसों के सुधार की पहल कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना सैयद कौकब मुजतबा ने इस बारे में पूछने पर कहा कि सोसाइटी अगर मदरसा बोर्ड से मान्यता लिए बगैर मदरसा चला रही है तो यह गैर कानूनी है. विदेश से आने वाले फंड की निगरानी के लिए बने विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत अगर क्लीयरेंस नहीं ली गई है तो यह आपराधिक कृत्य के दायरे में आएगा. इस पर सीधे कार्रवाई की जा सकती है. मौलाना मुजतबा कहते हैं कि लखनऊ में कुछ ही मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, बाकी तो सब धंधे हैं और दुकानें चल रही हैं. कई तो केवल कागजी होते हैं. कई मदरसे तो घरों में चल रहे हैं, जहां पर कट्टरपंथ की तालीम दी जा रही है. कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिसमें मदरसा चलाया जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में कागजों पर मदरसा नाम हटा कर चैरिटेबल या ट्रस्ट लगा देते हैं. मौलाना कहते हैं कि लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस, नाजमिया, तंज़ीमुल मुकातिब जैसे कुछ ही मान्यता प्राप्त इदारे हैं, जो बाकायदा नियम-कानून से चल रहे हैं. यहां खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानित 359 मदरसों की सूची में मदरसा अल-ज़हरा और मदरसा खदीजतुल कुबरा के नाम नहीं हैं. मौलाना सैयद कौकब मुजतबा का कहना है कि सुविधाओं और धन (फंड) की लालच में दुकानों की तरह मदरसे खोले जा रहे हैं. मदरसों में धन का लेनदेन इतना अधिक है कि मदरसा बनाकर कोई जल्दी ही अमीर बन जाता है. इस वजह से धार्मिक शिक्षा देने के बजाय मदरसे धन कमाने का धंधा बन गए हैं. ■

मर्दों द्वारा लड़कियों के मदरसे का निरीक्षण

> उसूलन तो लड़कियों के मदरसे मौलानाओं द्वारा संचालित होने चाहिए और मदरसे का अंदरूनी प्रबंधन मौलानाओं की बेगमों और अन्य महिला सदस्यों द्वारा देखा जाना चाहिए. लेकिन इनका क्या है, ये तो धंधे और चंदे के लिए मदरसा खोल लेते हैं, इन्हें शरियत से क्या लेना देना!
>
> **– मौलाना असीफ़ जायसी,**
> *एडिटर, उर्दू अखबार नकीब*

> औपचारिक रूप से मामला पेश होने पर बोर्ड इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है. बाकायदा कमेटी गठित कर जांच कराई जाएगी और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी. मदरसे जैसी पाक-पवित्र जगहों पर इस तरह की गतिविधियां चलती हैं, तो ऐसे मदरसों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए.
>
> **– मौलाना यासूब अब्बास,**
> *प्रवक्ता, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड*

> मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना सैयद कौकब मुजतबा ने इस बारे में पूछने पर कहा कि सोसाइटी अगर मदरसा बोर्ड से मान्यता लिए बगैर मदरसा चला रही है तो यह गैर कानूनी है. विदेश से आने वाले फंड की निगरानी के लिए बने विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत अगर क्लीयरेंस नहीं ली गई है तो यह आपराधिक कृत्य के दायरे में आएगा.

इस्लामिक चैरिटी फंड पाने में यूपी सबसे अव्वल

विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के आंकड़े भी बताते हैं कि इस्लामिक चैरिटी से फंड लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर है. राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से पर नेपाल बॉर्डर से जुड़े इलाकों पर चलने वाले एनजीओ को इसी तरह का फंड मिल रहा है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में छोटा सा कस्बाई शहर है इटवा. यहां तकरीबन दो दशक पहले अल फ़ारूक नामक संस्था की स्थापना कतर आधारित सैलाफी विचारधारा के उपदेशक और स्थानीय मौलाना शेख साबिर अहमद मदनी ने की थी. कतर के राज परिवार द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट से इस संस्थान को करोड़ों रुपये मिल रहे हैं. इस धन का इस्तेमाल अनाथालयों और मदरसों के निर्माण में दिखाया जाता है. लेकिन यह मूल सैलाफी विचारधारा पर चल रहा है, जो सूफी मत के बिल्कुल खिलाफ है. कतर स्थित शेख ईद बिन मोहम्मद अल थानी चैरिटेबल एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय चैरिटी संगठन के रूप में प्रदर्शित करता है, लेकिन इसके संस्थापक अब्दअल रहमान अल नुयामि को अलकायदा और अन्य इस्लामिक समूहों को फंडिंग के आरोप में अमेरिका द्वारा दिसंबर 2003 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में मदरसा व अन्य धार्मिक-सामाजिक सेवा में लगी संस्था सफा एजुकेशनल एंड टेक्निकल वेलफेयर सोसाइटी को भी कुछ ही अर्से में कुवैत से करीब पांच करोड़ रुपये मिल चुके हैं. इस फंड को भी शैक्षणिक दिखाया गया, लेकिन असलियत यही है कि वह सैलाफी विचारधारा फैलाने में ही इस्तेमाल हो रहा है. सफा समूह का मुख्य दानदाता जमियत रेहायुत तुरस अल इस्लामी है, जो रियाइवल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज सोसायटी नाम के अन्य चैरिटी से जुड़ा है. अल कायदा नेटवर्क से जुड़े होने के कारण इस सोसायटी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है. उत्तर प्रदेश के नेपाल से जुड़े इलाकों में सैलाफी विचारधारा फैलाने में लगे मदरसों का जाल बिछ गया है. नेपाल के अंदर भी मदरसों में भारतीय छात्र ही ज्यादा पढ़ रहे हैं. यूपी और नेपाल के इन मदरसों को सउदी अरब के प्रसिद्ध चैरिटी रबीता अल आलम अल इस्लामी या मुस्लिम वर्ल्ड लीग से फंड मिलता है. मुस्लिम वर्ल्ड लीग की गतिविधियां संदेहास्पद हैं. मुस्लिम वर्ल्ड लीग अफगानिस्तान समेत कई देशों में वैश्विक जेहाद के समर्थन में विश्व के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त संसाधनों के वितरण को संयोजित करता है. इसी लीग ने 1988 में पाकिस्तान में खैबा ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसे 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने इसके अलकायदा से जुड़े होने के चलते प्रतिबंधित कर दिया था.

उत्तर प्रदेश के मदरसों को सर्वाधिक चंदा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब से मिल रहा है. इसके बाद कुवैत, ब्रिटेन और कनाडा का स्थान आता है. मदरसों के जरिए ही आईएसआईएस का धन उत्तर प्रदेश लाए जाने का भी खुलासा हुआ है. यूपी के हरदोई में हाल ही गिरफ्तार हुए आंतकी अब्दुल शमी कासमी उर्फ शमीउल्लाह ने केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बताया कि आईएसआईएस बड़े ही शातिर तरीके से अपने धन की घुसपैठ करा रहा है. शमीउल्लाह के मुताबिक मदरसों और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए आईएसआईएस की रकम यहां आ रही है. शमीउल्लाह 2007 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधान परिषद चुनाव

दोस्ती में दरार, कैसे होगा बेड़ा पार

चौथी दुनिया ब्यूरो

चुनाव तो बिहार विधान परिषद की चार सीटों के लिए ही होने वाले हैं, लेकिन इससे पूरे सूबे की राजनीति में सरगर्मी आ गई है. सूबे के सत्तारूढ़ महागठबंधन का सबसे छोटा साझीदार कांग्रेस अपनी उपेक्षा से नाराज है और सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती देने के लिए ताल ठोक रहा है. विपक्षी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भी दो घटक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) आमने सामने हैं. दोनों गठबंधनों की यह राजनीतिक तनातनी गौतम बुद्ध की ज्ञानभूमि गया में साफ देखने को मिल रही है. यह दिलचस्प है कि गया की ही दोनों सीटों को लेकर सूबे के दोनों गठबंधनों में उबाल है. गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर एनडीए में कोई विवाद नहीं है, लेकिन गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की उम्मीदवारी को लेकर लोजपा अड़ गई है. महागठबंधन की ओर से इन दोनों सीटों पर राजद के प्रत्याशी हैं, जबकि स्नातक सीट पर कांग्रेस दावा करती रही है. लेकिन उसकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया. नतीजतन, उसने दोनों सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए. महागठबंधन के सबसे इकबाली नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उनकी पार्टी जनता दल(यू) की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं कहा जा रहा है. इधर एनडीए में भाजपा के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी मामले को सुलझाने में लगे हैं.

परिषद के चार निर्वाचन क्षेत्रों, गया स्नातक, गया शिक्षक, कोशी शिक्षक और सारण स्नातक के लिए 9 मार्च को मतदान होना है. परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की उम्मीदवारी से यह चुनाव राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो गया है. वे कई बार से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं. इस बार भी वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके साथ एनडीए के सभी दल हैं. लेकिन गया की दोनों सीटों के साथ-साथ कोशी शिक्षक और सारण स्नातक क्षेत्र के अन्य किसी भी प्रत्याशी का ऐसा सौभाग्य नहीं है. गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह का मुकाबला पहले तो राजद के डॉ. पुनीत सिंह से होना था, लेकिन अब कांग्रेस के अजय कुमार सिंह की चुनौती भी उन्हें मिलेगी. गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, तो निवर्तमान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने पिछला चुनाव निर्दलीय जीता था, लेकिन कुछ महीने पहले वे रालोसपा में शामिल हो गए. इस लिहाज से यह सीट रालोसपा के खाते में गई. वहीं, लोजपा पिछले चुनाव में यहां दूसरे नंबर पर रही थी, इसलिए वह चाहती है कि उसे यहां से उम्मीदवारी मिले. रालोसपा की दावेदारी के बाद लोजपा ने एनडीए के शीर्ष नेताओं से आपत्ति दर्ज करवा दी. मामले ने तूल पकड़ा, तो रालोसपा सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान से दिल्ली में बातचीत भी की. शुरू में तो सकारात्मक परिणाम की खबर आई. लेकिन फिर क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला. इसके बाद लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के हितों की अनदेखी की बात करते हुए गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी. प्रो. डीएन सिन्हा ने नामजदगी का पर्चा दाखिल भी कर दिया. लोजपा की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाने के बाद दोनों दलों रालोसपा और लोजपा के बीच किसी बातचीत की कोई खबर नहीं है. इधर सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है और वे दोनों दलों के नेताओं के निरंतर संपर्क में हैं. खबर है कि इस समस्या के समाधान के लिए एनडीए के चौथे घटक हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी पहल कर रहे हैं. यह देखने वाली बात होगी कि लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान व उनके अनुज पशुपति कुमार पारस पर जीतन राम मांझी कितना असर डाल पाते हैं. इधर सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मांझी की पार्टी के नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह अपना भाग्य आजमा रहे हैं. महाचंद्र प्रसाद सिंह हालांकि परिषद चुनाव के चतुर पहलवान हैं, लेकिन चुनाव तो आखिर चुनाव ही है! दोनों गठबंधनों के बड़े भाइयों ने भी यह कहना आरंभ कर दिया है कि परिषद चुनाव से सत्ता की राजनीतिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता. इसमें दो राय नहीं कि विधान परिषद के चुनाव आम निर्वाचन के राजनीतिक तत्वों के वाहक नहीं होते, लेकिन सीमित दायरे में ही सही, ये उम्मीदवारों और घोषित दलों की तात्कालिक सामाजिक स्वीकृति को तो अभिव्यक्त करते ही हैं.

अवधेश कुमार सिंह

संजीव श्याम सिंह

कांग्रेस को लगता है कि महागठबंधन के दोनों भाइयों, बड़े भाई लालू प्रसाद और छोटे भाई नीतीश कुमार ने उसकी अनदेखी की है. कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के नेताओं को बताना चाहती है कि इस चुनाव से उसके भी हित जुड़े हुए हैं. गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के अजय कुमार सिंह बराबर चुनाव लड़ते रहे हैं, जीते भी हैं. अवधेश नारायण सिंह को अजय कुमार सिंह कड़ी टक्कर देते रहे हैं. इसके बावजूद कांग्रेस के दावे को दरकिनार करते हुए इस सीट को राजद के खाते में डाल दिया गया. लालू प्रसाद और उनकी पत्नी व पुत्रों के रुख ने कांग्रेस को और उत्तेजित कर दिया. कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जब अवधेश नारायण सिंह के खिलाफ उम्मीदवार देने में अनिच्छा जाहिर की, तो राजद ने झटपट अपनी पार्टी के दिग्गज नेता जगदानंद सिंह के पुत्र डॉ. पुनीत सिंह को गठबंधन प्रत्याशी घोषित कर दिया. कांग्रेस ने जब इस सीट पर अपना दावा किया, तो राजद ने रुख कड़ा कर लिया. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सूबे के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान से बातचीत की और फिर दोनों सीटों से अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी. गया स्नातक क्षेत्र से अजय कुमार सिंह और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हृदय नारायण सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है. अब देखना है कि कांग्रेस का ये कदम किस हद तक राजद को परेशान करता है. इन सबसे नीतीश कुमार के लिए धर्मसंकट की स्थिति बन गई है. अब देखना यह है कि वे और उनका जद(यू) राजद को समर्थन देता है या कांग्रेस को. यह भी हो सकता है कि जद(यू) मौन साध ले.

देखा जाय तो सूबे में दोनों गठबंधनों, सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी एनडीए के नेतृत्व ने गठबंधन धर्म को तरजीह नहीं दी. लगता है कि दोनों गठबंधनों के बड़े दलों ने अपने-अपने जूनियरों पर फैसले थोप दिए हैं. महागठबंधन में कांग्रेस और एनडीए में लोजपा की शिकायत रही है कि गठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर कभी कोई बैठक नहीं हुई और उनकी राय नहीं ली गई. हालांकि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इसे स्वीकार नहीं करती. इधर महागठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी राजद ने कह दिया कि मुख्यमंत्री की राय से ही सब कुछ तय किया गया है. अर्थात, महागठबंधन में कांग्रेस से पूछने की कोई जरूरत नहीं समझी गई. जद(यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनका दल कांग्रेस के प्रश्नों का जवाब देने के बदले खामोश रहना बेहतर समझता है. राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने साफ कर दिया है कि आगे गुंजाइश होने पर कांग्रेस के बारे में विचार किया जाएगा. अभी तो चार सीटें थी और हमने फिफ्टी-फिफ्टी बांट लिया. इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस चुनाव लड़ने चिंता छोड़े और राजद के दोनों प्रत्याशियों की जीत के लिए मेहनत करे.

ऐसे तो गठबंधन के छोटे दलों के प्रति नेतृत्वकारी दलों के राजनीतिक आचरण विधानसभा चुनावों के बाद से ही सवालों के घेरे में हैं, लेकिन विधान परिषद चुनावों ने तल्खी को और उजागर कर दिया है. दोनों गठबंधनों में से किसी ने भी आंतरिक मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी समिति के गठन की जरूरत नहीं समझी. पूछने पर उनका जवाब होता है कि इसकी क्या जरूरत है. हालांकि यह भी तय है कि संवादहीनता से किसी का लाभ नहीं होगा ना लालू का, ना नीतीश का और ना ही भाजपा का.■

feedback@chauthiduniya.com

खौफ़नाक राह पर घाटी

हारून रेशी

चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि कश्मीर में मिलिटेंटों को प्राप्त जनसमर्थन के कारण सेना को जान-माल का नुक़सान उठाना पड़ता है. दरअसल, उनका यह बयान दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में 12 फरवरी को मिलिटेंटों और सेना के बीच हुए मुठभेड़ के बाद आया है. 10 घंटे की इस मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों ने पकड़े गए मिलिटेंटों को छुड़ाने की कोशिश की थी. सैंकड़ों स्थानीय युवाओं ने मिलिटेंटों के विरूद्ध जारी ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए सेना पर पथराव किया था. पथराव करने वाले नौजवान, सेना के चंगुल में फंसे मिलिटेंटों को बचाने की कोशिश कर रहे थे. इस झड़प में चार मिलिटेंट, दो सैनिक और दो आम नागरिक मारे गए. मारे गए लोगों में शामिल इस्हाक़ अहमद रेशी के परिजनों ने आरोप लगाया कि सेना ने अपनी हिरासत में ही उसका क़त्ल कर दिया था. एनकाउंटर ख़त्म होने के बाद हज़ारों लोगों ने मारे गए लड़ाकों और स्थानीय लोगों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया. नमाज-ए-जनाज़ा के मौके पर लोगों ने भारत विरोधी और आज़ादी के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाज़ी की.

इस मुठभेड़ के दो दिन बाद ही 14 फरवरी को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में मिलिटेंटों के साथ सेना के एक झड़प में मिलिटेंटों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सेना पर पथराव किया. इस मुठभेड़ में चार सैनिक और एक मिलिटेंट मारे गए. मिलिटेंटों के मारे जाने पर स्थानीय लोगों ने तीन दिनों तक शोक हड़ताल की. ये कश्मीर की वो स्थिति है, जिसके परिदृश्य में देश के सैन्य प्रमुख ने उपरोक्त असाधारण बयान दिया. जनरल रावत ने कश्मीरियों को चेतावनी दी कि आगे से अगर सैन्य ऑपरेशन में लोगों ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की, तो उन्हें (जनता को) आतंकवादियों का समर्थक माना जाएगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी.

बीते 28 वर्षों के मिलिटेंट आंदोलन में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सैन्य प्रमुख ने खुले शब्दों में मिलिटेंटों को जनसमर्थन प्राप्त होने की बात कही है. उनके इस बयान का लोगों ने विरोध किया है. अलगाववादी नेताओं का कहना है कि सेना प्रमुख के बयान में यह धमकी है कि अगर आप आगे आएंगे, तो आपको मारा जाएगा. वहीं कुछ लोग सेना प्रमुख के बयान को 'तथ्यों की स्वीकारोक्ति' बता रहे हैं. मानवाधिकार के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ख़ुर्रम परवेज़ का कहना है कि 28 वर्षों तक भारत यह दावा करता रहा है कि कश्मीर में पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर जारी है और अब भारतीय सेना प्रमुख के बयान ने पाकिस्तान के इस रुख़ को सही साबित किया है कि कश्मीर की मिलिटेंसी को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त है. युवा पत्रकार गौहर गिलानी ने भी इस विषय पर समान विचार प्रकट करते हुए फेसबुक पर लिखा है, मिस्टर रावत की इस स्वीकारोक्ति कि जनता सेना का समर्थन नहीं करती है, से साफ़ ज़ाहिर होता है कि कश्मीरियों का आंदोलन स्थानीय है और पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है. आम लोगों में मिलिटेंटों के प्रति नरम रुख़ और मिलिटेंट गतिविधियों के बढ़ते हुए ग्राफ़ से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां परेशान हैं. आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के आरंभिक 45 दिन यानी 15 फरवरी तक घाटी में सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में 19 मिलिटेंट और 6 सेना के जवान मारे गए हैं. मारे जाने वाले मिलिटेंटों में से 10 कश्मीरी थे और 6 विदेशी, जबकि बाक़ी 3 की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि पिछले वर्ष 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिद्दीन के मशहूर कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शनों से कश्मीरी युवाओं में मिलिटेंसी से लगाव पैदा हो गया. पुलिस आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2016 के बाद से अब तक 100 स्थानीय युवा मिलिटेंसी में शामिल हुए हैं. पिछले वर्ष सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में 56 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें से अधिकतर हिजबुल मुजाहिद्दीन के लड़ाके थे. कश्मीर घाटी के हालात व घटनाओं का जायज़ा लेने से साफ़ पता चलता है कि यहां न केवल भारत विरोधी आंदोलन के प्रति जनता की सहानुभूति बढ़ती जा रही है, बल्कि अलगाववादी नेताओं की लोकप्रियता में भी इज़ाफ़ा हो रहा है. हुर्रियत नेताओं ने 9 और 11 फरवरी को अफ़ज़ल गुरु और मोहम्मद मक़बूल बट्ट की बरसियों पर हड़ताल की अपील की थी, जिस पर घाटी में लोगों ने कड़ाई से अमल किया. हुर्रियत ने जनता से अपील की थी कि 10 फरवरी को वे श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य विश्लेषकों के कार्यालय तक मार्च करें, ताकि वहां अफ़ज़ल गुरु और मक़बूल बट्ट के शवों को भारत से वापस दिलाने की मांग का ज्ञापन सौंपा जा सके. उल्लेखनीय है कि मक़बूल को गद्दारी के आरोप में 11 फरवरी 1984 को और अफ़ज़ल गुरु को संसद हमले की साज़िश में संलिप्त होने के आरोप में 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी. फांसी के बाद दोनों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को नहीं लौटाए गए और तिहाड़ जेल परिसर में ही दफ़ना दिया गया. उनके शवों की वापसी की मांग कश्मीर में समय-समय पर होती रही है. संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय तक प्रस्तावित उस मार्च को रोकने के लिए अधिकारियों को श्रीनगर में कर्फ़्यू लगाना पड़ा. कई अलगाववादियों को गिरफ़्तार किया गया और कई को उनके घरों में नज़रबंद रखा गया.

पथराव को रोकने के लिए हाल ही में घाटी के कई ज़िलों में सुरक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किया कि स्थानीय लोग मुठभेड़ स्थल से तीन किलोमीटर के दायरे में जमा न हों. सेना के द्वारा पकड़े गए मिलिटेंटों को छुड़ाने और सैन्य ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए सैनिकों पर पथराव का यह सिलसिला पिछले वर्ष फरवरी में शुरू हुआ, जब श्रीनगर के पानपुर में एक इमारत में फंसे मिलिटेंटों और सैनिकों के बीच लगातार 48 घंटे तक मुठभेड़ हुई. एक ओर सेना मिलिटेंटों वाली उस इमारत को ध्वस्त करने के लिए मार्टर बमों और रॉकेटों से हमले कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर दर्जनों युवा हाथों में पत्थर लिए सेना पर हमले के मूड में डटे हुए थे. मरने वाले मिलिटेंटों के अंतिम संस्कार में हज़ारों की संख्या में आम लोगों के शिरकत की परंपरा भी पिछले वर्ष ही शुरू हुई. जनता का यह व्यवहार इस बात का जीता जागता सबूत है कि कश्मीर में मिलिटेंसी को जनसमर्थन प्राप्त है. अब सवाल पैदा होता है कि कश्मीर में मिलिटेंटों को लोगों का समर्थन क्यों मिल रहा है? राजनीतिक विश्लेषक ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ इस बारे में कहते हैं कि जनता का यह व्यवहार दिखा रहा है कि उनके अन्दर गुस्सा और नफरत भरा हुआ है. इसकी बुनियादी वजह जनता पर लगातार ढाए जा रहे जुल्म हैं. कश्मीर का समाधान बल प्रयोग नहीं हो सकता. मैं समझता हूं कि जनता को जितना अधिक कुचलने की कोशिश की जाएगी, लोग उतना ही बिफर जाएंगे. नई दिल्ली अगर स्थिति को बदलना चाहती है, तो उसे सबसे पहले बल प्रयोग बंद करना होगा और जनता की जायज़ मांगों को मानते हुए मसले का राजनीतिक हल तलाशने के लिए गंभीर क़दम उठाने होंगे. यही एक रास्ता है. ज़रीफ़ का मानना है कि कश्मीरी जनता एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की चपेट में आ चुकी है. एक ओर उनके दिलों से डर ख़त्म हो गया है और दूसरी ओर उन्होंने 'करो या मरो' का इरादा बना लिया है. ऐसी स्थिति में नई दिल्ली के पास एकमात्र रास्ता यही है कि वे ईमानदारी के साथ कश्मीर समस्या को अंतिम रूप से हल करने के लिए राजनीतिक अमल शुरू करें, वरना यहां हालात बद से बदतर हो जाएंगे. भविष्य में हालात कैसा रुख़ अख्तियार करते हैं, इसके बारे में विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह सच्चाई है कि हर गुज़रने वाले दिन के साथ नई दिल्ली कश्मीर में जनता का समर्थन खो रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार की बेशर्मी और बेहयाई से लोग नग्न होने पर मजबूर

इस कहानी को पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ तस्वीर देखिए. एक-एक तस्वीर हजार शब्दों की कहानी को खुद में समेटे हुए है. इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर आपकी आत्मा आपको नहीं झकझोरती, तो दो मिनट के लिए रुकिए. इसकी जांच कीजिए कि आपका ज़मीर अभी जिन्दा है भी या नहीं. ये तस्वीरें हमारे समाज का ही एक सच हैं. हमारे लिए एक चेतावनी भी. हम आज न चेते, तो ये सिस्टम कल हमें भी नग्न होने पर मजबूर कर सकता है. अपने साथ हुए अन्याय के ख़िलाफ आख़िर हम कर भी क्या सकते हैं? सीएम, पीएम, डीएम से शिकायत कर सकते हैं. गुहार लगा सकते हैं. देश की अदालत स्वत: संज्ञान ले सकती है. लेकिन फिर भी न्याय न मिले, हक न मिले, तो फिर क्या करेंगे? बन्दूक उठाएंगे तो नक्सली कहलाएंगे. कानून की नज़र में कसूरवार ठहराए जाएंगे. तो फिर रास्ता क्या बचता है? झारखंड के घटवार आदिवासियों ने खुद को नग्न कर विरोध जताने का तरीका शायद इसीलिए चुना कि कम से कम इससे भी उनकी आंखों से कुछ तो शर्म टपके, जिनकी बेशर्मी और बेहयाई ने इनकी जिन्दगी को जीते-जी खत्म कर दिया है. पढ़िए, चौथी दुनिया की खास रिपोर्ट:

शशि शेखर

अपनी जमीन से उजड़ने का दर्द क्या होता है, ये देखना और महसूस करना हो तो एक बार झारखंड के धनबाद चले जाइए. सिर्फ झारखंड ही क्यों, आप इसके साथ ही जामतारा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और वर्द्धमान जिले के करीब 250 गांवों के हजारों विस्थापित परिवारों से भी मिल आइए, जो 50 साल बाद भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि अब उन्होंने खुद को नंगा कर लिया है, ताकि सरकार और दामोदर घाटी कॉरपोरेशन (डीवीसी) के अधिकारियों की आंखों में शर्म आए. लेकिन उनकी आंखों में शर्म बची ही होती, तो फिर इन गरीब आदिवासियों को खुद को नंगा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अगर उनकी आंखों में शर्म होती, तो अपने पूर्वजों की जमीन से उजड़ने के 50 साल बाद भी इन गरीबों को दर-दर की ठोकरे क्यों खानी पड़ती? केन्द्र से ले कर झारखंड तक में सबका साथ-सबका विकास की बात करने वाली सरकार अभी सत्ता में है. फिर भी, इनको शर्म नहीं आती.

सवाल सिर्फ एक सरकार का भी नहीं है. दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय हुई थी. तब ऐसे प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था. आखिर ये कैसा मंदिर था, जिसने अपने ही लोगों को अपनी ही जमीन से उजाड़ दिया और आज 50 साल बाद नंगा होने पर मजबूर कर दिया? आजादी के बाद 1953 में दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई. सिंचाई के साधन बढ़ाने और बिजली परियोजना के लिए इस परियोजना को लाया गया था. जनहित के लिए लाई जा रही इस परियोजना के लिए झारखण्ड के धनबाद, जामतारा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और वर्धमान जिलों के लगभग 41 हज़ार एकड़ ज़मीन के साथ ही चार हजार से ज्यादा घरों का अधिग्रहण किया गया. इतने बड़े पैमाने पर हुए अधिग्रहण से करीब 70 हज़ार लोग प्रभावित हुए. ये लोग अपनी जमीन से उजड़ गए. जिन लोगों की जमीन इस परियोजना के लिए ली गई, आज उनकी तीसरी पीढ़ी न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रही है.

परियोजना के लिए ली गई जमीन के बदले इन लोगों को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की तरफ से मुआवजा और नौकरी मिलनी थी. जाहिर है, ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से विस्थापित परिवारों की तीसरी पीढ़ी आज नौकरी और न्याय पाने के लिए जंग लड़ रही है. मुआवजे के नाम पर दामोदर घाटी कॉरपोरेशन ने साल 1976 तक महज 350 लोगों को जमीन के साथ-साथ नौकरी दी. कुछ परिवारों को मुआवजा मिला. लेकिन नियम के मुताबिक हर परिवार को जमीन के साथ-साथ मुआवजा और एक सदस्य को रोजगार मिलना चाहिए था. जिन परिवारों को आज तक रोजगार नहीं मिला, उनमें से अधिकतर घटवार आदिवासी समुदाय से आते हैं. ऐसा ही एक परिवार है, कन्हाई मांझी का.

धनबाद-डीवीसी डैम विस्थापित

क्या है इनकी मांग

1. दामोदर घाटी परियोजना से विस्थापित सभी परिवारों को ज़मीन के बदले ज़मीन और नौकरी दी जाए.
2. भूमिहीन और आश्रित परिवारों को भी नौकरी और आजीविका मुहैया कराई जाए.
3. दामोदर घाटी कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा नौकरी के लिए पैनल बनाया जाना असंवैधानिक है, इसमें सभी विस्थापित परिवार शामिल नहीं हैं.
4. जिन फर्जी विस्थापितों को नौकरी दी गई है, उन्हें नौकरी से निकाला जाए और इसके लिए दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ कार्रवाई की जाए.
5. नौकरी का अधिकार विस्थापित परिवारों की अगली पीढ़ी का भी है.
6. भू-अधिग्रहण और पुनर्वास कानून 2011 के तहत सभी विस्थापितों को न्याय मिले.

> भ्रष्ट अधिकारी पुनर्वास के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे हैं. क्या कारण है कि डीवीसी ने आज तक उन फर्जी विस्थापितों का कोई विवरण नहीं दिया है, जिन्हें विस्थापित बता कर नौकरी और मुआवजा दिया गया. सरकारें आती रहीं, जाती रहीं पर घटवार आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो पाया.
>
> **-रामाश्रय सिंह,**
> *घटवार आदिवासी महासभा*

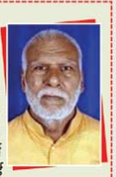

कन्हाई मांझी की 46 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई थी. आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला.

यहां एक और पेंच है. डीवीसी पर ये आरोप है कि इसने नौकरी देने के नाम पर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है. चौथी दुनिया से बात करते हुए घटवार आदिवासी महासभा के रामाश्रय सिंह बताते हैं कि डीवीसी ने विस्थापितों के साथ अन्याय तो किया ही, लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा ये किया कि इसने हजारों (वे ये संख्या 9 हजार बताते हैं) अन्य लोगों को फर्जी विस्थापित बता कर नौकरी दे दी और जो नौकरी के असली हकदार हैं, वास्तव में जिनकी जमीन इस परियोजना में गई है, उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली है. ये हालत सैकड़ों परिवारों की है. रामाश्रय सिंह बताते हैं कि नौकरी और मुआवजे के नाम पर अब तक कई घोटाले किए जा चुके हैं. वे कहते हैं कि गैर विस्थापित लोगों ने नौकरियां और ज़मीन हासिल कर ली. रामाश्रय सिंह के मुताबिक, अवैध तरीके से नौकरी पाए 11 लोगों को बर्खास्त करने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है.

विस्थापित लोगों ने अपने हक के लिए साल 2006 में घटवार आदिवासी महासभा का गठन किया और इसके बैनर तले आंदोलन शुरू किया. इन लोगों ने भूख हड़ताल और सत्याग्रह भी किए. जामताड़ा जिला मुख्यालय के सामने कई बार आन्दोलन किए. मैथन बांध से प्रभावित लोगों ने भी आधा दर्जन बार भूख हड़ताल किया. साल 2010 में तकरीबन 20 हजार लोगों ने रैली निकाली. पंचेत बांध के लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे. गिरिडीह में रेल चक्का जाम किया. साल 2010 में पुरुलिया जिले की परियोजना से प्रभावित लोगों ने होली के दिन भूख हड़ताल किया. यानी, पिछले 10 सालों से ये लोग अपने अधिकार को पाने के लिए सतत संघर्ष करते आ रहे है. जो भी तरीका इन्हें सही लगा उसे अपनाया, लेकिन हर विरोध के बाद इन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी.

कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र

घटवार आदिवासी महासभा की अगुआई रामाश्रय सिंह कर रहे हैं. वे इस मामले को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंची, तो ये खुलासा हुआ कि विस्थापित आदिवासियों को धोखा दे कर अन्य दूसरे लोगों को नौकरी दे दी गई है. पिछले तीन साल के दौरान केन्द्र और झारखंड में भाजपा की सरकार है. घटवार आदिवासियों को उम्मीद थी कि नई सरकार से उन्हें न्याय मिलेगा. लेकिन इन सरकारों ने अब तक उनके लिए भी कुछ नहीं किया है. दामोदर घाटी परियोजना केन्द्र सरकार के अधीन है. पावर मिनिस्ट्री इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है. रामाश्रय सिंह ने प्रधानमंत्री को कई खत लिखे और इस मामले की जानकारी देते हुए सीबीआई जांच की मांग की. लेकिन हर बार, तकरीबन 18 बार प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से झारखंड के मुख्य सचिव और ऊर्जा मंत्रालय को इस जवाब का पत्र भेजा गया कि कार्रवाई के लिए पत्र को अग्रसरित कर दिया गया है. उसके बाद न तो झारखंड के मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री और न ही केंद्रीय ऊर्जा विभाग की तरफ से उस आदेश पर कोई कार्रवाई की जाती है. दूसरे शब्दों में कहें, तो इन अधिकारियों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र का भी कोई महत्व नहीं है. ये कहानी प्रधानमंत्री कार्यालय की महत्ता को भी दिखाती है. रामाश्रय सिंह बताते हैं, 'निगम के भ्रष्ट अधिकारी पुनर्वास के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे हैं. क्या कारण है कि डीवीसी ने आज तक उन फर्जी विस्थापितों का कोई विवरण नहीं दिया है, जिन्हें विस्थापित बता कर नौकरी और मुआवजा दिया गया. सरकारें आती रहीं, जाती रहीं पर घटवार आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो पाया.' मुआवजे की बाट जोहते-जोहते तीसरी पीढ़ी आ चुकी है. लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इन गरीबों के दिल और दिमाग से संघर्ष का जज्बा अभी तक खत्म नहीं हुआ है. वे लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ने को तैयार हैं.

बहरहाल, सालों से चली आ रही लंबी लड़ाई के बाद घटवार आदिवासियों ने अंत में विरोध का एक ऐसा तरीका चुना, जिसे देख तो क्या, सुन कर भी इंसानियत शर्मसार हो जाए. साल 2016 के अंत में विस्थापित परिवारों ने नग्न हो कर धनबाद में प्रदर्शन करने का फैसला लिया. मर्द और औरतों ने अपने कपड़े उतार कर सरकार से इंसाफ की मांग की. लेकिन सरकार तो सरकार, मुख्यधारा की कथित राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी ये कोई खबर नहीं थी. शायद कथित राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे अपने ही समाज की एक नग्न तस्वीर को सत्ता और हुक्मरानों तक पहुंचा सकें. दिल्ली को धनबाद में नग्न हुए लोग नहीं दिखे. रांची में बैठे सत्ताधीश भी इस बदरंग तस्वीर को देख पाने की हिम्मत नहीं जुटा सके. अगर ये तस्वीर दिल्ली और रांची के सत्ताधीशों की नजर से गुजरी होती, तो शायद वे भी एक बार सोचने को मजबूर होते. ये भी हो सकता है कि दम तोड़ती इंसानियत के इस दौर में इन लोगों ने इस तस्वीर को देख कर भी अनदेखा कर दिया हो. यही हुआ होगा. वरना एक अदद नौकरी और मुआवजे के लिए एक नग्न तस्वीर को सत्ता और हुक्मरानों तक पहुंचा सकें. दिल्ली को धनबाद में नग्न हुए लोग नहीं दिखे. रांची में बैठे सत्ताधीश भी इस बदरंग तस्वीर को देख पाने की हिम्मत नहीं जुटा सके. अगर ये तस्वीर दिल्ली और रांची के सत्ताधीशों की नजर से गुजरी होती, तो शायद वे भी एक बार सोचने को मजबूर होते. ये भी हो सकता है कि दम तोड़ती इंसानियत के इस दौर में इन लोगों ने इस तस्वीर को देख कर भी अनदेखा कर दिया हो. यही हुआ होगा. वरना एक अदद नौकरी और मुआवजे के लिए एक इंसान किसी इंसान को नंगा होने पर मजबूर तो नहीं ही कर सकता. खैर, घटवार समाज ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है. धनबाद के बाद उनका अगला ठिकाना दिल्ली ही है, जहां ये आदिवासी एक बार फिर नंगे बदन प्रदर्शन करने को तैयार हैं, अगर सरकारों की बेहयाई और बेशर्मी का पर्दा उनकी आंखों के आगे से जल्द नहीं हटा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जश्न-ए-रेख्ता 2017 उर्दू के जादू का जश्न

हमें ख़ुशी है कि हमारी कोशिशों को क़ुबूलियत हासिल हुई. ख़ास तौर पर नए ख्वाब देखने वाले उन नौजवानों के लिए, जो उर्दू पढ़ना-लिखना न जानने के बावजूद उर्दू के ज़ुल्फ़ों के असीर हैं. आज 2017 में यह हाल है कि हमने तो जश्न का सिर्फ इन्तेज़ाम किया, इसे सेलिब्रेट यही लोग कर रहे हैं, जिनके दिलों में उनके माशूक़ के सिवा कोई और है, तो वो है उर्दू ज़ुबान का इश्क़. इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू ज़ुबान का दामन दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है. नई नस्ल इस ज़ुबान से दूर होती जा रही है. लेकिन यह भी सच है कि नई नस्ल में इस ज़ुबान को सीखने की पूरी इच्छा है. इस इच्छा का अंदाज़ा जश्न में शामिल नौजवानों की बड़ी तादाद से भी हो सकता है.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

शफ़ीक़ आलम

रेख्ता फाउंडेशन ने हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली दिल्ली के दिल में स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट (आईजीएनसीए) के प्रांगण में एक बार फिर जश्न-ए-रेख्ता की शानदार महफ़िल सजाई और उर्दू के आशिकों को उर्दू तहज़ीब के अलग-अलग रंगों से एक बार फिर अवगत कराया. 17 फरवरी से 19 फरवरी तक चले इस तीन दिवसीय जश्न की कामयाबी इस बात की दलील है कि रेख्ता फाउंडेशन के संस्थापक संजीव सराफ ने चंद साल पहले जो एक पौधा लगाया था, वो अब तनावर दरख्त का रूप लेकर फल देने को तैयार हो गया है. इस बात का एतराफ किसी और ने नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर शायर, साहित्यकार और फ़िल्मकार गुलज़ार ने की. उन्होंने कहा कि मीर और ख़ुसरो के बाद रेख्ता (यानि उर्दू) के लिए किसी का शुक्रिया अदा करना हो, तो मुझे संजीव सराफ साहब का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा. उर्दू की रवायत (परम्परा) को तसलसुल देना और यहां तक क़ायम रखना और उसके लिए मेहनत करना बड़ी बात है. इस साल जश्न-ए-रेख्ता की एक ख़ास बात यह रही कि इसके सारे प्रोग्राम रेख्ता डॉट ऑर्ग पर लाइव स्ट्रीम किए गए, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौजूद रेख्ता डॉट ऑर्ग के दर्शकों और पाठकों ने इस जश्न का ग़ायबाना लुत्फ़ उठाया.

ताकि उर्दू लिपि ज़िन्दा रहे...

जश्न-ए-रेख्ता का आगाज़ रेख्ता फाउंडेशन के संस्थापक संजीव सराफ और गुलज़ार के साथ सुप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने शमा रौशन करके किया. इस अवसर पर रेख्ता डॉट ऑर्ग पर उर्दू लिपि सिखाने वाले प्रोग्राम अमोज़िश का लोकार्पण भी किया गया. इस बात में कोई शक नहीं कि उर्दू की ख़ूबसूरती और सौन्दर्य का दारोमदार बहुत हद तक इसकी लिपि में भी निहित है. ज़ुबान तो सब बोलते हैं, लेकिन अगर लिपि समाप्त हो गई, तो फिर उसके साथ उसकी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी. इसी बात की तरफ इशारा करते हुए गुलज़ार ने कहा कि 80 से 90 फीसद फिल्मो में जो ज़ुबान बोली जाती है वो उर्दू है. ज़िंदा ज़ुबान वक़्त से साथ-साथ बदलती रहती है. अब हम 19वीं सदी या 18वीं सदी की उर्दू नहीं बोलते हैं, बल्कि आज की उर्दू बोलते हैं. लेकिन एक चीज़ जिसकी कमी महसूस हो रही है, वो इसकी लिपि है. उर्दू लिपि कहीं सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है, उसे संभालना बहुत ज़रूरी है. उर्दू की लिपि बहुत ख़ूबसूरत है. मेरी यही ख्वाहिश है कि उर्दू लिपि ज़िंदा रहे. रेख्ता डॉट ऑर्ग की पेशकश अमोज़िश का ज़िक्र करते हुए और पांच साल पहले ख़ुद उर्दू लिपि सीखने की वजह बताते हुए संजीव सराफ का कहना था, हम जानते हैं कि ज़ुबान को उसके रस्मुलख़त (लिपि) से अलग करना जिस्म को रूह से अलग करना है. उनका यह भी कहना था कि ज़ुबान की ख़ूबसूरती और उसकी मौसिक़ी (संगीत) को पूरी तरह समझने के लिए लिपि का जानना ज़रूरी है. रेख्ता पर अमोज़िश की शुरुआत की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, जो उर्दू लिपि सीखना चाहते हैं, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाते.

जश्न-ए-रेख्ता क्यों?

जश्न-ए-रेख्ता मनाने का मक़सद ज़ाहिर करते हुए संजीव सराफ ने कहा कि जश्न-ए-रेख्ता-2015 मुख्तलिफ क़ौमों, मज़ाहिब और तबक़ों के लोगों को जोड़ने और दिलों के दरमियां मोहब्बत का पुल बनाने के अमल के लिए बरपा किया गया था. हमें ख़ुशी है कि हमारी कोशिशों को क़ुबूलियत हासिल हुई. ख़ास तौर पर नए ख्वाब देखने वाले उन नौजवानों के लिए, जो उर्दू पढ़ना-लिखना न जानने के बावजूद उर्दू की ज़ुल्फों के असीर हैं और आज 2017 में यह हाल है कि हमने तो जश्न का सिर्फ इन्तेज़ाम किया. इसे सेलिब्रेट यही लोग कर रहे हैं, जिनके दिलों में उनके माशूक़ के सिवा कोई और है, तो वो है उर्दू ज़ुबान का इश्क़. इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू ज़ुबान का दामन दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है. नई नस्ल इस ज़ुबान से दूर होती जा रही है. लेकिन यह भी सच है कि नई नस्ल में इस ज़ुबान को सीखने की पूरी इच्छा है. इस इच्छा का अंदाज़ा जश्न में शामिल नौजवानों की बड़ी तादाद से भी हो सकता है.

रेख्ता डॉट ऑर्ग

हालांकि जश्न-ए-रेख्ता मनाने के संदर्भ में जो बातें संजीव सराफ ने कहीं, वो बिलकुल दुरुस्त हैं, लेकिन इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रेख्ता फाउंडेशन की कामयाबी, ख़ास तौर पर रेख्ता डॉट ऑर्ग की कामयाबी. रेख्ता ने एक ऐसी शुरुआत की, जिसे उर्दू के नाम पर चलने वाली किसी बड़ी सरकारी संस्था या यूनिवर्सिटी को करना चाहिए था. बहरहाल, रेख्ता डॉट ऑर्ग की कामयाबी का सफ़र लगातार जारी है. इसकी सामग्री में दिन प्रतिदिन इजाफ़ा होता जा रहा है. पिछले साल इस वेबसाईट पर शायरों की तादाद 1,700 थी, जो अब बढ़कर 2,300 हो गई है. नज्मो, ग़ज़लों, ऑडियो और विडियो की तादाद में भी लगातार इज़ाफा हुआ है. इ-बुक सेक्शन में अब किताबों की संख्या 23,000 से ऊपर पहुंच गई है. सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े ज़खीरे से फायदा उठाने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है. उर्दू लिपि नहीं जानने वाले लोगों के लिए उर्दू के साथ-साथ रोमन और देवनागरी लिपि में ग़ज़लों और नज्मों का एहतमाम किया गया है. इस वेबसाइट की एक ख़ास बात यह भी है कि उर्दू के मुश्किल शब्दों का अर्थ महज़ एक क्लिक में मालूम हो जाता है. बहरहाल, इस वेबसाइट पर वे नादिर और दुर्लभ किताबें भी दस्तयाब हैं, जो वर्षों पहले आउट ऑफ़ प्रिंट हो चुकी थीं. उर्दू में शोध करने वाले शोधकर्ताओं के लिए भी यह बड़ी लाइब्रेरी की तरह है. रेख्ता ने प्रकाशन की दुनिया में भी अपना क़दम रखा है और उर्दू शायरी के तीन संग्रह प्रकाशित किया है.

संजीव सराफ ने अपने संबोधन में, इस जश्न में शामिल सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और पिछले एक वर्ष के दौरान दुनिया से रुख़सत हो चुके उर्दू अदीबों और शायरों, जिनमें बानो कुदसिया, सलमा सिद्दीक़ी, पैग़म अफ़ाक़ी, बेकल उत्साही के नाम शामिल थे, को ख़िराज-ए-अक़ीदत पेश किया. पहले दिन की महफ़िल का समापन संगीत की महफ़िल रंग-ए-मौसिक़ी से हुआ, जिसमें आमान अली बंगश और अयान अली बंगश ने अपने सरोद वादन से माहौल को संगीतमय कर दिया.

जश्न-ए-रेख्ता के दूसरे दिन के प्रोग्रामों में भी उर्दू का जादू सर चढ़ के बोला. दीवान-ए-आम, दीवान-ए-ख़ास, बज़्म-ए-रवां और कुंजे सुख़न के सभी प्रोग्रामों में भरपूर जोश-ओ-ख़रोश देखने को मिला. सूरतगर ख़्वाबो के प्रोग्राम में मशहूर फिल्म लेखक जावेद सिद्दीक़ी ने गुलज़ार से बातचीत की, जिसमें गुलज़ार ने उर्दू के आवामी रंग पर भरपूर रौशनी डाली. 'थिएटर के भोले रंग' शीर्षक से उर्दू ड्रामों पर बहस हुई साथ ही नज़ीर अकबराबादी और आगरा बाज़ार पर ड्रामा पेश किया गया. इस प्रोग्राम में नादिरा बब्बर, सलीम आरिफ़ और सौरभ शुक्ला आदि ने भी शिरकत की. प्रेमचंद की लेखनी पर अब्दुल बिस्मिल्लाह, अली अहमद फ़ातमी, आलोक राय, मैनेजर पाण्डेय और तारिक़ छत्तारी ने शिरकत की. 'दिल्ली जो एक शहर था' शीर्षक से मशहूर इतिहासकार इरफ़ान हबीब ने दिल्ली की तारीख़ के साथ-साथ उर्दू की भी तारीख़ पर भी रौशनी डाली. इसके अलावा कई दूसरे प्रोग्राम हुए, मज़ाहिया शायरी की मजलिस सजी, बच्चों ने अपने प्रोग्राम पेश किए, किताबों का एक छोटा से मेला भी लगा. दीवान-ए-ज़ायक़ा में लोगों ने अलग-अलग पकवानों का भी लुत्फ़ लिया. इसके अलावा मुशायरा का एहतमाम किया गया, मौसिक़ी की मजलिस भी सजी, और फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई.

जश्न-ए-रेख्ता का एक मक़सद उर्दू और हिंदी को करीब लाना भी है. लिहाज़ा साहित्य से संबंधित अलग-अलग विषयों की चर्चा में उर्दू शायरों, अदीबों के साथ-साथ हिंदी से जुड़े लोग भी शामिल हुए. तीसरे दिन के प्रोग्राम की शुरुआत फ़रीदून शहरयार और हिंदी कवि और गीतकार प्रसून जोशी की गुफ्तगू से हुई. हिंदी कवि और राजनेता कुमार विश्वास ने विशेष रूप से उर्दू शायर जॉन एलिया को याद किया. दारैन शाहीदी और पूनम गिरधानी ने अपनी दास्तान-गोई से सबको मन्त्र मुग्ध कर दिया. 'उर्दू सुरों का बहार' शीर्षक से पेश हुए एक कार्यक्रम में मशहूर अभिनेता अन्नू कपूर से बातचीत की अभिनेता और फिल्म लेखक रूमी जाफ़री ने, जिसमें सिनेमा और उर्दू अदब के हवाले से बहस की गई. इस कार्यक्रम में कुछ कलाकारों ने अपने गीत भी पेश किए. 'उर्दू का अदालती लेहजा' शीर्षक से इस बार एक ख़ास प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस टी एस ठाकुर, रिटायर्ड जस्टिस आफ़ताब आलम, राजनेता सलमान ख़ुर्शीद और प्रो. ताहिर महमूद ने अदालतों में उर्दू शायरी के इस्तेमाल की दिलचस्प कहानियां बयान की.

फ़ौज़िया अर्शी की ग़ज़लों के एलबम का लोकार्पण

तीसरे दिन के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण ग़ज़ल गायिकी का भी रहा. इस प्रोग्राम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मोरारका और सुप्रसिद्ध समाज सेविका भारती मोरारका ने फ़ौज़िया अर्शी की ग़ज़लों के एलबम 'ग़ज़ल बाई ग्रेट मास्टर्स' का लोकापर्ण किया. यूं तो कमल मोरारका किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन प्रोग्राम की मुनासबत से उनके बारे में भी कुछ कहना ज़रूरी हो जाता है. एक तरफ जहां वे देश के सर्वश्रेष्ठ 10 उद्योगपतियों में से एक हैं, वहीं पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं. वे देश के बेहतरीन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में से एक हैं, साथ ही आर्ट क्रिटिक भी हैं. उनके बारे में अगर गुलज़ार साहब के शब्दों में कहें, तो बेशक वे भी उर्दू के आशिक़ों में से एक हैं और बड़ी ख़ामोशी के साथ इस ज़ुबान की ख़िदमत कर रहे हैं. इस प्रोग्राम में फ़िल्मकार, संगीतकार और ख़ूबसूरत आवाज़ की धनी फ़ौज़िया अर्शी ने उर्दू के अज़ीम शायरों मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा ग़ालिब, बहादुर शाह ज़फर और फैज़ अहमद फैज़ का कलाम गुनगुना कर कार्यक्रम में मौजूद ग़ज़ल गायिकी के शैदाइयों का दिल जीत लिया. यहां पेश की गई ग़ज़लें जिनमें 'हस्ती अपनी हुबाब की सी है (मीर तक़ी मीर)', 'बेख़ुदी बे सबब नहीं (मिर्ज़ा ग़ालिब)', 'इश्क में ज़ालिम तेरे (बहादुर शाह ज़फर)', और 'नहीं निगाह में मंज़िल (फैज़ अहमद फैज़)' शामिल हैं, के अलावा 'बात मेरी कभी सुनी ही नहीं (दाग़ देहलवी)' फ़ौज़िया अर्शी के एलबम 'ग़ज़ल बाई ग्रेट मास्टर्स' की ज़ीनत बनी हैं.

दरअसल, जश्न-ए-रेख्ता की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील यह रही कि इसमें नौजवानों, स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. इससे ज़ाहिर होता है कि इस ज़ुबान के चाहने वालों की एक नई नस्ल तैयार हो गई है. रेख्ता ने उनके ज़ौक़ का सामान भी मुहैया करा दिया है. जिस सफ़र पर संजीव सराफ तन्हा रवाना हुए थे, उसने अब एक कारवां का रूप ले लिया है. मजरूह सुल्तानपुरी ने शायद उन्हीं जैसे लोगों के लिए यह शेर कही थी:

मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंज़िल मगर,
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

शहाबुद्दीन की तिहाड़ यात्रा

इर्शादुल हक

शहाबुद्दीन मामले में बिहार का पुलिस प्रशासन इतना चौकन्ना शायद ही कभी रहा हो. इस बार वे न सिर्फ चौकन्ने थे, बल्कि उनका हर कदम गोपनीयता से भरा था. चौकन्नापन और गोपनीयता के साथ-साथ जो सबसे खास बात थी, वह थी पुलिस अधिकारियों की शहाबुद्दीन के प्रति जवाबदेही. बिहार पुलिस शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने के लिए सीवान जेल से निकाल कर पटना के राजेंद्रनगर टर्मिनल पर ट्रेन में बैठा चुकी थी. लेकिन यह पूरी प्रक्रिया महज एक ड्यूटी नहीं थी, यह तो मिशन था. इस मिशन की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत हुई थी, जिसमें उसने बिहार सरकार से कहा था कि वह एक सप्ताह के अंदर शहाबुद्दीन को सीवान जेल से, दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करे. साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि शहाबुद्दीन के ऊपर चलने वाली तमाम अदालती कार्रवाई तिहाड़ से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चलाई जाए. इसलिए बिहार पुलिस ने 19 फरवरी को अदालती हुक्म की तामील करते हुए शहाबुद्दीन को ट्रेन में बैठा दिया. अगले दिन यानी 20 फरवरी को औपचारिक रूप से शहाबुद्दीन तिहाड़ के कैदी बन गए.

जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, शहाबुद्दीन को सीवान से दिल्ली शिफ्ट करने की प्रक्रिया बिहार पुलिस की ड्यूटी से ज्यादा एक मिशन का हिस्सा थी. एक गोपनीय मिशन, एक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और सतर्कता से भरा मिशन. आखिर यह मिशन क्यों था? इसमें सतर्कता क्या थी और इस मिशन को पूरा करने में पुलिस ने किस संवेदनशील जिम्मेदारी को निभाया. ये तमाम बातें काफी दिलचस्पी से भरी हैं.

सबसे पहले संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की बात करते हैं. शहाबुद्दीन कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सुबह के धुंधलके अंधेरे में पटना पहुंच चुके थे. उनके पास तब ट्रेन पकड़ने के लिए 14 घंटे का वक्त था. ऐसे में पुलिस अधिकारियों के सामने दो सवाल थे. पहला, ट्रेन के प्रस्थान समय से 14 घंटे पहले ही शहाबुद्दीन को पटना क्यों लाया गया. दूसरा, अगर उन्हें पटना लाया ही गया, तो चौदह घंटे उन्हें रखा कहां जाए. 14 घंटे पहले पटना लाने के पीछे ये तर्क था कि शहाबुद्दीन को अगर दिन में सीवान से पटना लाया जाता, तो उनके समर्थकों की भीड़ को काबू में करना एक गंभीर चुनौती बन जाती. अब पुलिस अधिकारियों के सामने यह चुनौती थी कि शहाबुद्दीन को 12-14 घंटे कहां ठहराया जाए. पुलिस चाहती तो उन्हें किसी अज्ञात जगह पर रख सकती थी. लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया. उसने शहाबुद्दीन को सीवान से पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट किया. माना जा रहा है कि मीडिया और विपक्षी दलों की आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया गया. भाजपा जैसे विरोधी दल शहाबुद्दीन मामले में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते. पुलिस अगर शहाबुद्दीन को अस्थाई तौर पर किसी अज्ञात जगह पर ठहराती, तो विरोधी दल और मीडिया इसकी खोज में लग जाते और सवाल करते कि हत्या के इस आरोपी की मेहमाननवाजी क्यों की जा रही है. इसलिए पुलिस इन आलोचनाओं से बचने के लिए सीधे उन्हें बेऊर जेल के गेट पर ले गई. हालांकि शहाबुद्दीन को बेऊर में अस्थाई तौर पर शिफ्ट करने का न कोई औपचारिक आदेश था और ना ही इस तरह का कोई प्रोविजन था. लिहाजा वहां इसकी कोई तैयारी भी नहीं थी. बेऊर गेट पर पुलिस वैन शहाबुद्दीन को ले कर ढाई घंटे तक खड़ी रही. सूत्र बताते हैं कि आला अधिकारियों ने इस संबंध में आनन-फानन में टॉप लेवल के राजनीतिक नेतृत्व से सम्पर्क साधा था. तब उन्हें निर्देश दिया गया कि शहाबुद्दीन के अस्थाई ठहराव के लिए उन्हें बेऊर ले जाना ही उचित रहेगा, वरना विपक्षी दल और मीडिया सरकार पर सवाल उठाने लगेंगे. उतनी सुबह बेऊर के जेल अधीक्षक भी नींद में थे, उन्हें जगाया गया. वे अपने आवास से आए, फिर औपचारिकता पूरी की गई और तब शहाबुद्दीन को जेल में एंट्री मिली. शहाबुद्दीन को बेऊर शिफ्ट करने की कोई पूर्वनिर्धारित योजना नहीं थी. इसलिए इसकी भनक जेल अधिकारियों को भी नहीं लगी. ध्यान रहे कि शहाबुद्दीन बिहार के उन कुछ नेताओं में से हैं, जो मीडिया के लिए टीआरपी और विरोधियों के लिए गंभीर राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं. इसीलिए सरकार की तरफ से शहाबुद्दीन मामले में सख्त निर्देश दिए गए थे. पुलिस ने इन निर्देशों का पालन किया. नतीजा सामने था. इस पर न तो मीडिया ने कोई सवाल उठाया और न ही विपक्ष को हमला करने का कोई मौका मिला.

शहाबुद्दीन को तिहाड़ शिफ्ट करने के मामले में पुलिस प्रशासन ने गोपनीयता का भी बहुत ध्यान रखा. आलम यह था कि आखिरी लम्हे तक अधिकारियों ने यह राज छुपाए रखा कि शहाबुद्दीन को कैसे, किस माध्यम से और कहां से दिल्ली भेजा जाना है. शहाबुद्दीन की सुरक्षा को ले कर पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी. अधिकारियों द्वारा इस अभियान में गोपनीयता बरतने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जिस सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से शहाबुद्दीन को दिल्ली भेजा उसका टिकट भी शहाबुद्दीन के नाम पर बुक नहीं कराया गया था. खबरों के अनुसार, पुलिस ने 48 या 50 बर्थ बुक कराया था. लेकिन बुकिंग लिस्ट में कहीं भी शहाबुद्दीन का नाम नहीं था. इसलिए जब ट्रेन में टीटीई पहुंचा, तो शहाबुद्दीन के स्लीपर क्लास में बैठने के एवज में अतिरिक्त शुल्क दिया गया.

शहाबुद्दीन के तिहाड़ शिफ्ट करने के मामले में पुलिस प्रशासन ने गोपनीयता का भी बहुत ध्यान रखा. आलम यह था कि आखिरी लम्हे तक अधिकारियों ने यह राज छुपाए रखा कि शहाबुद्दीन को कैसे, किस माध्यम से और कहां से दिल्ली भेजा जाना है. शहाबुद्दीन की सुरक्षा को ले कर पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी. अधिकारियों द्वारा इस अभियान में गोपनीयता बरतने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जिस सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से शहाबुद्दीन को दिल्ली भेजा उसका टिकट भी शहाबुद्दीन के नाम पर बुक नहीं कराया गया था. खबरों के अनुसार, पुलिस ने 48 या 50 बर्थ बुक कराया था. लेकिन बुकिंग लिस्ट में कहीं भी शहाबुद्दीन का नाम नहीं था. इसलिए जब ट्रेन में टीटीई पहुंचा तो शहाबुद्दीन के स्लीपर क्लास में बैठने के एवज में अतिरिक्त शुल्क दिया गया. पुलिस की यह सतर्कता लाजिमी भी थी, क्योंकि इससे पहले सितम्बर 2016 में जब शहाबुद्दीन को बेल मिली थी और जब वे भागलपुर से सीवान आए थे, तब भागलपुर से ले कर सीवान तक पूरे रास्ते शहाबुद्दीन समर्थकों और मीडिया को संभाल पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था.

राजनीतिक ख़ामोशी लेकिन सोशल मीडिया में हलचल

फरवरी के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने चंदा बाबू की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, जिसमें गुजारिश की गई थी कि सीवान में रहते हुए शहाबुद्दीन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. चंदा बाबू के तीन बेटों की हत्या का इल्ज़ाम शहाबुद्दीन पर है और उसकी सुनवाई सीवान की अदालत में चल रही है. अदालत के आदेश के बाद बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष की तरफ से, उम्मीदों के अनुरूप कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. विपक्ष ने भी औपचारिक बयान देते हुए महज अदालती आदेश का स्वागत किया. लेकिन सोशल मीडिया में हलचल जरूर मच गई. फेसबुक पर शहाबुद्दीन समर्थकों और विरोधियों में जबर्दस्त भिड़ंत हो गई. शहाबुद्दीन समर्थक, इस पूरे मामले में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेने लगे. उनका कहना था कि मुसलमानों के वोट से सत्ता में आई इस सरकार ने ही सितम्बर में शहाबुद्दीन को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उन्हें दोबारा जेल भेजवा दिया. कई शहाबुद्दीन समर्थकों ने तो इसके लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी पोस्ट की. इन टिप्पणियों के बाद लालू समर्थकों ने भी आपत्तिजनक टिप्पणिया फेसबुक पर पोस्ट की.

पिछले छह-सात महीनों के घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं, तो शहाबुद्दीन जेल से जमानत पर बाहर आए, राज्य सरकार और चंदा बाबू ने उनकी बेल को चैलेंज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दिया और अब आखिर में उन्हें दिल्ली की जेल में शिफ्ट कर दिया गया. ये तमाम मामले मीडिया में जबर्दस्त हलचल की वजह बने रहे हैं. हालांकि अब तिहाड़ में रहते हुए भी आरोपों की सुनवाई के कारण शहाबुद्दीन समय-समय पर चर्चा का विषय बनते रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

जन्मांक के हिसाब से इस सप्ताह आपका भविष्यफल

क्या कहता है आपका टैरो कार्ड

अलंकृता मानवी
लेखिका मशहूर टैरो कार्ड रीडर हैं. आप भी अगर टैरो कार्ड के ज़रिए अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो संपर्क करें- astro@chauthiduniya.com

जन्मांक 1: (जिनका जन्म 1, 19, 28 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह सूर्य है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, नाइन ऑफ ज्वेल्स. इस हफ्ते आपको वित्तीय लाभ मिलेगा. कोई पुरानी/पैतृक संपत्ति मिल सकती है. अचानक कहीं से पैसा आने की उम्मीद है. आपकी किस्मत में इस हफ्ते बहुत सारा पैसा है.

जन्मांक 2: (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह चन्द्रमा है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, सिक्स ऑफ ज्वेल्स. इस सप्ताह यदि आप दान-पुण्य करेंगे, उदारता दिखाएंगे और दूसरों की सहायता करेंगे, तो आपको फायदा होगा.

जन्मांक 3: (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, परिनिर्वाण कार्ड. यह हफ्ता आपके लिए आरामदायक और तनावरहित रहने वाला है. आपको पेशेवर और वित्तीय फायदा मिल सकता है. टेंशन न लें, आराम से रहें, ध्यान और योगा करें.

जन्मांक 4: (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह है यूरेनस यानी अरुण ग्रह)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, अमोघ सिद्धी कार्ड. अगर आप पढ़ाई और करियर में आगे जाना चाहते हैं, तो दैवीय आशीर्वाद जरूर लें. इससे आपको लाभ मिलेगा. आपकी इच्छा पूरी होगी.

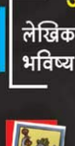

जन्मांक 5: (जिनका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह बुध है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, डाकनी ऑफ वज्र कार्ड. इस सप्ताह यदि आप कोई रचनात्मक काम करते हैं, तो लाभ मिलेगा. कलाकारों के लिए यह सप्ताह बेहतर है. आप अपनी जिंदगी में रचनात्मकता लाएं. इससे खुशी और नई ऊर्जा मिलेगी.

जन्मांक 6: (जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह शुक्र है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, कर्मा जस्टिस कार्ड. यदि आप इस सप्ताह अच्छा काम करेंगे, तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा. जैस कर्म करेंगे, वैसा प्रभाव होगा. प्रयास करेंगे तभी परिणाम मिलेगा. सोच समझ कर काम करें.

जन्मांक 7: (जिनका जन्म 7, 16, 25 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह वरुण है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, एस ऑफ ज्वेल्स कार्ड. इस सप्ताह आपकी हर इच्छा (विश) पूरी होगी. प्रयास करेंगे, तो अच्छा परिणाम मिलेगा. वित्तीय फायदा होगा.

जन्मांक 8: (जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह शनि है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, सिक्स ऑफ डबल वज्र कार्ड. इस सप्ताह आप भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करेंगे. संतुष्टि का एहसास होगा. पार्टनरशीप के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप जितना प्यार बांटेंगे, उतना ही प्यार मिलेगा.

जन्मांक 9: (जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह मंगल है) ?
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, टू ऑफ डबल वज्र कार्ड. ये सप्ताह शादी/पार्टनरशीप/लव अफेयर/नई ऊर्जा/नए काम के लिए काफी अच्छा रहेगा.

सेलीब्रिटी टैरो कार्ड

इस हफ्ते आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म बद्री की दुल्हनिया आ रही है. आइए, जानते हैं कि टैरो कार्ड के हिसाब से इन दोनों और फिल्म का भविष्य क्या होगा?

आलिया भट्ट
इनका कार्ड है फाइव ऑफ वज्रा और सेवन ऑफ डबल वज्रा. इसके मुताबिक ये फेमस होंगी, लेकिन इनके बीमार पड़ने की भी संभावना है. इन्हें सलाह लेने की जरूरत है.

फिल्म बद्री की दुल्हनिया
इस फिल्म का कार्ड है, एस ऑफ लोटसेज. कुल मिला कर ये फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी.

वरुण धवन
इनका कार्ड है, नाईन ऑफ ज्वेल्स और द बुद्धा ऑफ डबल वज्रा. इन्हें बहुत सारा पैसा मिल सकता है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इन्हें दैवीय सुरक्षा भी लेनी चाहिए.

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

प्रधानमंत्री पद की गरिमा बरक़रार रहनी चाहिए

प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है. दो कारणों से यह दुखद है. एक तो ये कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं. यदि वे अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने जाते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद और कार्यालय की गरिमा को अवश्य बरकरार रखना चाहिए. उन्हें केवल अपनी पार्टी के लिए ही नहीं बोलना चाहिए. एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि बेशक उन्हें उनके सूत्र और खुफ़िया विभाग ये बताते होंगे कि उनकी पार्टी राज्य में बहुत अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए वे कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों. हालांकि उनका पिछला बयान, जो उन्होंने हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब कब्रिस्तान के लिए ज़मीन आवंटित होती है, तो श्मशान के लिए भी होनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं. एक अंतिम चरण, यानी सातवें चरण का चुनाव बाकी रह गया है. परिणाम 11 मार्च को आएगा, तभी ये पता चलेगा कि कौन जीता, कौन हारा. लेकिन हर कोई ये देख रहा है कि यूपी में प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाषा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है. दो कारणों से यह दुखद है. एक तो ये कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं. यदि वे अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने जाते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद और कार्यालय की गरिमा को अवश्य बरकरार रखना चाहिए. उन्हें केवल अपनी पार्टी के लिए ही नहीं बोलना चाहिए. एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि बेशक उन्हें उनके सूत्र और खुफ़िया विभाग ये बताते होंगे कि उनकी पार्टी राज्य में बहुत अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए वे कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर भी, यह मुद्दा इतना छोटा है, जिसे देश के प्रधानमंत्री को उठाने की जरूरत नहीं थी.

इसी तरह, असफल हो चुके नोटबन्दी के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास कहते हैं कि अभी भी उतने ही नोट निकालें जितना चाहिए. इसका मतलब है कि लोग अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा निकाल रहे हैं. यह कैशलेस और लेसकैश इकॉनोमी बनाने में उनका प्रयास है. ये एक बेकार का विचार है, स्टुपिड आइडिया है. भारत जैसे देश में 97 फीसदी लेनदेन

> **अगर यूपी में बीजेपी ठीक ठाक प्रदर्शन करती है, तो हमारे सामने दो साल तक मुश्किल समय रहेगा. यदि बीजेपी को मतदाता निराश करते हैं, तो फिर उनको कुछ सदबुद्धि आएगी (हालांकि इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कभी-कभी नेताओं का व्यवहार प्रतिकूल भी होता है). अगर वे 11 मार्च को अच्छा नहीं करते, तो उन्हें 2019 जीतने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए. तो सवाल यह है कि विपक्ष को क्या पहल करनी चाहिए.**

नगद में होता है. लेनदेन की संख्या के लिहाज़ से, राशि के लिहाज़ से नहीं. ज़ाहिर सी बात है, बड़ी राशि का लेनदेन बैंकों के चैनल के जरिए ही होता है. यह देश कैश के इस्तेमाल का इतना आदि है कि पहले तो इस आदत को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर बदलना ही है, तो इसके लिए 10 साल 15 साल 20 साल का समय लगेगा. पहले नोट बंद करना फिर कार्ड का इतेमाल लोगों के सर ज़बरदस्ती मढ़ना बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार है. राजनेता वोट हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन यदि सचिव स्तर के अधिकारी इस तरह का बयान देने लगे, तो ये दिखाता है कि उच्चतर स्तर का प्रशासनिक सेटअप कमजोर हुआ है. जब एटीएम से भी नकली पैसे

निकलने लगें, तो सिस्टम की दुर्दशा का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये संकेत ठीक नहीं हैं. ईमानदारी से प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी के फैसले ने काम नहीं किया, यानी ये असफल रहा. उन्हें देश के उन कामों में लगना चाहिए, जिसके लिए देश ने उन्हें चुना है. बहरहाल, 11 मार्च तक ये सब चलता रहेगा. अगर यूपी में बीजेपी ठीक ठाक प्रदर्शन करती है, तो हमारे सामने दो साल तक मुश्किल समय रहेगा. यदि बीजेपी को मतदाता निराश करते हैं, तो फिर उनको कुछ सदबुद्धि आएगी (हालांकि इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी नेताओं का व्यवहार प्रतिकूल भी होता है). अगर वे 11 मार्च को अच्छा नहीं करते, तो उन्हें 2019 जीतने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए. तो सवाल यह है कि विपक्ष को क्या पहल करनी चाहिए. उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में मात देने के लिए. लेकिन ये बातें भी 11 मार्च के बाद होनी चाहिए, अभी ऐसा करना बहुत जल्दबाजी होगी.

दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी में पिता-पुत्र और चाचा के बीच रस्साकशी के बाद आखिरकार साइकल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव को मिला. यह बहुत दुखद है कि चुनाव आयोग के समक्ष मुलायम सिंह ने पार्टी पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से गंभीर प्रयास नहीं किए. यह लोगों को पता चल गया कि वे अपने पुत्र के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहते थे. अब अमर सिंह, जो समाजवादी पार्टी में बहुत अन्दर तक घुसे रहे है, ने कहा है कि इस ड्रामे की पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी. हालांकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं. लेकिन तथ्य ये है कि समाजवादी पार्टी एकजुट हो कर चुनाव लड़ रही है, चाहे परिणाम जो हो. मैंने पहले भी कहा है कि हमें 11 मार्च तक इंतजार करना चाहिए. देश हित के लिए आशा करनी करनी चाहिए. नतीजे ऐसे हों जो आने वाले दिनों में सरकार को सार्थक कदम उठाने पर मजबूर कर दें. देखते हैं क्या होता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

बेख़ौफ़ होना भी ख़ौफ़नाक होता है

शुजात बुख़ारी

भारत ने हम पर सबसे बड़ा एहसान ये किया है कि उसने हमारे मन से मौत और बंदूक का ख़ौफ़ निकाल दिया है. लिहाज़ा अब हमें इनकी परवाह नहीं है. ये अल्फाज़ पिछले साल दिसंबर में शोपियां में युवाओं के एक समूह ने पूर्व भारतीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात के दौरान कहे थे. दरअसल, इन शब्दों की गूंज 12 फरवरी को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और मिलिटेंट के दरम्यान हुए मुठभेड़ में भी महसूस की गई. फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित समीर वासिर की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब सुरक्षा बल फ्रिसल (कुलगाम) में मुठभेड़ स्थल पर मोपिंग ऑपरेशन कर रहे थे, तो युवाओं ने चारों ओर से उन पर पत्थर फेंके. मुठभेड़ स्थलों तक लोगों के पहुंचने की यह नई प्रवृत्ति सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है, खास तौर पर जब वे कोलैटरल डैमेज से बचना चाहते हों. इस प्रवृत्ति ने एक साहसी पीढ़ी पैदा की है, जो यशवंत सिन्हा जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता के सामने यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें (सेना की) कोई परवाह नहीं है.

कुलगाम के मुठभेड़ में मारे गए चार मिलिटेंटों के जनाज़े में हिस्सा लेने के लिए जब हजारों की भीड़ उमड़ी, तो पिछले 26 सालों में पहली बार 18 फरवरी 2016 को पुलिस को जनता के लिए एडवाइजरी जारी करने पर मजबूर होना पड़ा. इस एडवाइजरी में कहा गया था कि किसी एनकाउंटर स्थल के दो किलोमीटर की परिधि में रहने वाले नागरिक (एनकाउंटर की स्थिति में) अपने घरों में ही रहें और अपने बच्चों को भी बाहर न निकलने दें. ऐसा करने से छिटक कर या गलती से उन्हें भी गोली लग सकती है. नागरिकों से यह भी अपील की जाती है कि वे अपने घरों के दरवाजों या खिड़कियों से बाहर झांक कर न देखें. एडवाइजरी में बड़े बुजुर्गों से भी अपील की गई थी कि वे इस सिलसिले में लोगों को सचेत करें. इस तरह का ट्रेंड उस समय स्थापित हुआ था, जब 25 दिसम्बर 2015 को कुलगाम के इलाके में ही लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू कासिम (पस्किस्तानी नागरिक) के जनाज़े में लगभग 30,000 लोग शरीक हुए थे. यहीं से मिलिटेंटो के प्रति लोगों की धारणा में बदलाव की शुरुआत हुई और यह भी संकेत मिला कि पुलिस तेजी से अपनी पकड़ खोती जा रही है.

अबू क़ासिम के मारे जाने के बाद मिलिटेंटों के जनाज़ों में हिस्सा लेने का एक चलन सा बन गया और इसने लोगों के उस जुनून को पुनर्जीवित कर दिया, जिसके तहत वे मिलिटेंटो को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधि मानते हैं. हालांकि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के भीतर इसे खतरे की घंटी के रूप में देखा गया. शीर्ष के अधिकारियों से ये पूछा गया कि एक पाकिस्तानी नागरिक, जो पुलिस के अनुसार यहां तबाही फैलाने आया था, उसकी अंतिम विदाई में एक विशाल जन समूह को शामिल होने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

जब तक पुलिस हरकत में आती और हालात पर नियंत्रण कायम करती, तब तक मिलिटेंटो की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए आंदोलन करने वालों ने हालात पर अपना कब्जा जमा लिया था. अब हालात 1990 के दशक से

बिलकुल अलग हो गए थे, जब एनकाउंटर की हालत में लोग भाग कर छिपने की कोशिश करते थे. फ़रवरी 2016 में पंपोर स्थित इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के प्रांगण में एनकाउंटर के दौरान 48 घंटे तक गोलियां चली थीं और पहली बार लोगों को किसी एनकाउंटर स्थल के पास जमा होते देखा गया था. महिलाओं ने लोक गीत गा कर मिलिटेंटो की वीरता का बखान किया. यह भी देखा गया कि जब उनके शवों को उनके घरों को भेजा गया, या विदेशी होने की हालत में दफन करने के लिए कब्रिस्तान लाया गया, तो महिलाओं ने 'मेहंदी' लगा कर दूल्हे की तरह उनकी विदाई की. यह एक लंबे समय तक जारी रहा. हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी की सोशल मीडिया पर बहादुरी ने सशस्त्र संघर्ष को नई गति दे दी है.

8 जुलाई 2016 के एनकाउंटर में उसकी मौत के बाद यह मालूम हुआ कि उसकी छवि कितनी शक्तिशाली हो गई थी और कैसे उसने साधारण कश्मीरी नौजवानों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई थी. उसके बाद छह महीने तक कश्मीर बंद रहा और इस विद्रोह ने एक नए कश्मीर को परिभाषित किया. उसी वजह से शोपियां में नौजवानों के समूह ने यशवंत सिन्हा को बताया कि वे किसी चीज़ की परवाह नहीं करते. इस बीच बुरहान छाया रहा. यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में उसे कश्मीरियों का नया हीरो कहा. कुछ विश्लेषकों के मुताबिक, उस घटना ने सैयद अली गिलानी, मीरवाइज़ उमर फारूक़ और यासीन मलिक़ की तिकड़ी को महत्वहीन बना दिया. हालांकि बुरहान की मौत से जो तूफान पैदा हुआ, उसने कई मोर्चों पर नई दिल्ली को घेर लिया और राज्य में वर्तमान में पीडीपी-भाजपा सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई. इस दौरान गोलियों एवं पेलेट गनों कि बारिश होती रही, जिसे हजारों लोग अपंग और अक्षम हुए. लेकिन यह सब वास्तव में पिछले एक साल से कश्मीर में हो रही घटनाओं के परिणाम स्वरुप हुआ. राज्य का झंडा हटाने, बीफ पर प्रतिबंध लगाने, सैनिक और पंडित कॉलोनियों की स्थापना के प्रस्तावों ने कश्मीरियों के बीच अत्यधिक असुरक्षा की भावना पैदा की है. वे एक अवसर के लिए इंतजार कर रहे थे और बुरहान की घटना उनके लिए एक अवसर की तरह थी.

अभी यह बहस जारी थी कि अगले कुछ महीनों में कश्मीर में क्या होगा, तभी कुलगाम का एनकाउंटर सामने आ गया, जिसमें दो नागरिकों की जानें गईं. इस तरह की अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि इस साल की गर्मियां भी 2016 के जैसे होने वाली हैं. ऐसा किसने कहा और क्यों कहा? इसके लिए शायद कोई स्पष्ट जवाब न हो. 2008 और 2010 की तरह ही 2016 की घटनाएं आम लोगों और नेतृत्व दोनों के एक सबक की तरह हैं. इसमें कोई शक नहीं कि निर्दोष नागरिकों की हत्या पर शोक प्रकट किया जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक संघर्ष और सशस्त्र संघर्ष में अवश्य फर्क किया जाना चाहिए. जब भावनाएं अत्यधिक तीव्र हों, तो कभी-कभी यह सुझाव देना असंभव लगने लगता है कि नेतृत्व ऐसी रणनीति अपनाए, जिससे खुद का नुकसान न हो. इसका मतलब यह नहीं है कि केवल भावनाओं से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए. एक महत्वपूर्ण सबक यह भी है कि विरोध को, अंतहीन कैलेंडर को कैसे समाप्त किया जाए. क्या नेतृत्व को कैलेंडर जारी करने के महेनज़र पैदा असंतोष का आनंद राज्य को लेने देना चाहिए? नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, लिहाज़ा उस विश्वास का इस्तेमाल सही दिशा में करना चाहिए.

जिस तरह से लोगों ने मिलिटेंसी को सामाजिक स्वीकृति दी है, वह दीवार पर लिखी इबारत है. अब यह नई दिल्ली को देखना है कि कश्मीर किधर जा रहा है? जब तक हिंसा और जवाबी हिंसा इस तथ्य के संदर्भ में कारगर रहेगी कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हैं, तब तक लोगों को ही उसके परिणाम का सामना करना पड़ सकता है. नई दिल्ली निश्चित रूप से उन पर से अपना नियंत्रण खो चुकी है, क्योंकि अब लोग सुलह के विचार से दूर जा चुके हैं. अब लोगों को डायलॉग के लिए राज़ी करने में अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी की जरूरत है. अभी तक दिल्ली में बीजेपी सरकार ने इस दिशा में कोई इशारा नहीं दिया है. शायद उसे लग रहा है कि भारी हथियारों से लैस सेटअप से यह मसला हल किया जा सकता है. लेकिन राजनीति कश्मीर समस्या के केंद्र में है और इससे दूर हटने का मतलब है, हिंसा को बुलाना, जैसा कि पहले ही ज़ाहिर हो चुका है. लोग इस हिंसा का हिस्सा बनने में संकोच नहीं करते. केवल हिंसा के माध्यम से समाधान के बारे में सोचना खतरनाक है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा. नरेंद्र मोदी के लिए भले ही जम्मू एवं कश्मीर किसी अन्य राज्य की तरह कोई राज्य हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं. कश्मीर इस क्षेत्र के ग्रेट गेम (महान खेल) का हिस्सा है, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ज़ाहिर है, भारत शामिल हैं. आप कब तक युवाओं के खिलाफ पेलेट गनों के इस्तेमाल पर सफाई देंगे? हर बार इस तरह के उल्लंघनों से बचा नहीं जा सकता है.

12 फरवरी को जब बंदूकें खामोश हो गईं और फ्रिसल एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटो के अंतिम संस्कार की तस्वीरें राइजिंग कश्मीर के आधिकारिक सोशल मीडिया साईट पर प्रकाशित की गईं, तो दो घंटे के भीतर इसके व्यूअरस की संख्या 4,50,000 के पार हो गई थीं और उन तस्वीरों को व्यापक रूप से शेयर भी किया गया था. कश्मीर में मिलिटेंसी में नए जोर आए हैं, जिसमे मिलिटेंटो के जनाज़े में लोगों की भारी हिस्सेदारी भी हो रही है. इस तथ्य के महेनज़र जो लोग आश्वस्त हैं कि बाद में इससे निपट लिया जाएगा, उन्हें अपना यह ख्याल त्याग देना चाहिए.■

–लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

चुनाव परिणाम आने के बाद देश में एक नयी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी

फिर बैतलवा डाल पर. उत्तर प्रदेश चुनाव में अब लगभग यही हो गया है. कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि कौन चुनाव जीतेगा. भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साह में है. उसके पास साधनों की कमी नहीं है. वो प्रचारकों की एक बड़ी सेना के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी, लेकिन अजीत सिंह ने पहले दौर में उसे परेशान कर दिया. चुनाव के शुरू में ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन ने ये आभास दे दिया था कि वो सत्ता के प्रबल दावेदार हैं और उनका बनाया वातावरण अभी तक उन्हें निराश नहीं कर रहा है. तीसरा बड़ा दल मायावती का है. मायावती एक सशक्त सामाजिक गठजोड़ के साथ चुनाव में उतरी हैं, जिसमें दलित और मुस्लिम समाज एक साथ रहकर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है. पर इनमें से सच क्या है?

उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे पहले हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन की बात करें. इस गठबंधन में सबकुछ अच्छा दिखने के बाद भी दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती नजर नहीं आ रही हैं. कांग्रेस के वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ झुकते देखे जा रहे हैं. अखिलेश यादव के लिए पहली चुनौती उनके अपने समर्थक हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला और वो चुनाव में खड़े हो गये हैं. दूसरी चुनौती मुलायम सिंह यादव के समर्थकों की है, जो भले ही बड़े पैमाने पर चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन वो अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को दिल से समर्थन करते नहीं दिख रहे हैं. इसके बावजूद नौजवानों का एक बड़ा तबका अखिलेश यादव के साथ चुनाव में खड़ा दिखाई दे रहा है. आमतौर पर यह धारणा बनी है कि अखिलेश और राहुल गांधी का गठजोड़ नौजवानों की आशाओं को पूरा करने वाला गठजोड़ हो सकता है.

पर अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या उनके खिलाफ एक नए वातावरण का होना है. पिछड़े वर्ग का सबसे सशक्त समाज यादव समाज उनके साथ है और मानना चाहिए कि पूरी तौर पर उनके साथ है. लेकिन यादव समाज के अलावा जितने समाज हैं, जिन्हें हम पिछड़ा कहते हैं, जिनमें कुर्मी, कोयरी, लोधी हैं, ये सभी लोग अखिलेश यादव के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं. सभी पिछड़ों में ये भावना घर कर गई है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों को सत्ता में प्रमुखता देना चाहते हैं. पिछड़े वर्ग के दूसरे तबकों को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं. छोटे-छोटे समाज, जिनमें पाल, सैनी,

> **“अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या उनके खिलाफ एक नए वातावरण का होना है. पिछड़े वर्ग का सबसे सशक्त समाज यादव समाज उनके साथ है और मानना चाहिए कि पूरी तौर पर उनके साथ है. लेकिन यादव समाज के अलावा जितने समाज हैं, जिन्हें हम पिछड़ा कहते हैं, जिनमें कुर्मी, कोयरी, लोधी हैं, ये सभी लोग अखिलेश यादव के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं. सभी पिछड़ों में ये भावना घर कर गई है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों को सत्ता में प्रमुखता देना चाहते हैं.”**

कुम्हार हैं, इस तरह की बहुत सारी जातियां जो थोड़ा-थोड़ा मिलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, वो समाजवादी पार्टी से छिटक गई हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गई हैं. मजे की बात यह है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना नहीं पड़ा है. जब मुलायम सिंह अपने नेतृत्व में रणनीति बनाते थे तो वे दूसरे समाज को सीटें ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन वो ये आभास पूरे पिछड़े वर्ग को दिलाते थे कि जो लोग उनके साथ हैं, वही प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं. इसका परिणाम यह होता था कि यादवों के अलावा पिछड़े वर्ग के जितने समाज हैं, वो सब मुलायम सिंह के साथ बड़ी संख्या में खड़े दिखाई देते थे. इस बार अखिलेश यादव से ये चूक हो गयी और वो सिर्फ और सिर्फ यादव समाज के नेता के तौर पर उभर कर सामने आये. इसका दुष्परिणाम शायद उन्हें भोगना पड़ सकता है क्योंकि पिछड़े समाज के बाकी तबकों के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए.

इसी गठबंधन का दूसरा हिस्सा कांग्रेस अपने प्रचारकों की फौज के साथ मीटिंग करने में तो सफल हो रहा है, लेकिन जिस स्टार प्रचारक के बल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह या उम्मीदवारों में जीतने की रणनीति बननी थी, वो चुनाव से सिरे से दूर हैं. प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करना था, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे. लेकिन प्रियंका गांधी ने खबरें लीक कराईं कि अब वो पूरे प्रदेश में नहीं, बल्कि सिर्फ रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार करेंगी. जब वो एक दिन के लिए चुनाव प्रचार में उतरीं, तो कार्यकर्ताओं को लगा कि शायद अब वो आगे बढ़ें. तब तक तीन दौर के मतदान हो चुके थे. शायद प्रियंका गांधी ने प्रचार में उतरना सही नहीं समझा. हो सकता है उनके पास ये फिडबैक गया हो कि कांग्रेस को 40 सीटों के आसपास मिल सकती है. अगर वो चुनाव प्रचार में उतरीं, तो हो सकता है उनके ऊपर ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि प्रियंका गांधी के प्रचार के बावजूद कांग्रेस 80, 90 सीटें नहीं जीती. हालांकि प्रियंका गांधी के विश्वासपात्र प्रशांत किशोर, जिन्हें बाजार में पीके कहा जाता है, उनका मानना है कि कांग्रेस 70 सीटों के आसपास जीत सकती है.

अब मायावती जी पर आते हैं. मायावती जी घूम रही हैं. कांग्रेस और अखिलेश यादव के पक्ष में लालू यादव सभाएं कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने ये बात सफलतापूर्वक मुस्लिम मतदाताओं के मन में डाली है कि अगर मायावती सत्ता में आने की कोशिश करती हैं, तो बिना भारतीय जनता पार्टी के नहीं आ सकती हैं. यही काम लालू यादव ने भी किया है, जिसको लेकर मायावती जी को बार-बार ये बयान देना पड़ रहा है कि वो बीजेपी के साथ सत्ता में नहीं जाएंगी. मायावती के साथ एक दुविधा ये भी है कि दलितों के साथ जिन अतिपिछड़े समाजों का रिश्ता बना था, वो रिश्ता इस चुनाव में टूट गया है. मायावती की पुरानी रणनीति है कि सिर्फ और सिर्फ अपने को सामने रखो और सबकी नेता की छवि बनाओ. पर शायद इस चुनाव में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सबसे आखिर में भारतीय जनता पार्टी, जो बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ रही है. उसने बिहार की रणनीति अपनायी कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए. नरेंद्र मोदी की सभाओं में अपार भीड़ हो रही है. पहली बार नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है कि वो पार्टी के नेता के तौर पर हर जगह मीटिंग कर रहे हैं. इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने राज्य के चुनाव में इतनी सभाएं नहीं की थी. नरेंद्र मोदी बिल्कुल लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाने की रणनीति बनाकर शुद्ध चुनावी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी आलोचना देश में इसलिए हो रही है क्योंकि उनके भाषण से मुद्दे गायब हैं और सिर्फ चुनाव जीतने वाली भाषा धाराप्रवाह निकल रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे बयान दिये, जिनसे ये लगता है कि वो चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं. उनका ये बयान कि अगर गांव में कब्रिस्तान है तो श्मशान भी होना चाहिए. इस बयान को अच्छी नजर से नहीं देखा गया. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिन्दू हैं और वो जानते हैं कि हिन्दुओं का मानना है कि अगर मृत्यु के बाद मोक्ष पाना है या स्वर्ग जाना है तो गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे उनका दाह संस्कार होना चाहिए. अगर दाह संस्कार वहां होता है जहां कब्रिस्तान बना हुआ है तो फिर मोक्ष मिलेगा, इसमें संदेह पैदा हो जाएगा. अगर कब्रिस्तान और श्मशान एक साथ बनाने की उनकी बात मान भी ली जाए तो पूरे देश में जैसे मंदिर-मस्जिद का झगड़ा चलता है, वैसा ही झगड़ा कब्रिस्तान और श्मशान का शुरू हो जाएगा. लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश सहित राज्यों के विकास की एक अलग तस्वीर पेश करेंगे, पर शायद उन्होंने इसे पेश करना उचित नहीं समझा.

उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़ी जातियों का भाजपा के साथ मिलना इस कहावत को चरितार्थ करता है कि बेताल फिर वापस डाल पर चला गया. हर चुनाव की तरह यह चुनाव भी किसी को ये अंदाजा नहीं लगने दे रहा, न आभास होने दे रहा है कि 11 मार्च को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम निकलेंगे तो कौन पार्टी या कौन पार्टियां मिलकर सत्ता में आएंगी.

मेरी समझ से ये स्थिति लोकतंत्र के हित में है. अगर हम अंदाजा लगा लें तो फिर चुनाव की जरूरत ही क्या है. जनता इतनी समझदार हो गयी है कि वो किसी को भी अपने मन में झांकने नहीं देती. अब तक सर्वे एजेंसियां राजनीतिक दलों के हथियार के तौर पर अपने को इस्तेमाल करवाती आई हैं. अब लगता है कि जब 8 मार्च को एक्जिट पोल के नतीजे सामने आयेंगे तब ये तस्वीर अवश्य सामने आएगी, लेकिन अधिकांश सर्वे नतीजे अब तक अंतिम परिणाम से अलग ही दिखाई दिए हैं. मजे की बात है कि सर्वे या एक्जिट पोल करने वाले कभी जनता से क्षमा नहीं मांगते कि उन्होंने उन्हें भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के चुनाव परिणाम आने के बाद देश में एक नयी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें नये सिरे से दलों के बीच बातचीत होगी. बहुत सारे दल जो इस चुनाव में अपना इच्छित स्थान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो 2019 के लिए एक साथ मिलते नजर आएंगे. भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ज्यादा सख्त और तेज भी हो जाएगी और इसकी भी कोशिश करेगी कि किस तरह 2014 का परिणाम 2019 में दिखायी दे.■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे भारतीय राजनीति की दिशा तय करेंगे

परंजय गुहा ठाकुरता

यह कहना बिल्कुल स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर अल्पकालिक तौर पर भारतीय राजनीति पर पड़ेगा. हिंदुस्तान के हर छह लोगों में से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है. अगर यह देश होता तो आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश होता. लेकिन कई बार यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों का असर इन तथ्यों से भी बड़ा रहा है. इन चुनावों के परिप्रेक्ष्य और समय को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर वैसे ही मुहाने पर खड़े हैं.

8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 86 फीसदी नोटों को बंद करने के फैसले के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है. जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है. यहां के नतीजे आंशिक तौर पर ही सही लेकिन नोटबंदी पर जनादेश के तौर पर देखे जाएंगे. अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाती है या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है, तो इसे मोदी के पक्ष में जनादेश कहा जाएगा. इससे मोदी के करिश्माई नेता की छवि मजबूत होगी. उनके राजनैतिक सूझ-बूझ की भी दाद दी जाएगी. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी इसका फायदा मिलेगा. कुल मिलाकर ऐसे नतीजे से प्रधानमंत्री विपक्ष के खिलाफ और मजबूत दिखने लगेंगे और पहले से बेहाल विपक्ष और असहाय दिखने लगेगा.

अगर प्रदेश में भाजपा दूसरे या तीसरे स्थान पर रहती है तो इसे मोदी और शाह के लिए बड़ा झटका माना जाएगा. 2014 लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों के आधार पर भाजपा को 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 328 सीटों पर बढ़त हासिल थी. ऐसे में अगर भाजपा का प्रदर्शन खराब होता है तो इससे पार्टी के अंदर मोदी के विरोधियों को भी नई ताकत मिल सकती है. इस बात पर सवाल उठने शुरू हो सकते हैं कि क्या ऐसे आदमी के हाथों में पार्टी का भविष्य सुरक्षित है, जिसने नोटबंदी जैसा निर्णय लिया. यह भी संभव है कि ज्यादा हमले अमित शाह पर हों, लेकिन इन नतीजों का असर भाजपा से बाहर भी काफी होगा. बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में से जो भी पहले नंबर पर रहेगा, वह इस जीत

> **चुनाव जब दिल्ली में फरवरी 2015 में हुआ तो मुकाबला आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भाजपा की किरण बेदी के बीच था. इसमें बाजी केजरीवाल के हाथ लगी. बिहार में नीतीश कुमार की कामयाबी भी कुछ ऐसी ही थी. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश के खिलाफ भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है.**

को राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा. 2015 के अंत में आए बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद नीतीश कुमार को 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा था. मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में भाजपा को पटखनी देने के बाद अखिलेश यादव या मायावती भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे.

ऐसी स्थिति में यह बात भी चलेगी कि क्या भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर मात देने के लिए बिहार में जिस तरह का महागठबंधन हुआ था, वैसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए. समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में सीमित स्तर पर ही सही, लेकिन एक कोशिश की है. अगर सपा पहले नंबर पर रहती है तो इससे अखिलेश यादव मजबूत होकर उभरेंगे. इससे न सिर्फ यह साबित होगा कि वे परिवार में चले खींचतान का ठीक से सामना कर पाए, बल्कि मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़े रखा. उनकी कम उम्र को देखते हुए उन्हें लंबी रेस का घोड़ा माना जाएगा.

यह कहा जा सकता है कि 2014 का लोकसभा चुनाव पार्टी केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित था. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तरह हुए लोकसभा चुनावों में एक छोर पर नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी. इसमें कामयाबी मोदी को मिली. पर इस तरह के चुनाव दोधारी होते हैं. ऐसा ही चुनाव जब दिल्ली में फरवरी 2015 में हुआ तो मुकाबला आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भाजपा की किरण बेदी के बीच था. इसमें बाजी केजरीवाल के हाथ लगी. बिहार में नीतीश कुमार की कामयाबी भी कुछ ऐसी ही थी. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश के खिलाफ भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है. अगर बसपा जीतती है तो माना जाएगा कि ऐसा मायावती की सियासी ताकत की वजह से हो पाया. अगर अखिलेश अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह माना जाएगा कि पांच साल के शासन के बावजूद उन्होंने सत्ता विरोधी भावनाओं का ठीक से सामना किया. उत्तर प्रदेश के नतीजे यह भी बताएंगे कि वोट बैंक की राजनीति कहां खड़ी है.

सवाल यह भी है कि अगर भाजपा हार जाती है तो क्या इससे 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए बचे हुए दो साल में मोदी और शाह की कार्यशैली में कोई बदलाव आएगा? मोदी ने पहले भी यह साबित किया है कि वे चौंकाने वाले निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है. क्या वे पार्टी और पार्टी के बाहर के अपने विरोधियों के खिलाफ उन्हें शांत करने वाला रवैया अपनाएंगे या फिर वे अपनी आक्रामकता को बरकरार रखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाएंगे. नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन 11 मार्च से भारतीय राजनीति की दिशा बदलेगी.■

(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

लखीसराय: बालू का अवैध धंधा धड़ल्ले से चालू

वैध कंपनी पर भारी खनन माफ़िया

जिले में गठित एसटीएफ टीम यदा-कदा कानूनी रस्म अदायगी के लिए ओवर लोडिंग एवं अवैध बालू खनन को लेकर वाहन चालकों के विरुद्ध छापामारी अभियान भी चलाती है. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य सरकार को इससे करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की बांदा स्थित मेसर्स वेस्ट लिंक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 24 करोड़ 42 लाख 65 हजार रुपये की बोली लगाकर 2016 से 2019 तक जिले की किउल नदी बालू घाटों की आम नीलामी हासिल की है. इस दौरान मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त की निगरानी में 16 जुलाई 2016 को लखीसराय-जमुई एकीकृत यूनिट के बालूघाटों की नीलामी प्रक्रिया का इकरारनामा भी मेसर्स कंपनी के नाम संपन्न हो गया.

एसके गांधी

लखीसराय जिले में बालू माफिया एवं कुछ भ्रष्ट नौकरशाहों के संरक्षण में किउल नदी बालू घाट से बालू के अवैध उत्खनन एवं बिक्री का कार्य परवान पर है. इस दौरान अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित जिलास्तरीय टास्क फोर्स भी इन मामलों में कार्रवाई नहीं कर रही है. फलस्वरूप सुरजीचक से मंझवे तक 18 किलोमीटर लंबी किउल नदी बालू घाट के दोनों साइड में दिन-रात ट्रैक्टरों से बालू की ओवर लोडिंग जारी है. इस क्रम में लखीसराय, चानन एवं रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित सुरजीचक, सलोनाचक, गढ़ी विशनपुर, कबैया, काली पहाड़ी, जयनगर, महिसौना, गोडीह, घोषीकुंडी, मोहनकुंडी, पचाम, खुटुपार, गोहरी, मलिया, इटौन, भलुई, तेतरहट, शर्मा, मंझवे, नोनगढ़ आदि कई स्थानों पर माफिया की दबंगई एवं पुलिसिया मिलीभगत से बालू का अवैध उठाव एवं बिक्री चालू है.

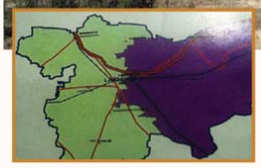

जिले में गठित एसटीएफ टीम यदा-कदा कानूनी रस्म अदायगी के लिए ओवर लोडिंग एवं अवैध बालू खनन को लेकर वाहन चालकों के विरुद्ध छापामारी अभियान भी चलाती है. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य सरकार को इससे करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की बांदा स्थित मेसर्स वेस्ट लिंक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 24 करोड़ 42 लाख 65 हजार रुपये की बोली लगाकर 2016 से 2019 तक जिले की किउल नदी बालू घाटों की आम नीलामी हासिल की है. इस दौरान मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त की देखरेख में 16 जुलाई 2016 को लखीसराय-जमुई एकीकृत यूनिट के बालूघाटों की नीलामी प्रक्रिया का इकरारनामा भी मेसर्स कंपनी के नाम संपन्न हो गया.

इसके पूर्व 2011-15 की बंदोबस्ती राजधानी पटना की मेसर्स राजनंदनी प्रोजक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम था, जिसका समय 31 दिसम्बर 2015 को पूरा हो गया था. इस दौरान 01 जनवरी से 15 जुलाई 2016 तक बालू के धंधों पर रेगिस्तान के बेताज बादशाहों के वर्चस्व की लड़ाई के कारण जिला प्रशासन को दो-तीन बार डाकबोली रद्द करनी पड़ी थी.

बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के कारण कंपनी ने अभी तक बालू उत्खनन एवं उठाव-बिक्री के कार्य शुरू नहीं किए हैं. हालांकि इकरारनामे के अनुसार कंपनी ने 25 फीसदी अग्रिम राशि राजकोष में जमा कर दी है. विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में जारी किए जाने की उम्मीद है. इसके लिए विधायी प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

> **बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के कारण कंपनी ने अभी तक बालू उत्खनन एवं उठाव-बिक्री के कार्य शुरू नहीं किए हैं. हालांकि इकरारनामे के अनुसार कंपनी ने 25 फीसदी अग्रिम राशि राजकोष में जमा कर दी है. विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में जारी किए जाने की उम्मीद है. इसके लिए विधायी प्रक्रिया अंतिम चरण में है.**

इस बीच मेसर्स वेस्ट लिंक ट्रेडिंग कंपनी के निदेशक अतुल सिंह एवं कार्यकारी पदाधिकारी अनूप सिंह ने जिला प्रशासन से किउल नदी बालूघाटों से जारी अवैध उत्खनन पर तत्काल पाबंदी लगाने की गुहार लगाई है. उन्हें उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष से पूर्व पर्यावरण मानकों से संबंधित एनओसी भारत सरकार को देकर जिले में बालू उठाव एवं बिक्री कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो जाएंगे. लेकिन तब तक किउल नदी से चोरी छिपे बालू की बिक्री पर रोक लगाने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है.

इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सूबे के सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को बालू एवं अन्य खनिज संपदा की अवैधानिक खुदाई, उठाव एवं बिक्री पर रोक लगाने को लेकर जिलावार विशेष टास्क फोर्स गठित करने के आदेश जारी किए हैं. इसके बावजूद कोर्ट के आदेश की प्रशासनिक अनदेखी की जा रही है.

जिले में अवैध बालू उठाव एवं बिक्री के कारण आम लोग फिलहाल दो से पांच हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू खरीदने को मजबूर हैं. इसके पूर्व प्रति ट्रैक्टर एक हजार से ढाई हजार रुपये तक बालू उपलब्ध था. इसके चलते कई सरकारी एवं प्राइवेट निर्माण कार्य की लागत में कई गुना वृद्धि हो गई है. वहीं कई बड़ी निर्माणाधीन कार्य परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं और इंदिरा आवास निर्माण भी दिवा स्वप्न साबित हो रहा है.

विदित हो कि जिले में पंजीकृत असंगठित 7368 मजदूरों में से ढाई हजार खनन उद्योग के काम में लगे हैं. इसके चलते इसे लखीसराय की अर्थव्यवस्था का लाइफलाइन भी कहा जाता है. कुल आबादी के 20 फीसदी लोगों के परवरिश का जरिया बालू खनन ही है. बालू माफिया के लिए डायमंड रिवर कहलाने वाली किउल नदी से देखते-देखते इलाके के कई लोग मालामाल हो गए.

1960-70 के दशक में इस धंधे में जिले के धनासेठों एवं रेलवे अधिकारियों का वर्चस्व था. उस वक्त किउल एवं लखीसराय में बालू को रेलवे वैगन से राज्य के बाहर भेजा जाता था. 1980 के दशक तक इस धंधे में बाहुबलियों एवं कई सफेदपोशों का प्रवेश हुआ, जो देखते-देखते एमएलए, एमपी एवं अन्य जनप्रतिनिधि बन गए. इस बीच अफसरशाह एवं व्यवसायी बालू व्यवसाय से बाहर हो गए. इस दौरान बालू के धंधों पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई. किउल नदी बालू के घाटों से लेकर सड़कों पर बालू लदे वाहनों से रंगदारी टैक्स वसूलने का धंधा भी शुरू हुआ.

इस बारे में पूछे जाने पर जिलाधिकारी सुनील कुमार कहते हैं कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय एवं खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश के अनुसार गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स छापेमारी कर धरपकड़ अभियान चला रही है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण सुरक्षा मानकों का भी अक्षरश: अनुपालन किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर वाहनों की जांच कर अवैध बिक्री और ओवरलोडिंग पर हर हाल में पाबंदी लगाई जाएगी. उन्होंने बताया कि 2011-15 तक जिले में खनन राजस्व में तीन गुणा राजस्व की वृद्धि हुई है.

वित्तीय वर्ष 2015-16 में वाहनों की जांच से वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप 50 फीसदी से ज्यादा राजस्व की वसूली की गई. इस दौरान 1000 से ज्यादा वाहनों चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. 2016-17 में भी अपेक्षित खनन राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिला खनन विभाग प्रयासरत है. गौरतलब है कि गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स में प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, एएसपी (अभियान), पर्यावरण संरक्षण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी के अलावा लखीसराय अनुमंडल स्तर के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं.

इसी मामले में एसपी अशोक कुमार ने कहा कि जिले की प्राकृतिक संपदा लूटने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई में जिला पुलिस कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी.

उन्होंने बताया कि अवैध बालू खनन एवं बिक्री रोकने के लिए जिले के एसपी (अभियान) पवन कुमार उपाध्याय एवं प्रभारी खनन एवं भूतत्व सह वरीय उपसमाहर्ता मुकेश कुमार सहित संबंधित थानाध्यक्षों व अन्य अधिकारियों की अगुआई में कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बालू माफिया के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाए जाएंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

गया में जीटी रोड पर

बेख़ौफ़ चल रहा ओवरलोडिंग का धंधा

सुनील सौरभ

पुलिस अधिकारियों के प्रयास के बाद भी बिहार में जीटी रोड राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-2 पर ओवरलोडेड गाड़ियों को पार कराने का धंधा नहीं रुक रहा है. इससे बिहार सरकार को लाखों रुपए रोज राजस्व की क्षति हो रही है. हाल में बिहार पुलिस के अधिकारियों ने जीटी रोड पर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में उनका ही तबादला करा दिया गया या फिर राजनीतिक दबाव डालकर चुप करा दिया गया. पटना प्रक्षेत्र के आईजी नैयर हसनैन खान को जब जीटी रोड पर इंट्री मफिया और पुलिस की मिलीभगत द्वारा प्रतिदिन हजारों ओवरलोडेड वाहन पार कराने की जानकारी मिली, तब उन्होंने कमान खुद संभाल ली. आईजी खान ने गया जिले में एक सप्ताह में करीब एक हजार ओवरलोडेड वाहनों को जब्त कर लिया. इन ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ गया, औरंगाबाद व रोहतास जिले के जीटी रोड स्थित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई और करीब सौ लोगों को जेल भेज दिया गया. आईजी ने इंट्री माफिया से संलिप्तता के आरोप में गया जिले के डोभी, बाराचट्टी, शेरघाटी, आमस, औरंगाबाद जिले के मदनपुर, मुफ्फसिल, बारुण के एसएचओ को निलंबित कर दिया. इस कार्रवाई से राज्य के पुलिस महकमे समेत सभी सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया. डोभी-मोहनियां स्थित समेकित जांच चौकी पर वाणिज्य कर, वन विभाग, खनन विभाग के पदाधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है. इनका काम ओवरलोडेड वाहनों व बिना उचित परमिट व कागजात के किसी भी तरह की सामग्री को लाने-ले जाने पर रोक लगाने और टैक्स वसूलना है. आईजी नैयर हसनैन खान ने जिन वाहनों को पकड़ा, उन पर अवैध बालू, कोयला, पत्थर एवं अन्य सामान लोडेड था. जब्त वाहन बगैर सरकारी राजस्व का भुगतान किए तथा तय से अधिक वजन के साथ जीटी रोड से गंतव्य की ओर जा रहे थे. पुलिस सूत्रों से पता चला कि सभी निलंबित एसएचओ को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था. तय समय सीमा में स्पष्टीकरण नहीं देने पर आईजी ने जीटी रोड के थाने का प्रभार दोबारा नहीं देने का आदेश सभी जिले के पुलिस कप्तान को दिया है. इससे पूर्व 2015 में भी मगध प्रक्षेत्र के तत्कालीन डीआईजी शालीन ने जीटी रोड पर इंट्री माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई थी. लेकिन कुछ दिनों बाद ही डीआईजी शालीन का स्थानांतरण हो गया. चर्चा थी कि इंट्री माफिया के राजनीतिक संरक्षकों ने डीआईजी का तबादला कराया था. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामप्रमोद सिंह ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में आवेदन भी दिया था. इसमें जीटी रोड पर प्रतिदिन तीन करोड़ रुपए राजस्व हानि के अलावा इंट्री माफिया व पुलिस की मिलीभगत की जानकारी दी गई थी.

गया जिले में जीटी रोड स्थित डोभी चेक पोस्ट पर इंट्री माफिया की पकड़ मजबूत है. यहां लगे सभी 24 सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं. नये लगे 30 कैमरे भी अभी काम नहीं कर रहे हैं. चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के लिए प्रतिदिन दो पाली में मजिस्ट्रेट की तैनाती का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस पर भी कोई अमल नहीं हुआ. इसके अलावा परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न मार्गों पर रोजाना चेकिंग की बात हुई थी, लेकिन ये अधिकारी चेकपोस्ट पर ही तैनात रहते हैं. सच्चाई यह है कि स्थानीय राजनीतिज्ञों का भी इन माफिया को समर्थन हासिल है.■

feedback@chauthiduniya.com

बाज़ार में आई पानी की

नई टंकी

क्रेटिया पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी नई और उत्कृष्ट पानी टंकी बाजार में उतारी है. पूर्वोत्तर भारत एवं नेपाल के समक्ष विशेष तकनीक और फूड ग्रेड मेटेरियल से निर्मित पानी टंकी लॉन्च करते हुए कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि भारत के मौसम को देखते हुए इसका निर्माण किया गया है. यह टंकी गर्मी के मौसम में भी पानी को ठंडा व स्वच्छ बनाए रखता है. कंपनी के निदेशक एवं आईआईटियन दुष्यंत पालड़ीवाला ने कहा कि एक साल के अनुसंधान के बाद इस पानी टंकी का निर्माण किया गया है, जो बिल्कुल अलग तरीके का है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला
Call : 95340 95340

मनोज तिवारी

सात सौ पचास एकड़ विवादित ज़मीन पर दख़ल को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प

दियारा बना अखाड़ा

राजेश सिन्हा

नदियों की कोख से निकली जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए खून से लाल होती रही दियारा की धरती एक बार फिर आंदोलित है. एसटीएफ ने कोसी क्षेत्र के कुख्यात अपराधी रामानंद यादव उर्फ रामानंद पहलवान गिरोह के साथ मुठभेड़ में पांच सशस्त्र अपराधियों को पकड़ा है. फसल बुआई के समय अक्सर सुलगने वाली कोसी में फिलहाल शांति है, लेकिन भागलपुर-खगड़िया का दियारा इन दिनों अपराधियों का अखाड़ा बन गया है. दियारे की जमीन पर कब्जे को लेकर आपराधिक गुटों के बीच जारी गोलीबारी से इलाका दहल रहा है. इस क्षेत्र में पुश्तैनी जमीन पर खेती करने वाले किसान भी अपने खेत की ओर ताकना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं. इस जमीनी विवाद की पृष्ठभूमि भागलपुर के तत्कालीन अपर समाहर्ता द्वारा साठ के दशक में तैयार की गई थी. गंगा की गर्भ में पलने वाली सात सौ पचास एकड़ जमीन का न केवल सर्वे कर दिया गया, बल्कि दो-दो पक्षों के नाम मालगुजारी रसीद भी जारी कर दी गई. कोसी के साथ भागलपुर पुलिस भी इस बात से वाकिफ है कि दियारा में विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है. इस क्षेत्र में एक पखवाड़े से रुक-रुक कर हो रही गोलीबारी के बीच कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हालात बिगड़ने के आसार बने हैं. पुलिस प्रशासन भौगोलिक स्थिति से अनजान होने के कारण या फिर अपराधियों के राजनीतिक संरक्षण के कारण इन इलाकों में जाने से परहेज करती है.

दरअसल, यहां सात सौ पचास एकड़ जमीन का भागलपुर के तत्कालीन समाहर्ता द्वारा न केवल गलत सर्वे किया गया, बल्कि दो अलग-अलग पक्ष के किसानों के नाम रसीद भी काट दिया गया. नतीजतन पहले से जमीन पर कब्जा जमाए किसानों का कहना है कि जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे. खगड़िया जिले के दक्षिणी छोर पर तीन ओर से गंगा नदी से घिरे परबत्ता प्रखंड अंतर्गत कुल्हड़िया, भरसों तथा लगार पंचायत के सैकड़ों किसान परेशान हैं. उनकी चिंता का मुख्य कारण है तीनों पंचायत की सीमा से सटे भागलपुर के थाना बिहपुर स्थित मौजा शंकरपुर की सात सौ पचास एकड़ जमीन को लेकर उत्पन्न तनाव. 1960 में जब पूरे बिहार में जमीन का सर्वे हुआ था, तब भौगोलिक बनावट और गंगा नदी में इस मौजे की जमीन के डूबे रहने के कारण सर्वे नहीं हो सका था. 1909 की कबूलियत के आधार पर किसान इस जमीन पर जोत करने लगे. जमींदारी उन्मूलन के बाद भागलपुर के तत्कालीन समाहर्ता ने 1959-60 में अपने स्तर पर जमीन का सर्वे कराया. 1964 में प्रकाशित सर्वे में कई गड़बड़ियां सामने आईं. पता चला कि जमीनी स्तर पर सर्वे कराने के बजाय समाहर्ता के टेबल पर ही जमीन का सर्वे करा लिया गया. सलारपुर के किसान महेन्द्र यादव का कहना है कि उक्त मौजे की जमीन 1951 से लेकर 1971 तक गंगा में डूबी थी, इसलिए 1960 के सर्वे को वैधानिक नहीं माना जा सकता है. पहले का नक्शा भी किसान की दलील को पुख्ता

करता है. सर्वे को लेकर बिशौनी निवासी तथा आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक यदुनंदन झा ने विधानसभा में मामला उठाया. सर्वे रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने 24 नवम्बर 1965 को अधिसूचना जारी कर शीघ्र सर्वे कराने पर जोर दिया.

इससे पूर्व 1979 में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सरकार के उपसचिव सच्चिदानंद प्रसाद ने सभी आयुक्तों तथा समाहर्ता के नाम प्रेषित पत्र में स्पष्ट कहा कि यदि जमीन की पहचान समाप्त नहीं होती है, तो बिहार काश्तकार अधिनियम की धारा 52 ए के अनुसार ऐसी जमीन पुराने रैयतों की ही मानी जाएगी. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में 150 किसान जमीन की लगान रसीद कटाने लगे. लेकिन 2008 में बिहपुर के अंचल अधिकारी ने यह कहकर उन किसानों के नाम रसीद काटने से मना कर दिया कि 1960 में हुए सर्वे के आधार पर आलमनगर के पूर्व विधायक यदुनंदन झा के पुत्र उमेश चन्द्र झा समेत ग्यारह भूधारियों के नाम दाखिल-खारिज कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है. इस तरह वर्षों से लगान रसीद कटाकर खेती करने वाले 150 किसान और 1960 के सर्वे के आधार पर दाखिल-खारिज का रसीद कटाकर ग्यारह बड़े भूधारी अब आमने-सामने आ गए हैं. 750 एकड़ भूमि पर दखल को लेकर कई बार छिटपुट हिंसा हो चुकी है. इसके बाद कई किसानों ने पटना उच्च न्यायालय में 1960 में कराए गए सर्वे को चुनौती दी. न्यायाधीश ने इस सर्वे को अवैध करार देकर याचिकाकर्ता को पूर्ण सर्वे के लिए उचित स्तर पर आवेदन देने को कहा. भागलपुर के समाहर्ता ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को पत्र भेजकर बताया कि फिलहाल उक्त मौजे की जमीन पर जमींदारी उन्मूलन के बाद तैयार की गई जमाबंदी से रसीद काटना बंद कर दिया गया है. 1964 में प्रकाशित सर्वे रिपोर्ट व तैयार खतियान के आधार पर मालगुजारी रसीद काटी जा रही है. नतीजतन भूमि विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है. इसलिए भागलपुर के गंगा दियारा क्षेत्र का वृहत सर्वेक्षण के बावत कार्रवाई करने का आदेश दिया जाय. इस बीच भागलपुर के अपर समाहर्ता ने 150 किसानों के पक्ष में आदेश देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. भागलपुर के समाहर्ता द्वारा नए सर्वे की मांग पर भू अभिलेख विभाग के निदेशक ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा आधुनिक तकनीक से सर्वे कराने की प्रक्रिया जारी है. सर्वे कराने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है. तब तक रिविजनल सर्वे के अभिलेख से काम चलाया जाय. वहीं किसानों का कहना है कि इस इलाके में कभी रिविजनल सर्वे हुआ ही नहीं. बहरहाल, स्थिति यह है कि 750 एकड़ जमीन के अलग-अलग दावेदार एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने के लिए कमर कस चुके हैं. एक पक्ष के किसान 1954 से 2008 तक की लगान रसीद लेकर दूसरे पक्ष से भिड़ने को तैयार हैं, तो दूसरे पक्ष के लोग 1975 से लगान रसीद दिखा रहे हैं. ऐसा कर अधिकारियों ने नरसंहार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है. दूसरे पक्ष के अहम पक्षकार पूर्व विधायक यदुनंदन झा के परिजनों का कहना है कि उक्त जमीन पर 1970 तक उनलोगों का कब्जा रहा. वर्ष 2000 में 1960 के सर्वे के आधार पर उनलोगों द्वारा मोटेशन कराया गया था. अब भी आधे जमीन पर उनलोगों का ही कब्जा है.

इधर खगड़िया के जिलाधिकारी जय सिंह कहते हैं कि जमीनी विवाद सुलझाने में अधिकारी लगे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस जमीनी विवाद को सुलझाना भागलपुर जिला प्रशासन का कर्तव्य है.■

लाश पड़ी रही, अमीन ने सुलझाया सीमा विवाद

था ना पुलिस घटनास्थल को अपने थाना क्षेत्र से बाहर बताकर पल्ला झाड़ लेती है. बीते 18 अप्रैल को खगड़िया जिले में मौजा शंकरपुर गोसायदास दियारा में भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड निवासी 18 वर्षीय कूलो यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही परबत्ता थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार मौका-ए-वारदात पर पहुंचे जरूर, लेकिन लोकेशन भागलपुर जिला होने के कारण पड़ोसी थाना बिहपुर को सूचना दी गई. हास्यास्पद स्थिति तब हो गई जब बिहपुर थाना पुलिस इसे खगड़िया जिला पुलिस का मामला बताकर बैरंग लौट गई. सीमा क्षेत्र का विवाद सुलझाने के लिए अमीन तक को बुलाना पड़ गया. इसके बाद अगले दिन परबत्ता प्रखंड के अंचलाधिकारी शैलेंद्र कुमार तथा भागलपुर जिले के नारायणपुर से पहुंचे सीओ विनोद कुमार की मौजूदगी में अमीन द्वारा जमीन की मापी की गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजना तक गंवारा नहीं समझा. लाश की पहरेदारी के लिए गृहरक्षक जवान तैनात कर दिए गए. आखिर में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस से यह प्रमाणित हो सका कि घटनास्थल भागलपुर जिला पुलिस के अधीन है.■

feedback@chauthiduniya.com

वीर कुंवर सिंह और धरमन बाई के प्रेम प्रसंग पर ख़ामोश हैं इतिहासकार

अफ़साना जो ना बन सका इतिहास

राणा अवधूत कुमार

सन् 1857 में छिड़े प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वाधीनता सेनानियों में से एक अति महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह. इसके अलावा उनके साथ एक ऐसी कहानी भी जुड़ी है, जिसे इतिहास में मुकम्मल स्थान नहीं मिल सका है. यह अफसाना जुड़ा था जगदीशपुर, आरा की धरमन बाई नाम की एक बेहद खूबसूरत नर्तकी के साथ. इस्लाम धर्म को शिद्दत से मानने वाली धरमन बाई पेशे से तो बेशक एक तवायफ थी, लेकिन उसमें राष्ट्रीयता और देशप्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी थी.

लोक मानस में किस्से के रूप में मशहूर इस प्रेम कहानी का कई जगहों एवं खास स्थानों पर जिक्र है. बिहार के कुछ इतिहासकार बताते हैं कि एक बार जब सार्वजनिक मुजरे के कार्यक्रम में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने बाबू कुंवर सिंह की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, तो धरमन ने सभी के सामने न सिर्फ बाबू कुंवर सिंह का भरपूर पक्ष लिया बल्कि सार्वजनिक रूप से उनकी बहादुरी, शौर्य और वीरता का बखान भी किया. इस प्रकरण के बाद कुंवर सिंह का धरमन के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ गया था.

बाद में तो धरमन बाबू कुंवर सिंह की विश्वस्त सहयोगी के साथ ही उनकी जीवनसंगिनी भी बन गयी थी. कई इतिहासकार बताते हैं कि मुजरे वाली यह घटना पटना में हुई थी और अब वह जगह पटना के बांकीपुर क्लब के नाम से मशहूर है. बांकीपुर की इस घटना का जिक्र बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की किताबों में भी दर्ज है. सवाल है कि इस प्रेम कहानी को सामाजिक मान्यता क्यों नहीं मिली?

1857 के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास गवाह है कि धरमन बाई एक नर्तकी होने के बावजूद बाबू कुंवर सिंह के साथ कई ऐतिहासिक लड़ाइयों में शामिल रहीं. यही नहीं, धरमन बाई ने अपने जीवन की सारी कमाई बाबू कुंवर सिंह को दान में दे दी थी, ताकि वे अंग्रेजों के खिलाफ कारगर तरीके से लड़ सकें. बाद में धरमन ने जीवनसंगिनी बनकर बाबू कुंवर सिंह को नैतिक सहारा भी दिया था, लेकिन इस ऐतिहासिक सच पर आज भी पर्दा पड़ा है. कुंवर सिंह को लेकर हजारों लोक आख्यान हैं, किंवदंतियां हैं, लेकिन धरमन बीवी का नाम शायद ही कहीं मिले. ऐसा आखिर क्यों है? केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन

वीर कुंवर सिंह

विभाग की '1857 के अमर सेनानी' नामक श्रृंखला के तहत आई किताब में अब जाकर स्वीकार किया गया है कि धरमन बीबी बाबू कुंवर सिंह की दूसरी पत्नी थीं. इस पुस्तक की लेखिका प्रसिद्ध इतिहासकार रश्मि चौधरी हैं, जिन्होंने अपनी किताब में बाबू कुंवर सिंह एवं धरमन बीबी के प्रेम प्रसंग को उकेरा है. भोजपुर जिला, ऐतिहासिक शहर आरा, ग्रामीण क्षेत्रों और गंवई जनमानस में प्रचलित किस्सों के अनुसार जगदीशपुर और बीबीगंज में धरमन बाई अंग्रेजों के खिलाफ बाबू कुंवर सिंह का भरपूर साथ देती थीं.

कुंवर सिंह को अंग्रेजों की फौज की खुफिया रिपोर्ट देने, उनसे बचाने और युद्ध के दौरान भोजपुर को सुरक्षित बचाये रखने के लिए रात-रात भर मोर्चे पर अकेले लड़ती रहीं. एक नर्तकी से कहीं ज्यादा वह अपने मुल्क के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वीरांगना थी. क्या एक स्वतंत्रता सेनानी को इस तरह गुमनामी में रखना देश के गौरवपूर्ण अतीत के लिए उचित है? आरा, जगदीशपुर और कई अन्य गांवों में भी बाबू कुंवर सिंह के साथ और अकेले भी गोरों के खिलाफ छापामार युद्ध करने के प्रमाण मिलते हैं. भोजपुर मुख्यालय, आरा शहर का धरमन चौक, करमन टोला और धरमन मस्जिद अपने आप में धरमन की कहानी बयां कर रहा है. आरा और जगदीशपुर स्थित धरमन मस्जिद के अलावा धरमन का घर, इस बात के पक्के सबूत हैं कि धरमन से कुंवर सिंह की किस हद तक नजदीकियां थीं. आरा शहर के करमन टोले के बारे में कहावत है कि करमन धरमन की छोटी बहन थी, धरमन बीबी के आग्रह पर बाबू साहब ने आरा में करमन टोले को स्थापित किया था.■

feedback@chauthiduniya.com

नेताओं की अनाप-शनाप बयानबाज़ियों में ही गुजर गया विधानसभा चुनाव

जनता की झोली में बोली

सियासत इतनी गिरी कि बे-ईमान हो गई/ यूपी में बिजली भी हिंदू मुसलमान हो गई/लोकतंत्र तो भइया तबेला हो गया/ सियासत में गधों पर झमेला हो गया

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नेताओं की अनापशनाप बयानबाजियों में निपट गया. न कोई मुद्दा सामने आया, न कोई ठोस योजना सामने आई. लोगों को घूस का प्रलोभन देकर वोट हासिल करने की मनोवृत्ति खुल कर अभिव्यक्त हुई. स्थानीय भाषा में कहें तो यूपी का चुनाव नेताओं के अल्ल-बल्ल-सल्ल में निपट गया. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किए, लेकिन बसपा का घोषणा पत्र नहीं आया. घोषणा पत्र में भी मुद्दे कम और घूस का प्रलोभन अधिक था. लोगों को मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त स्मार्ट फोन, मुफ्त प्रेशर कूकर, 25 रुपए किलो देसी घी और सस्ती दरों पर बिजली-पानी देने जैसे वायदे तो शामिल हुए, लेकिन व्यापक नीतियों पर आधारित कार्यक्रमों का अभाव रहा. कोई भी दल अपने चुनाव प्रचार अभियान में उत्तर प्रदेश के बुनियादी मुद्दों का जिक्र नहीं कर रहा, जिक्र कर भी रहा तो उसमें समस्या के निपटारे की कम दूसरे पर प्रहार करने की मंशा अधिक जाहिर हुई. बिजली पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई तो वह हिंदू-मुसलमान में बंट गई और बाँखलाए अखिलेश यादव गुजरात के गधों की चर्चा के स्तर पर आ गए. इस चुनाव में राजनीति ने अपना स्तर खोने का भी रिकॉर्ड ही बनाया. किसी ने खूब कहा, सियासत इतनी गिरी कि बे-ईमान हो गई / यूपी में बिजली भी हिंदू मुसलमान हो गई / लोकतंत्र तो भइया तबेला हो गया / सियासत में गधों पर झमेला हो गया...

उत्तर प्रदेश की समस्याएं बड़ी और जटिल हैं, लेकिन चुनाव अभियान के दौरान नारे, जुमले और आरोप-प्रत्यारोप के शोर में इस राज्य के सारे बुनियादी मसले ताक पर चले गए. तकरीबन 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में घनघोर आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेती, कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर सवाल सामने खड़े हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के चुनाव-प्रचार में इन सवालों को कायदे से तरजीह नहीं मिली. अगर किसी ने इनका जिक्र भी किया तो बेहद सतही अंदाज में. सपा-कांग्रेस गठबंधन समेत सभी दल अपनी रैलियों और सभाओं में जुटी और जुटाई गई भीड़ को अपनी लोकप्रियता का पैमाना मानकर मस्त रहे. नेताओं के छिछले और निम्नस्तरीय कटाक्षों की होड़ लगी रही. मुद्दों की चर्चा करने के नाम पर सारे नेता असंगत बातें करते रहे. नोटबंदी से लेकर कानून व्यवस्था और सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर कब्रिस्तान और श्मशान तक के मसले केवल राजनीतिक जुमलेबाजियों से ही अभिव्यक्त हुए. यह मुद्दा नहीं बना. किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था, कृषि, किसानों की बदहाली, बीमार स्वास्थ्य सेवा और सड़ियल शिक्षा व्यवस्था के सुधार के उनके पास क्या उपाय हैं. चुनाव प्रचार में जिस भी नेता को देखें, वह व्यक्तिगत आक्षेपों और व्यक्तिपरक तुलना में ही लगा रहा. एक केंद्रीय मंत्री ने यह जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग की विशाल संभावनाएं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से ऐसी कोई ठोस योजना सामने नहीं रखी, जो उन संभावनाओं को पुख्ता करने की बात कहती हो. उत्तर प्रदेश का वस्त्र, मूर्ति, लकड़ी, पीतल, पत्थर, कालीन, दरी जैसे लघु उद्योगों का भट्ठा बैठता जा रहा है, लेकिन इस पर किसी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं है. लघु, कुटीर और सूक्ष्म उद्योग से जुड़े लोगों को भीषण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जब यूपी में छोटे उद्योग धंधे ही मार खा रहे हैं, तब आईटी, बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन विकास की बड़ी-बड़ी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है. हालांकि इनके बारे में इस चुनाव में किसी भी नेता ने कोई ठोस बात नहीं की.

उद्योग धंधों की सबसे बड़ी परेशानी बिजली है. आजादी के इतने वर्षों बाद भी उत्तर प्रदेश के ढेर सारे गांव और कस्बे बिजली के बिना हैं, तो विकास को लेकर की जा रही बड़ी-बड़ी बयानबाजियों का बेमानीपन समझ में आता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली के मसले पर हाथ रखा तो परस्पर हमले शुरू हो गए. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनारस में 24 घंटे बिजली सप्लाई होने की बात कहने लगे तो योगी आदित्यनाथ ने यह कह कर पोल खोल दी कि बनारस के मशहूर काशी-विश्वनाथ मंदिर में चार घंटे से अधिक नियमित बिजली नहीं दी जाती. इसी तरह देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है जबकि महादेवा में चार घंटे बिजली मिलती है. पर्व-त्यौहार पर बिजली में धार्मिक भेदभाव किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में यह बात कही थी. इस पर अखिलेश ने बौखला कर गुजरात के गधों पर बात शुरू कर दी और राजनीति के स्तर को काफी नीचे ले गए. मुख्यमंत्री के बयानों की असलियत यही है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली-अमेठी के कुछ गांवों में आज भी बच्चे लालटेन की रौशनी में पढ़ते हैं और महिलाएं मिट्टी के तेल की ढिबरी की रौशनी में खाना पकाती हैं. इसी तरह मुख्यमंत्री अखिलेश के ग्रामीण जनपद इटावा और मुलायम परिवार के गढ़ मैनपुरी के कई गांव अंधेरे में रहते हैं. अमेठी जिले के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर के तहत आने वाले ग्रामसभा कठोरा के मेड़ाई लोध का पुरवा गांव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत खंभे खड़े कर तार दौड़ा दिया गया था, लेकिन बिजली नहीं दौड़ी. बिजली कनेक्शन के लिए गांव के लोगों ने शुल्क भी जमा कर दिए थे और मीटर भी लगा दिया गया, लेकिन बिजली नहीं आई. बिजली के खंभे, तार और घरों में लगे मीटर दर्शनीय सामग्री बन कर रह गए. कोई नेता यह नहीं कह पाया कि वे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे. हालांकि सपा और भाजपा दोनों ने अपने घोषणा पत्र में अधिक बिजली देने की बात कही है, लेकिन बिजली का उत्पादन और उपलब्धता बड़ा सवाल है. सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि शहरों के साथ ही अब गांवों को भी 24 घंटे बिजली देंगे. भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में सरकार बनने पर गांव और शहर दोनों में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है. असलियत यह है कि हर बार चुनाव से पहले नेताओं को बिजली की याद आती है और चुनाव के बाद वे इसे भूल जाते हैं. मुलायम के प्रभावक्षेत्र मैनपुरी के ही लोग कहते हैं कि बिजली दो से चार घंटे ही मिलती है, इसमें क्या काम होगा.

यूपी में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों ने मुख्यमंत्री के सामने ही बिजली और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश में कारोबारी माहौल नहीं है. सरकार बड़ी-बड़ी योजनाओं और अनेक सुधार कार्यक्रमों की घोषणा करती है पर लाल फीताशाही के कारण वे मुश्किल से जमीन पर पहुंचते हैं. सरकार की तमाम योजनाओं की प्रगति भी बहुत धीमी है. कई योजनाओं का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर ही है. ऐसा लगता है कि योजनाओं की समीक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है या फिर सरकारी काम की निगरानी का तंत्र ऐसा होता है जिसकी खुद निगरानी की जरूरत है.

उस बैठक में अधिकारियों को चुस्त और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए और बस इतिश्री हो गई. सारे सख्त निर्देश ढाक के तीन पात होकर रह गए और विकास वहीं

(शेष पृष्ठ 13 पर)

हमेशा पराजित ही होता रहा है बुंदेलखंड

लोकसभा या विधानसभा चुनाव अपने अंतराल पर होते ही रहते हैं. सांसद और विधायक चुनते ही रहे हैं. केंद्र से लेकर प्रदेश में किसी न किसी पार्टी की सत्ता बनती ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड कभी नहीं जीतता. उसे नोच-नोच कर खाने वाले नेता जीत-जीत कर सत्ता का उपभोग करते रहते हैं. यह सवाल भले ही बुंदेलखंड के माहौल में तिर रहे हों कि चुनाव के बाद सत्ता में बुंदेलखंड की भागीदारी क्या होगी या जो सरकार बनेगी वह बुंदेलखंड की सुध लेगी भी या नहीं? बुंदेलखंड के अनुभव उन सवालों का जवाब खुद ब खुद दे देते हैं. उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के सात जिलों बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर की कुल 19 सीटों में से पांच सीटें सुरक्षित श्रेणी में हैं. इनमें बांदा की नरैनी, हमीरपुर की राठ, जालौन की उरई सदर, ललितपुर की महरौनी और झांसी की मऊरानीपुर सीट शामिल हैं. इसी चुनावी माहौल और नेताओं की बयानबाजियों के बरक्स स्वराज अभियान के 2015 के उस सर्वे का स्मरण करते चलें, जिसमें यह कहा गया था कि बुंदेलखंड के 53 प्रतिशत गरीब परिवारों ने पिछले आठ महीने से दाल नहीं खाई थी. 69 प्रतिशत लोगों ने दूध नहीं पिया था और हर पांचवां परिवार कम से कम एक दिन भूखा सोने पर विवश हुआ था. उस साल (2015) की होली के बाद से 60 प्रतिशत परिवारों ने गेहूं-चावल की जगह मोटे अनाज और आलू से भूख मिटाई और हर छठे घर ने फिकारा (एक घास) की रोटी खाई. उस अवधि में बुंदेलखंड में 40 प्रतिशत परिवारों ने अपने पालतू पशु बेच डाले. 27 प्रतिशत ने जमीन बेच दी या गिरवी रख दी और 36 प्रतिशत गांव में सौ से अधिक गाय-भैंसें चारे की कमी के कारण लावारिस छोड़ दी गईं. इस सार्वजनिक जानकारी के बावजूद कोई राजनीतिक दल और उसका नेता विकास की बेशर्म घोषणाएं करता है तो लोकतंत्र की घुटी हुई चीख पूरे बुंदेलखंड में सुनाई पड़ती है. ■

पृष्ठ 12 का शेष

का वहीं ठहर गया. आंकड़ा विश्लेषक कंपनी फोर्थलायन टेक्नोलॉजीज के एक सर्वेक्षण में भी यह बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती सबसे बड़ा मुद्दा है. यूपी के करीब 20 फीसदी लोगों ने रोजगार, अर्थव्यवस्था और विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 10 फीसदी लोगों ने कहा कि साफ पानी की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए बिजली को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने वाले घरों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि साल 2016 के अंत तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के 1,77,000 घरों में बिजली नहीं थी. मार्च 2014 में इसकी संख्या 1,85,900 थी. सर्वेक्षण में यह बात उभरी कि जिन घरों में बिजली है, उन्हें भी बिजली नहीं मिल पा रही है. इसी तरह यूपी के लोगों के लिए सड़क, भोजन, नोटबंदी, अपराध, भ्रष्टाचार, कृषि, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी मुद्दे हैं. रोजगार बड़ा मुद्दा है. श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कामगार आबादी की संख्या 2009 से 2015 के बीच प्रति 1,000 व्यक्ति पर 82 से घटकर 52 रह गई. बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है. 2015-16 में 18-29 के उम्र वर्ग में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर बेरोजगारों की संख्या 148 थी.

देश को कई प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश विकास के केवल नारे ही सुनता रहा है. विकास की गति यूपी में मंद है, जबकि विकास पर बयानबाजी की गति बहुत तेज. प्रत्येक चुनाव में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बातें कही जाती रही हैं, चाहे वह मुलायम रहे हों या अखिलेश, उत्तर प्रदेश कभी उत्तम प्रदेश नहीं ही बन पाया. वर्ष 2007 में मायावती आईं तो पूरे पांच साल स्मारकों, पार्कों और मूर्तियों के निर्माण में ही उलझी रह गईं. इसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई. लेकिन अखिलेश शासनकाल की भी अधिकांश योजनाएं अधर में ही लटकी रह गईं. आप याद करें, अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के विकास का जो

उत्तराखंड में भी जुमलों और नारों में दब गए जरूरी मसले

छोटे से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भी यही हुआ. सारे जरूरी मसले जुमलों, नारों और आपसी सिर-फुटौव्वल में ही गौण रह गए. किसी भी पार्टी या नेता ने पर्वत प्रदेश के बुनियादी मसलों पर हाथ नहीं रखा. उत्तराखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया या उस दौर में चलें तो याद आएगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन दरअसल आरक्षण के विरोध में खड़ा हुआ था जो बाद में पृथक राज्य के आंदोलन में बदल गया. राज्य बनने से पहले यहां के लोगों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता था क्योंकि लखनऊ दूर होने के कारण उत्तर प्रदेश में होने वाले विकास का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था. पहाड़ के लोगों को लगता था कि इसे समझे बिना लखनऊ में बैठकर पहाड़ के लिए योजनाएं बना दी जाती हैं, जिनका पहाड़ को कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता है. लेकिन जब पहाड़ में खुद की सरकार बन गई, तब भी सरकारों का रवैया वैसा ही रहा जैसा लखनऊ में रहता था. पृथक राज्य बनने के बाद जिन स्थितियों में सुधार आना था वह अब भी जस की तस हैं. उत्तराखंड बनने के बाद लोग चाहते थे कि उत्तराखंड की जमीन पर उनका अधिकार होगा. वे चाहते थे कि भूमि सुधार पर काम हो और सरकार चकबंदी लागू करे. लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध हों. लेकिन कुछ बड़ी सियासी ताकतों के कारण सब ठप्प ही रहा. आज पहाड़ के लोगों को लगता है कि पृथक राज्य बनाने के नाम पर उन्हें ठग लिया गया. भ्रष्टाचार चरम पर है और गरीबी व बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होने के बजाय उपेक्षित रह गई. चकबंदी पर भी कोई काम नहीं हुआ. आज जल, जंगल और जमीन का बंदोबस्त निजी हाथों में जाता जा रहा है और इन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है. जबकि जल, जंगल, जमीन जैसे स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय जनता का अधिकार होना चाहिए था, जिससे गांव से लेकर राज्य तक का विकास होता. अंग्रेजों की तरह यहां की सरकार ने भी जंगलों से आम नागरिक का अधिकार छीन लिया. पहाड़ के मूल निवासी जंगलों से जुड़े रहे हैं, उनका पूरा रोजगार जंगल से जुड़ा रहा है, वे यहां पशुपालन करते रहे हैं और फिर उन पशुओं के माध्यम से दूध, ऊन और कपड़े वगैरह प्राप्त करने के साथ-साथ उन जानवरों की मदद से अपनी खेती का व्यवसाय भी करते रहे हैं. लेकिन सरकार ने लोगों को यह अधिकार देने के बजाय उसे अपनी ही कमाई का जरिया बना लिया.

साधारण नागरिक को वनों का प्रयोग करने की इजाजत नहीं है. कोई लकड़ी नहीं काट सकता. पहाड़ पूरी दुनिया को लकड़ी दे रहा है, लेकिन खुद यहां के लोगों की जरूरत के लिए लकड़ियों का अभाव है. उत्तराखंड में पहले ही जमीन का अभाव था. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पौड़ी की सम्पूर्ण जमीन में 67 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल है, बची जमीन पर खेती होती है. कुछ जमीन बंजर है और शेष 2-3 प्रतिशत जमीन पर लोग रहते हैं. लोगों के पास पहले से ही जमीन की कमी थी और ऊपर से जंगलों को सुरक्षित रखने के नाम पर लोगों से उनका रोजगार भी छीना जा रहा है. ऐसे में पहाड़ में एक और समानान्तर आंदोलन सुगबुगा रहा है. आज हालत यह है कि उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन पर बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ गया है. श्रम की स्थिति चिंताजनक है. एक रिपोर्ट कहती है कि महज तीन साल में 5339 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र विकास के नाम पर बलि चढ़ा दिए गए और करोड़ों की आर्थिक हानि हुई. दूसरी तरफ जंगल के मूल निवासियों को वन संरक्षण के नाम पर बेदखल किया जा रहा है. वनों के घटने के कारण हर साल वर्षा के दिनों में, भूस्खलन, बाढ़ वगैरह से करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है. 2013 में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से 5700 यात्रियों की मौत हुई थी और प्रभावित पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के टूटने, दुकानों और होटलों के नदी में बहने के कारण भी राज्य में भारी जान-माल की क्षति हुई थी. आपदा में 9510 पशुओं की जानें गई थीं, 175 पुल, 1307 सड़कें, 4207 घर और 649 पशुघर नष्ट हुए थे. इसके अतिरिक्त फसलों का भी भारी नुकसान हुआ था. आपदाओं के बढ़ने का मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है. अधिक धन कमाने के लिए वन माफियाओं द्वारा दुर्लभ जड़ी-बूटियों और लकड़ी की तस्करी के लिए पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है. इसके अलावा पर्यावरण संतुलन के मापदंडों की अवहेलना और अवैध निर्माण कार्यों से वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं. लेकिन सरकारें या राजनीतिक दलों के लिए यह चिंता का विषय नहीं हैं.

उत्तराखंड में एक तरफ देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर जैसे मैदानी जिले आते हैं तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौड़ागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल पर्वतीय जिले आते हैं. उत्तराखंड अपनी अलग-अलग

भौगोलिक स्थितियों के कारण अलग-अलग किस्म की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है. इन चुनौतियों के प्रति राजनीतिक दलों और नेताओं की बेरुखी के कारण लोगों में काफी असंतोष है. विभिन्न सरकारों ने तमाम दावों और लोगों की बुनियादी जरूरतों की जानकारी होने के बावजूद उसे पूरा नहीं किया. हिमालय के बर्फ के ग्लेशियर केवल हिमालयी राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिए जीवन देने का काम करते हैं. इन ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां पर्यावरण संतुलन बनाए रखती हैं. भारत की कृषि, वन, पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओं का अस्तित्व इन्हीं नदियों के कारण है. ग्लेशियर नहीं होंगे तो देश रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा. राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि इस संवेदनशीलता को समझ ही नहीं पा रहे हैं. उत्तराखंड संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमांत प्रदेश भी है, इसकी अनदेखी भारत के लिए न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है. उत्तराखंड में भ्रष्टाचार में लिप्त जनप्रतिनिधियों, पूंजीपतियों और ठेकेदारों ने सरकारी तंत्र से मिलीभगत कर प्रकृति का घोर अनैतिक दोहन किया है. बारूदी विस्फोटों से सड़कें, भवन और सुरंगों का निर्माण पहाड़ी जिलों के लिए विनाशक साबित हुआ है. पहाड़ छलनी होकर दरक रहे हैं, इस वजह से बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं आम हो गई हैं और उत्तराखंड की जनता को बड़ी-बड़ी त्रासदियां झेलनी पड़ती हैं. आजीविका और रोजगार के लिए स्थानीय लोगों का पलायन भी भीषण असंतुलन पैदा कर रहा है. उत्तराखंड का विकास प्राकृतिक संतुलन के साथ-साथ जन-हितकारी दृष्टिकोण से होना चाहिए. इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर मूलभूत सुविधाएं और रोजगार दिया जाना आवश्यक है. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में छोटे-छोटे गांव हैं, उस पर पलायन के कारण परिवारों की संख्या बहुत कम रह गई है. ऐसे में प्रत्येक गांव में शिक्षा, चिकित्सा और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना मुश्किल है. इसलिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर विकास का प्रारूप खड़ा किया जाना चाहिए. उत्तराखंड में कुल 670 न्याय पंचायतें हैं, जिसमें एक न्याय पंचायत के अंतर्गत 10 से 15 ग्राम पंचायतें आती हैं. स्थानीय जनता और कर्मचारियों को पर्यावरणीय संतुलित मूलभूत सुविधाएं और रोजगार के साधन न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाने होंगे.

प्रदेश के सबसे अच्छी प्रतिभा वाले शिक्षक सबसे अधिक संख्या में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि सरकारी शिक्षा को लगभग फेल करार किया जा रहा है. सरकारी स्कूल केवल गरीब वर्ग के बच्चों के लिए ही पढ़ाई का जरिया बने हुए हैं. निजी स्कूलों की चांदी है. इसमें नेताओं, नौकरशाहों और शिक्षा माफियाओं का गठजोड़ काम कर रहा है. सम्पूर्ण शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है. उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है. आयुष के नाम पर सरकार जनता को धोखा दे रही है. सुविधाओं और रोजगार की तलाश में उत्तराखंड से लोगों का पलायन लगातार जारी है. पलायन रोकने के लिए रोजगार का ढांचा न्याय पंचायत स्तर पर खड़ा किया जाना जरूरी है.

उत्तराखंड में सड़कों के मौजूदा स्वरूप से सुविधा कम और नुकसान अधिक हो रहा है. कई क्षेत्र अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं. दूसरी तरफ सड़क बनाने के तरीके पुरातन और नुकसानदायक हैं. सड़क बनाने के तौर-तरीके से उत्तराखंड में बहुत तबाही हो रही है. उत्तराखंड राज्य बने इतना असा हो गया, लेकिन आज भी यहां सड़क निर्माण रोड मैपिंग के आधार पर नहीं किया जाता. निर्माण कार्यों में स्टोन कटर तकनीक का इस्तेमाल करने के बजाय विस्फोटकों का इस्तेमाल जमकर हो रहा है और मलबा पहाड़ों से नीचे गिरा दिया जाता है. मलबा नीचे आने से नदी का प्रवाह बाधित होता है और जहां नदी नहीं, वहां पेड़-पौधों को भारी नुकसान पहुंचता है. दूसरी तरफ नदियों का पानी ऊपर पहुंचाने का कोई ठोस तकनीक लागू नहीं किया जा रहा. जंगलों में आग भी पर्वतीय प्रदेश की भारी समस्या बनी हुई है. राजनीतिकारों को इससे कोई लेना देना नहीं. चीड़ के जंगलों में आग से जीव-जगत नष्ट हो रहा है और पर्यावरण के लिए अत्यधिक घातक साबित हो रहा है. उत्तराखंड के किसानों को फसल का उच्चतम मूल्य एवं समय से भुगतान नहीं मिल रहा है. किसान गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं. राजनीतिक दलों के नेता अपने भाषणों में उत्तराखंड में अलग से हिमालय नीति लागू करने की बात तो करते हैं, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं होता.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में अपराध, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अनियंत्रित ट्रैफिक जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. इसके अलावा नदी के कछारी इलाकों में रेत-पत्थर चुगान और अवैध खनन बेतहाशा हो रहा है. खनन के धंधे में माफिया शामिल हैं और नेता उनके संरक्षक हैं. बड़े पैमाने पर हो रहे गैरकानूनी खनन से नदियां हर साल अपना रास्ता बदल दे रही हैं. दूसरी तरफ निर्माण के लिए जरूरी रेत, रोड़ी, पत्थर वगैरह आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है. इसके लिए प्रदेश में कोई प्रभावी खनन नीति नहीं है और अवैध खनन रोकने में सरकार की कोई रुचि नहीं है. लगातार आपदाओं की मार झेल रहे इस प्रदेश के भूस्खलन वाले क्षेत्रों और टिहरी बांध जैसी बिजली परियोजनाओं के कारण बेदखल लोगों के लिए अभी तक कोई ठोस पुनर्वास नीति का भी निर्माण नहीं हो पाया है. असंगत विकास की कठिनाइयां झेल रहा टिहरी और प्रतापनगर क्षेत्र नाकारे राजनीतिक प्रबंधन का उदाहरण है. उत्तराखंड जल बिजली परियोजनाओं का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इस पर्वतीय प्रदेश के सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है. प्रदेश में जहां बिजली लाइन है वहां भी घंटों तक बिजली गुल रहना आम बात है. विडंबना यह है कि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के नुकसान तो उत्तराखंड ने झेले लेकिन विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड का हिस्सा सिर्फ 12.5 प्रतिशत आता है, जबकि बिजली परियोजनाओं में उत्तराखंड का लाभांश दोगुना किया जाना चाहिए.■

एजेंडा पेश किया था, उसमें विकास के 165 मुद्दे शामिल थे. उनमें कृषि, ऊर्जा, अवस्थापना, सुविधाओं का सृजन, मानव संसाधन विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, ग्राम्य विकास, कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, श्रम, प्रशासन तंत्र को कुशल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाए जाने के नए प्रयासों का उल्लेख था. मेट्रो परियोजना भी शामिल थी. इसी तरह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का काम भी एजेंडे में शुमार था. मेट्रो और आगरा एक्सप्रेस-वे पर काम तो हुआ, लेकिन अधिकांश अन्य मसले ऐसे ही रह गए. आम शहरी कहते हैं कि उन्हें ठीक सड़क, दुरुस्त बिजली और पुख्ता कानून व्यवस्था चाहिए. लेकिन उन्हें ये चीजें नहीं मिलीं.

किसान कहते हैं कि चीनी मिलों से उनके बकाये का भुगतान हो, उनकी फसलों का उचित दाम तय हो और उन पर कर्जों का बोझ न हो, जिससे आत्महत्याएं न हों. लेकिन किसानों की अपेक्षा पर कोई काम ही नहीं हुआ. कृषि और किसानों के विकास की कोई योजना ठोस शक्ल नहीं ले सकी. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान खेत योजना बनाई गई थी. इसके तहत किसानों को खेतों में ही जाकर प्रशिक्षित किया जाना था. उन्हें फसलों की बुआई, रोगों का उपचार, फसल कटाई और मड़ाई आदि की तकनीकी जानकारी दी जानी थी. किसानों को खाद के प्रयोग और भूमि की उर्वरा शक्ति परीक्षण के लिए भी जागरूक करने की योजना थी. साथ ही किसानों को गोबर और जैविक खाद के लाभ भी बताए जाने थे, लेकिन इस योजना को अधिकारियों ने जमीन पर ही नहीं उतरने दिया. किसान पूछते हैं कि वे मेट्रो रेल खाएं या एक्सप्रेस-वे चबा जाएं. दूसरी तरफ खेतों में घटता मानव श्रम भी विकट समस्या है. इसका भी कोई निराकरण नहीं हो रहा. इसका मुकाबला करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रचार-प्रसार के साथ ही छोटे और मंझोले किसानों को ये उपकरण सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.■

feedback@chauthiduniya.com

हिंदी की ताक़त का क़रार

अनंत विजय

बिहार की राजधानी पटना में आयोजित पुस्तक मेला हाल में संपन्न हुआ है. पुस्तक मेलों के लिहाज से देखें तो पटना पुस्तक मेला देश के बड़े पुस्तक मेलों में शुमार होता है. दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की ही तरह पटना में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यिक मसलों पर मंथन होता रहता है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित इस पुस्तक मेले को पूरब का सांस्कृतिक कुंभ कहना गलत नहीं होगा. ग्यारह दिन चलनेवाले इस पुस्तक मेले को लेकर देशभर के साहित्यकारों में उत्सुकता बनी रहती है. सहभागिता को लेकर भी और हाय हुसैन सिंड्रोम को लेकर भी पुस्तक मेला चर्चा में रहता है. इस बार तो इस मेले ने सोशल मीडिया पर भी अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करवाई. इसके पक्ष और विपक्ष में कमेंट्स लिखे गए. कुछ ऊलजलूल आरोप भी लगे. इसके बावजूद यह आयोजन खूब सफल रहा और अपने तेइसवें संस्करण में भी पाठकों का जबरदस्त प्यार इसको मिला. इस बार पटना पुस्तक मेले में दलित साहित्य से लेकर लेखन से गायब होते रोमांस तक की चर्चा हुई. नरेन्द्र कोहली से लेकर स्थानीय लेखकों ऋषिकेश सुलभ और आलोक धन्वा की भागीदारी रही. बच्चों को लेकर दिनभर पुस्तक मेले में कार्यक्रम हुए, लेकिन इस बार पुस्तक मेले में एक ऐसी साहित्यिक घटना घटी, जिसकी अनुगूंज काफी लंबे समय तक साहित्य जगत में सुनाई देनेवाली है.

हिंदी में इस बात को लेकर हमेशा से रोना रोया जाता है कि लेखकों को पैसे नहीं मिलते. हिंदी की किताबों की कम बिक्री को लेकर लेखकों और प्रकाशकों के बीच चिंता देखी जा सकती है. इस बात पर कमोबेश हर गोष्ठी आदि में रेखांकित किया जाता है कि हिंदी में खरीदकर पढ़नेवाले पाठक नहीं हैं. बहुधा प्रकाशकों और लेखकों के बीच संबंध खराब होने की वजह किताबों की रॉयल्टी ही बनती रही है. लेकिन पटना में जो हुआ वो हिंदी में एक नई मिसाल कायम करनेवाला है. बिहार के सबसे पुराने प्रकाशकों में से एक नोवेल्टी प्रकाशन ने अपने स्थापना के पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर अब साहित्यिक प्रकाशन के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला लिया है. ब्लूबर्ड नाम के नए प्रकाशन की शुरुआत के साथ ही नोवेल्टी प्लेटिनम सीरीज के तहत स्तरीय साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन की योजना बनाई है. संस्थान ने ऐलान किया कि थोक के भाव से साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन की बजाए वो साल में एक या दो ऐसी किताबों को छापेगा जिन्हें वृहत्तर पाठक वर्ग तक पहुंचाकर इस मिथक को तोड़ने का प्रयास होगा कि हिंदी में किताबें नहीं बिकती हैं. नोवेल्टी ने अपने इस नए उपक्रम नोवेल्टी प्लेटिनम के तहत पहली किताब चुनी है हिंदी के कथाकार, मीडिया विशेषज्ञ और संस्कृतिकर्मी रत्नेश्वर कुमार सिंह की. उनके उपन्यास रेखना मेरी जान को इस सीरीज के तहत प्रकाशित करने का एलान करते हुए नोवेल्टी ने रत्नेश्वर के साथ एक करोड़ पचहत्तर लाख के अनुबंध की घोषणा भी की. यह किसी भी भारतीय प्रकाशक के लिए किसी एक लेखक को दी जानी वाली अबतक की सबसे बड़ी राशि है. अनुबंध के लिए साइनिंग अमांउट के तौर पर रत्नेश्वर को ढाई लाख का चेक मेले के दौरान हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौंपा गया. प्रकाशक ने रेखना मेरी जान की दस लाख प्रतियां बेचने का लक्ष्य रखा है. नोवेल्टी के अमित झा का दावा है कि उन्हें हिंदी की ताकत का एहसास है और उसके हिसाब से ही उन्होंने रत्नेश्वर की किताब को बेचने की रणनीति बनाई है. तीन अप्रैल से इस किताब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो रही है और पांच अप्रैल से पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी. किसी एक किताब के लिए इस तरह की रणनीति और महात्वाकांक्षी लक्ष्य हिंदी में तो कम से कम पहली बार देखने को मिल रहा है. तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए लेखक और प्रकाशक दोनों मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं. देशभर के हर शहर में इस उपन्यास को लेकर कार्यक्रम आदि करने की योजना है, जिसमें लेखक की मौजूदगी होगी और वो अपने पाठकों से संवाद भी करेंगे.

> हिंदी में इस बात को लेकर हमेशा से रोना रोया जाता है कि लेखकों को पैसे नहीं मिलते. हिंदी की किताबों की कम बिक्री को लेकर लेखकों और प्रकाशकों के बीच चिंता देखी जा सकती है. इस बात पर कमोबेश हर गोष्ठी आदि में रेखांकित किया जाता है कि हिंदी में खरीदकर पढ़नेवाले पाठक नहीं हैं. बहुधा प्रकाशकों और लेखकों के बीच संबंध खराब होने की वजह किताबों की रॉयल्टी ही बनती रही है. लेकिन पटना में जो हुआ वो हिंदी में एक नई मिसाल कायम करनेवाला है.

अभी कुछ साल पहले ही अंग्रेजी के एक प्रकाशक ने शिवा त्रैयी पर उपन्यास लिखनेवाले अंग्रेजी के स्टार लेखक अमीष त्रिपाठी के साथ उनके आगामी उपन्यासों के लिए पांच करोड़ रुपए का करार किया था. उस करार में किताब, ऑडियो बुक और ई बुक्स का वैश्विक अधिकार भी शामिल था. अमिष के प्रकाशक ने उनकी किताबों की बिक्री को आधार बनाकर यह करार करने का दावा किया था. अमिष त्रिपाठी पहले से बेस्टसेलर रहे हैं और अंग्रेजी में किताबों का एक बड़ा बाजार पहले से रहा है. अमिष त्रिपाठी के उस करार को लेकर बाद में कई विवादित बातें सामने आई थीं, लेकिन हिंदी में एक किताब के लिए पौने दो करोड़ का करार परीकथा की तरह लगता है. हिंदी के लेखकों को इस करार पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है. रत्नेश्वर का प्रतीक्षित उपन्यास ग्लोबल वार्मिंग को केंद्र में रखकर लिखा गया है. ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े विषय के बड़े कैनवास के बीच इस उपन्यास में एक बेहद इंटेंस प्रेम कथा भी साथ-साथ चलती है. ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर विषय के साथ प्रेम को जोड़कर कथा को आगे बढ़ानेवाले रत्नेश्वर को उम्मीद है कि पाठकों को यह विषय बहुत पसंद आएगा. आत्मविश्वास से लबालब रत्नेश्वर कहते हैं कि जिस देश में करीब साठ करोड़ हिंदी भाषी हों वहां दस लाख किताबें बिकनी ही चाहिए और इसपर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको हिंदी की ताकत का एहसास नहीं है. उनको उम्मीद है कि रेखना मेरी जान के प्रकाशन के बाद एक बार फिर से हिंदी की ताकत स्थापित होगी. रत्नेश्वर पौने दो करोड़ रुपए के करार को लेकर उत्साहित तो थे लेकिन दिमाग सातवें आसमान पर नहीं है. एक उपन्यास के लिए पौने दो करोड़ का करार करने वाले पहले हिंदी लेखक बनकर रत्नेश्वर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है. वो कहते हैं कि इस करार के बाद उनसे हिंदी की ताकत को स्थापित करने की साथी लेखकों और पाठकों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है. वो इस बात से पूरी तरह से मुतमईन हैं कि उनका उपन्यास हिंदी लेखन में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा और उसकी प्रतिष्ठा उसको हासिल होगी. ■

anant.ibn@gmail.com

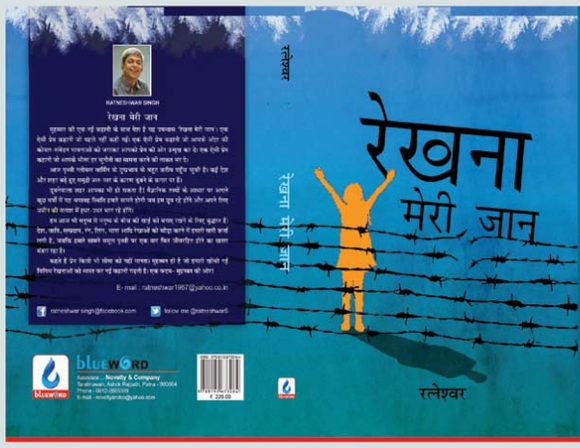

कासनी

परिचय

इसका मूल उत्पत्ति स्थान कासान नामक नगर माना जाता है इसलिए इसे कासनी कहते हैं. आयुर्वेद के प्राचीन संहिताओं में इसका उल्लेख नहीं है. यह पश्चिमोत्तर भारत, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, दक्षिण भारत तथा उत्तराखंड में 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है. इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं. 1. कासनी ग्राम्य और 2. कासनी वन्य.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **शिरो रोग–** कासनी बीज चूर्ण 1-2 ग्राम अथवा क्वाथ 10-20 मिली का सेवन करने से शिरो शूल का शमन होता है.
- **मुख रोग–** 2 ग्राम कासनी के पत्तों को पीसकर, ठण्डे पानी के साथ सेवन करने से रक्त वमन तथा रक्तष्ठीवन में लाभ होता है.
- **मुखपाक–** कासनी के बीजों का क्वाथ बनाकर गरारा करने से मुखपाक तथा मसूढ़ों की पीड़ा का शमन होता है.
- **उदर रोग–** 10-20 मिली कासनी बीज क्वाथ का सेवन करने से पित्तज छर्दि में लाभ होता है.
- कासनी के बीजों का फाण्ट बनाकर 15-20 मिली मात्रा में पिलाने से पित्तज छर्दि तथा अन्य पित्तज विकारों में लाभ होता है.
- **यकृत प्लीहा रोग–** 5-10 मिली कासनी पत्र-स्वरस या 15-20 मिली कासनी पत्र क्वाथ का सेवन कराने से कामला में लाभ होता है. इस अवधि में रोगी को तक्र और चावल या दूध तथा चावल का सेवन करना चाहिए. घी तथा शक्कर का प्रयोग वर्जित है.
- कासनी के पुष्पों का शर्बत बनाकर पिलाने से यकृत-विकारों में लाभ होता है.
- **अस्थिसंधि रोग–** कासनी के पत्रों को पीसकर लेप करने से संधिशूल तथा संधिशोध में लाभ होता है.
- **मानस रोग–** कासनी के पत्तों को जौ के आटे के साथ पीसकर हृदय प्रदेश पर लेप करने से उष्णताजन्य उन्माद तथा हृदय विकारों में लाभ होता है.
- **अनिद्रा–** कासनी बीज चूर्ण तथा वनफ्सा पुष्पों का क्वाथ बनाकर 15-30 मिली मात्रा में पिलाने से नींद अच्छी आती है.
- **पित्तज ज्वर–** कासनी के पत्रों के साथ पित्तपापड़ा, गिलोय, नागरमोथा तथा खस मिलाकर क्वाथ बनाएं. 15-20 मिली क्वाथ का सेवन करने से तृष्णा, बेचैनी, अतिस्वेद, निद्रानाश, मूत्रदाह तथा पित्तज ज्वर में लाभ होता है.

कासनी वन्य

- **शिरो रोग–** कासनी पत्र-स्वरस को माथे पर लगाने से या कासनी पत्र-स्वरस को चन्दन के साथ पीसकर मस्तक पर लगाने से शिर शूल में लाभ होता है.
- **नेत्र रोग–** कासनी पत्र को वनफ्सा के फूलों के साथ पीसकर नेत्र के बाहर चारों तरफ लगाने से नेत्र-विकारों का शमन होता है.
- **मुख रोग–** कासनी के बीजों का क्वाथ बनाकर गरारा करने से मुख रोग में लाभ होता है.
- **हृदय रोग–** कासनी के ताजे पत्रों को जौ के आटे के साथ पीसकर हृदय स्थान पर लेप करने से हृदय विकारों में लाभ होता है.
- **अस्थिसंधि रोग–** कासनी पंचांग को जौ के आटे के साथ पीसकर जोड़ों में लगाने से आमवात में लाभ होता है. इस प्रकार का लेप पैत्तिक उन्माद तथा वातरक्त में भी लाभप्रद होता है.
- **त्वचा रोग–** कासनी के पत्तों को लाल चन्दन, गुलाब अर्क तथा सिरके के साथ पीसकर लगाने से शीतपित्त में लाभ होता है. ■

प्रयोज्यांग : पंचांग.

मात्रा : चूर्ण 3-6 ग्राम. स्वरस 10-20 मिली या चिकित्सक के परामर्शानुसार.

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

गुरु-मार्ग का अनुसरण

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

सद्गुरु की ओर जाने वाला रास्ता ही आध्यात्मिक जीवन का असली रास्ता है. विशेष रूप से आज के द्वंद्व/संघर्षों, अन्तर्विरोधों से भरे घोर भौतिकतावादी युग में सद्गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का और भी अधिक महत्व है. जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि जैसे सभी नदियां सागर की ओर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो भी रास्ता अपनाता है, वे सभी रास्ते उसे शाश्वत ईश्वर की ओर ले जाते हैं. अधिकतर साधकों द्वारा जो साधना-पद्धतियां अपनायी जाती हैं, वे हैं- राजयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, हठयोग, लययोग, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग आदि. इनके अलावा अवधूत, कापालिक, अघोरी और अन्य बहुत प्रकार के साधक होते हैं. विभिन्न धर्मों की विभिन्न मान्यताएं हैं. ईश्वरीय अनुभूति के बारे में विभिन्न मान्यताओं के होते हुए भी सर्वजागतिक कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, जो सभी धर्मों में समान रूप से एक हैं. जो साधक इस सर्वजागतिक मार्ग को अपनाते हैं, वे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को दूसरों की अपेक्षा जल्दी प्राप्त कर लेते हैं.

शिरडी मस्जिद में बैठे हुए बाबा ने कहा था कि अनेक पथ हैं, परन्तु ईश्वर तक पहुंचने का एक पथ द्वारकामाई से होकर भी गुजरता है. यदि ध्यानपूर्वक यह देखा जाए कि शिरडी में बाबा ने लाखों-करोड़ों लोगों को ईश्वरीय अनुभूति की दिशा में कैसे प्रेरित किया, तो उसका एक स्पष्ट रूप दिखाई देता है. साईं-पथ मूलतः इन पर आधारित है-

-देह-रूप में एक ऐसे दिव्य/सम्पूर्ण स्वरूप का होना, जिन्हें सामान्यतः 'परफेक्ट मास्टर', 'सद्गुरु' या सूफियों द्वारा जिन्हें 'कुतुब' कहा जाता है. साधारणतः 'कुतुब' का अर्थ 'धुरी' अथवा केन्द्रबिन्दु है, जिसके चारों ओर अन्य सभी अर्थात् चेतन प्राणी एवं जड़ प्रकृति दोनों घूमते हैं. मानव समेत अन्य सब जीव चेतना के क्रम-विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए जीवन-मुक्त अवस्था में पहुंचते हैं. लेकिन फिर भी इनमें से वे, जो अपनी अथाह करुणा के कारण आनन्दमयी ईश्वरीय अवस्था के परम सुख का त्याग करते हैं और दोष एवं अवगुणों से युक्त दुखी मानवता की सेवा के लिए इस पृथ्वी पर देह-रूप में अवतरित होते हैं- उन्हें सद्गुरु कहते हैं. श्री मेहर बाबा ने कहा है कि किसी समय में पृथ्वी पर पांच सद्गुरु देह-रूप धारण कर सक्रिय भूमिका निभाते हैं.

- शरीरधारी सद्गुरु एक सामान्य मनुष्य एवं ईश्वर-दोनों ही रूपों में कार्य कर सकते हैं. ईश्वर-रूपी सद्गुरु में असीमित शक्ति, असीम ज्ञान, अनन्त सुख एवं चिरन्तन सत्ता होती है. ईश्वर के समान वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ होते हैं और उनमें दिव्य/अलौकिक शक्तियां होती हैं. वे अपनी शक्ति, ज्ञान और सुख संसार में लाखों लोगों के साथ बांटते हैं. इसके लिए वे जो मार्ग अपनाते हैं, उसे समझ पाना या उसकी कल्पना भी कर पाना मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है. इसी को उनकी लीला या ईश्वरीय चमत्कार कहते हैं. सभी चमत्कार प्रकृति के नियमों पर आधारित हैं, जिन्हें केवल जानने, अनुभव करने एवं समझने की आवश्यकता है. अग्नि, जल, वायु आदि- जिन्हें हिन्दू देवता मानते हैं- प्रकृति की ये सभी मूलभूत शक्तियां सद्गुरु के आदेश एवं इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं. ईश्वर की भांति सद्गुरु भी स्वयं में सबको एवं सबमें स्वयं को देखते हैं. वे बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करते हैं, जैसे कि वे स्वयं अपनी सेवा कर रहे हों. वे सबमें ईश्वर को देखते हैं, भले ही दूसरे उनमें ईश्वर को न देख सकें. वे दूसरों को असीम सुख प्रदान करते हैं और दूसरों की अपार पीड़ा को अपने ऊपर लेते हैं. यदि एक बार भी कोई मनुष्य या कोई भी प्राणी उनसे किसी भी रूप में जुड़ता है, तो वे जन्म-जन्मांतर तक उसकी चेतना का विकास सुनिश्चित करते हैं, जब तक कि जीव ईश्वर में विलीन न हो जाए. चेतना के विकास की इस परम और अंतिम अवस्था को सामान्यतः मुक्ति या मोक्ष कहते हैं.

- केवल सद्गुरु ही मनुष्य को ईश्वरीय साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं. वे सभी धर्मों में समान रूप से व्याप्त एवं प्रेम पर आधारित मानवतावादी आदर्शों का पालन करते हैं. भक्तों के प्रति अपने अतिशय प्रेम के कारण वे न केवल उनके आध्यात्मिक विकास, बल्कि उनकी भौतिक आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं. एक बार जब कोई भक्त उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो वे उसकी आवश्यकताओं का ठीक उसी प्रकार ध्यान रखते हैं जैसे कि एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, यहां तक कि वे अपनी देह तक त्याग कर सकते हैं. यही सब बाबा ने अपने अनेक भक्तों के लिए किया था, जो कि 'श्री साईं सच्चरित्र' के अध्ययन एवं विभिन्न भक्तों के अनुभवों से पता चलता है. बाबा से निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि कठिन-से-कठिन परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक उनके प्रति अपने विश्वास को बनाए रखें, साथ ही अपने भीतर विनम्रता, त्याग, सहनशीलता एवं भक्ति आदि गुणों को विकसित करें और सद्गुरु के आदर्शों/आशाओं के अनुरूप कार्य करें.

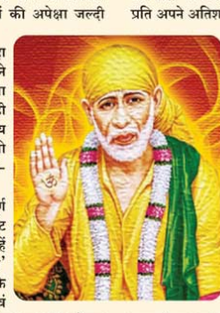

यदि कोई सच्ची गुरुभक्ति के मार्ग पर चलता है, तो वह अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी और आसानी से आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है. बाबा अनेक भक्तों को विभिन्न देवताओं, जैसे- हनुमान, गणेश आदि के रूप में दर्शन देते थे. फलतः भक्तों को विश्वास हो गया था कि बाबा तथा अन्य देवताओं, यहां तक कि ईश्वर और उनमें कोई भेद नहीं है. अतः गुरु-मार्ग के प्रथम चरण में यह आवश्यक है कि भक्त उन सभी देवी-देवताओं, जिनका कि वे पूजन करते हैं, उनमें बाबा को देखें और बाबा की उसी रूप में पूजा करें जैसे कि वे अपने उन देवताओं की पूजा करते हैं. संक्षेप में हमें सब कुछ बाबा में ही देखना चाहिए और उन्हीं से ही वह सब कुछ पाने की आशा करनी चाहिए. शुरू-शुरू में यह मार्ग कठिन लगता है, पर बाबा के प्रति दृढ़ निष्ठा एवं विश्वास के द्वारा इसे अवश्य प्राप्त किया जा सकता है. अतः यह उचित है कि हम सब इस दिशा में प्रयास करें. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

फिक्सिंग के दलदल में पाक क्रिकेट

- पाक सुपर लीग बना फिक्सिंग का नया अड्डा
- क्रिकेट और फुटबॉल में अब धड़ल्ले से हो रही है फिक्सिंग
- पाक क्रिकेटर शर्जील और खालिद ने की फिक्सिंग

सैयद मोहम्मद अब्बास

कहते हैं कि अगर किसी को पैसा कमाने का चस्का लग जाये तो वह अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ता है. क्रिकेट में खिलाड़ी अपने प्रदर्शन की बदौलत बहुत जल्द स्टार बन जाते हैं. कुछ खिलाड़ी अपने एक जानदार प्रदर्शन के सहारे अपनी तकदीर बदलने में कामयाब हो जाते हैं. उनका एक बेजोड़ प्रदर्शन उनके करियर की दशा और दिशा दोनों बदल देती है, लेकिन देखा गया है कि इसके बाद खिलाड़ी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और क्रिकेट की मर्यादाओं को छलनी करने से भी नहीं चूकते हैं. दरअसल कम समय में पैसा कमाने की चाहत कभी-कभी खिलाड़ियों को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती है. क्रिकेट में फिक्सिंग के खेल को रोकने के लिए चाहे कुछ भी किया जाये, लेकिन यह गंदा खेल बदस्तूर जारी है. इतना ही नहीं, अब क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में भी फिक्सिंग की बात लगातार सामने आ रही है. खिलाड़ी ऐसी हरकत कर देश का नाम खराब कर रहे हैं. ताजा मामला पाकिस्तानी क्रिकेटर शर्जील और खालिद के फिक्सिंग में शामिल होने का सामने आया है. एक बार फिर पाक क्रिकेट मैच फिक्सिंग की गिरफ्त में नजर आ रहा है. कुछ दिन पहले क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी मैच का परिणाम प्रभावित करने के चक्कर में कई खिलाड़ी दबोचे गए थे. एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार साओ के करीब 15 खिलाड़ियों पर मैच के परिणाम को प्रभावित करने के आरोप लगे, जिसके बाद इन खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके पूर्व कम्बोडिया के सात खिलाड़ियों पर भी गाज गिर चुकी है. खेलों की दुनिया में क्रिकेट के बाद दूसरे खेलों में भी फिक्सिंग की बाते सामने आती रही है. टेनिस में भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग को लेकर क्रिकेट में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं. आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर पहले कई खुलासे हो चुके हैं. श्रीसंत का क्रिकेट करियर इसकी भेंट चढ़ता दिख रहा है. श्रीसंत क्रिकेट की दुनिया में लौटने का दावा कर रहे हैं, जबकि बीसीसीआई ने उनके क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा रखी है. अतीत और वर्तमान में क्रिकेट में फिक्सिंग होती रही है. माना जाता है कि 90 के दशक में मैच फिक्सिंग चरम पर थी. यह वही दौर था जब अजहर जैसे काबिल खिलाड़ी का क्रिकेट करियर तबाह हो गया था. इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट भी इसकी चपेट में आता रहा है. पाकिस्तान के कई खिलाड़ी खुलेआम मैच फिक्सिंग के गंदे खेल में पकड़े गये. उनमें सलमान बट से लेकर मोहम्मद आसिफ के नाम शामिल हैं. इन दोनों के अलावा पाकिस्तान टीम के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गये, हालांकि बाद में वे मैदान पर वापसी करने में सफल रहे. इससे पूर्व सलीम मलिक का नाम भी सामने आ चुका है. सलीम मलिक पाक क्रिकेट के चमकते हुए सितारे थे, लेकिन जब उनपर यह दाग लगा तो उनका क्रिकेट करियर समय से पहले ही खत्म हो गया. अब एक बार फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फिक्सिंग में शामिल होने की बात सामने आ रही है. पाकिस्तानी सुपर लीग अब नया मैच फिक्सिंग का अड्डा बन गया है. इस लीग में एक नहीं कई खिलाड़ियों के मैच फिक्सिंग में शामिल होने की बात कही जा रही है. शर्जील और खालीद के बाद मोहम्मद इरफान और नासिर जमशेद जैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं.

> पाकिस्तानी सुपर लीग में फिक्सिंग की खबरों के बाद खुद शाहिद अफरीदी ने आरोपी खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए. सवाल यह है कि खिलाड़ी आखिर क्रिकेट के साथ क्यों गद्दारी करते हैं. अब समय आ गया है कि मैच फिक्सिंग को लेकर कड़े कदम उठाए जाएं ताकि खेल की गरिमा पर कोई आंच न आये.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग शुरू की. यह लीग क्रिकेट की दुनिया में लगातार अपना मुकाम बना रही है. आईपीएल की कामयाबी के बाद एशिया के कई और क्रिकेट बोर्ड ने इसी तरह की लीग शुरू की. उनमें श्रीलंका प्रीमियर लीग से लेकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग प्रमुख हैं. बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग की बात सामने आ चुकी है. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मोहम्मद अशरफुल पर फिक्सिंग का आरोप लगा और उनका क्रिकेट करियर खात्मे की ओर बढ़ चुका है. बोर्ड ने उनके क्रिकेट खेलने पर रोक लगा रखी है. इतना ही नहीं, दुनिया के कई और देशों के खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग अथवा स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आता रहा है. आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुई पाकिस्तानी सुपर लीग भी फिक्सिंग के दलदल में फंसती नजर आ रही है. पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार कई खिलाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. पाक बोर्ड के अनुसार कुछ खिलाड़ी अब भी रडार पर हैं. पाकिस्तान के खतरनाक ओपनरों में शुमार शर्जील खान रंगे हाथ स्पॉट फिक्सिंग में दबोचे गये हैं, जबकि नासिर जमशेद को भी निलंबित कर दिया गया है. पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचाररोधी इकाई लगातार इस बात का पता लगाने में जुटी है कि और कौन-कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल हैं. शुरुआती जांच में कई और खिलाड़ियों के नाम शामिल होने की बात कही जा रही है. पाक लीग में सट्टेबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है. पाकिस्तानी सुपर लीग में पकड़ गये खिलाड़ियों में ज्यादातर इस समय पाक टीम का हिस्सा भी हैं. ऐसे में उनका क्रिकेट करियर अब दांव पर लगता दिख रहा है.

पाकिस्तानी सुपर लीग से पूर्व आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के मामले सामने आ चुके हैं. इसमें कई खिलाड़ियों को दोषी पाया गया था, इतना ही नहीं, बोर्ड के कई आधिकारियों पर उस दौरान सवाल उठाया गया था. आईपीएल की दो बड़ी टीम चेन्नई और राजस्थान टीम की तब इस लीग से छुट्टी भी कर दी गई थी. दोनों टीम के मालिकों पर सट्टेबाजी करने का संगीन आरोप लग चुका है. इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आनन-फानन में कई बड़े कदम उठाये. कई खिलाड़ियों के फिक्सिंग में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया.

आईपीएल से पहले भी फिक्सिंग को लेकर कई खुलासे होते रहे हैं. विदेशी खिलाड़ियों के साथ-साथ भारतीय खिलाड़ियों को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं. 90 के दशक में मैच फिक्सिंग को लेकर कई अहम खुलासे होते रहे हैं. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन पर मैच फिक्सिंग का गंभीर आरोप लगा. इस मामले में लंबी जांच के बाद बीसीसीआई ने उनके करियर पर विराम लगा दिया था. दरअसल अजहर 100 टेस्ट मैच खेलते-खेलते रह गये और 99 टेस्ट ही खेल सके. इसके बाद अजहर का क्रिकेटीय कद एकदम से गिर गया. हालांकि लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद अजहर को कोर्ट से राहत मिल गयी. इतना ही नहीं, इसी दौर में जडेजा का क्रिकेट करियर भी फिक्सिंग के चलते खत्म हो गया. मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा भी इस खेल में अहम किरदार साबित हुए थे.

क्रिकेट के जानकारों की मानें तो 90 के दशक में शारजाह में क्रिकेट को लेकर फिक्सिंग का खेल सबसे ज्यादा खेला जाता था. विदेशी खिलाड़ियों ने कई बार पैसे लेकर मैच को प्रभावित किया है, हालांकि ये सभी खिलाड़ी बाद में जुर्माना देकर छूट गये. इसके बाद न सिर्फ बीसीसीआई, बल्कि आईसीसी भी इसे जड़ से खत्म करने का दावा करती रही है, इसके बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी लगातार मैच फिक्सिंग के खेल में शामिल रहे हैं. पाकिस्तानी क्रिकेट के खराब प्रदर्शन को अक्सर सवालों के घेरे में देखा जाता रहा है. पाकिस्तानी क्रिकेट की यह विडंबना रही है कि फिक्सिंग में पकड़े गये खिलाड़ियों पर वह हमेशा नरमी दिखाती रही है. स्पॉट फिक्सिंग में दागदार रहे खिलाड़ी सलमान बट और मोहम्मद आसिफ लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी करने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं. इतना ही नहीं पाकिस्तानी बोर्ड भी इनपर नरम पड़ता दिख रहा है.

पाकिस्तानी सुपर लीग में फिक्सिंग की खबरों के बाद खुद शाहिद अफरीदी ने आरोपी खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए. सवाल यह है कि खिलाड़ी आखिर क्रिकेट के साथ क्यों गद्दारी करता है. अब समय आ गया है कि मैच फिक्सिंग को लेकर कड़े कदम उठाए जाएं ताकि खेल की गरिमा पर कोई आंच न आये. ■

feedback@chauthiduniya.com

7 अप्रैल को रिलीज होगी जग्गा जासूसः बसु

फिल्म निर्देशक अनुराग बसु ने जग्गा जासूस की रिलीज को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लगा दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इस बात को जाहिर किया है. आपको बता दें कि जग्गा जासूस करीब दो साल से बन रही है. यह फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. इसकी टक्कर सीधे अमिताभ बच्चन स्टारर सरकार 3 से होगी. बॉक्स ऑफिस पर इस बड़ी लड़ाई के लिए अनुराग बसु ने भी कमर कस ली है. उन्होंने कहा कि जग्गा जासूस एक फैमिली फिल्म है. कई जगहों पर बच्चों की परीक्षा की तारीख को देखकर रिलीज की डेट आगे बढ़ सकती है. हम अपनी फिल्म की रिलीज की तारीख तभी आगे बढ़ाएंगे, जब हमें कोई अच्छी तारीख मिले. बहरहाल, जग्गा जासूस से जुड़ी इस जानकारी के बाद अनुराग बसु ने रिलीज की डेट पर से पर्दा हटा दिया है. मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म में 29 गाने हैं. ■

खिलाड़ी की बढ़ती डिमांड

अक्षय हैं बॉलीवुड के असली बॉस

खिलाड़ी अक्षय साल 2016 से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. पिछले साल भी उन्होंने लगातार 3 सुपरहिट फिल्में दी थीं. अक्षय की इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार भारत में किया था. जॉली एलएलबी 2 अक्षय की लगातार चौथी सौ करोड़ी फिल्म है.अक्षय का शानदार फॉर्म इस साल भी जारी है.

प्रवीण कुमार

बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख और आमिर खान के बाद अगर कोई तेजी से बढ़ रहा है तो वह है खिलाड़ी अक्षय कुमार. जी हां, अक्षय कुमार की फिल्में भले ही इन तीनों खानों के मुकाबले दो-तीन सौ करोड़ नहीं कमा पाती हों, लेकिन यह खिलाड़ी बेहद कम बजट की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ का कारोबार कराने में सक्षम है. वहीं तीनों खानों और दूसरे अभिनेताओं की फिल्मों का बजट अक्षय कुमार की फिल्मों से ज्यादा होता है. बॉक्स ऑफिस पर अक्षय का लगातार बेहतर परफॉर्मेंस उनकी डिमांड और बढ़ा रहा है. इससे पहले अक्षय कुमार ने राउडी राठौर, एयर लिफ्ट, रुस्तम, हॉलीडे, हाउसफुल-2, 3, बेबी, सिंह इज किंग, गब्बर: इज बैक, सिंह इज ब्लिंग, ब्रदर्स आदि हिट फिल्मों से दूसरे अभिनेताओं और बॉक्स आफिस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है.

हाल में अक्षय की जॉली एलएलबी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए 100 करोड़ का व्यापार आसानी से पूरा कर लिया.

खिलाड़ी अक्षय साल 2016 से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. पिछले साल भी उन्होंने लगातार 3 सुपरहिट फिल्में दी थीं. अक्षय की इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार भारत में किया था. जॉली एलएलबी 2 अक्षय की लगातार चौथी सौ करोड़ी फिल्म है.

अक्षय का शानदार फॉर्म इस साल भी जारी है. अक्षय अपने हर किरदार में एकदम फिट बैठते हैं, चाहे वह कॉमेडी हो, एक्शन हो या फिर कोई सीरियस रोल, दर्शक उन्हें हर किरदार में देखना पसंद करते हैं. यही कारण है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ते हुए सौ करोड़ से ऊपर का व्यवसाय करती हैं. जॉली एलएलबी 2 के सौ करोड़ कमाते ही यह फिल्म खिलाड़ी अक्षय के करियर की 7वीं सौ करोड़ी फिल्म बन गई है. इसके साथ ही अभिनेताओं की टॉप 5 लिस्ट में अक्षय कुमार सौ करोड़ की फिल्म देने वाले दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. पहले स्थान पर सलमान खान की 10 फिल्में हैं. अक्षय कुमार इस समय फिल्म पैडमैन, क्रैक, रोबोट 2.0, नाम शबाना, टॉयलेट- एक प्रेम कथा और गोल्ड से जुड़े हैं. ■

आइए जानते हैं अक्षय कुमार के करियर की टॉप 10 कमाई करने वाली फिल्में कौन सी हैं?

फिल्म	साल	कमाई (करोड़ में)
राउडी राठौड़	2012	131.00
एयर लिफ्ट	2016	129.00
रुस्तम	2016	127.42
हाउसफुल 2	2012	114.00
हॉली डे	2014	112.65
हाउसफुल 3	2016	107.70
जॉली एलएलबी 2	2017	104.45 *
बेबी	2015	95.50
सिंग इज ब्लिंग	2015	90.25
गब्बर इज बैक	2015	86.00
ब्रदर्स	2015	82.47

feedback@chauthiduniya.com

फिल्मी ख़बरें

ट्यूबलाइट का प्रचार नहीं करेंगे सलमान

वैसे तो सलमान खान को खुद की फिल्म का प्रमोशन करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनकी फैंस फॉलोइंग ही इतनी जबरदस्त है कि उनके फैंस सिनेमाघर तक अपने आप खिंचे चले आते हैं. लेकिन इस बार सुनने में आया है कि सलमान खान जिस तरह से अपनी फिल्मों का प्रमोशन समय से पहले करने लगते हैं, इस बार वे ऐसा नहीं करेंगे. जी हां, यह बात सच है. क्योंकि इस बार सलमान ने बाहुबली के लिए यह मैदान छोड़ा है.

सूत्रों की मानें तो सलमान ने अपनी प्लानिंग कुछ ऐसी की है कि वो अपनी फ़िल्म ट्यूबलाइट का प्रचार बाहुबली रिलीज़ हो जाने के बाद करेंगे. वो समझ गए हैं कि उससे पहले फ़िल्म को प्रमोट करना बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहने वाला है. यानी बाहुबली के लिए उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया है. गौरतलब है कि एसएस राजामौली की बाहुबली 1 कमाल की सुपरहिट साबित हुई थी और बाहुबली 2 अप्रैल 24 को रिलीज़ हो रही है. इस फ़िल्म का इंतज़ार इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के फैंस को है. ऐसे में सलमान ख़ान बाहुबली से पहले न तो ट्यूबलाइट के प्रोमो की बात सोच रहे हैं न प्रमोशन की. सलमान यही चाह रहे हैं कि एक बार बाहुबली का शोर थम जाए उसके बाद ही वो ट्यूबलाइट के प्रचार में लगें.

याद होगा कि पिछली बार भी बाहुबली और सलमान में कनेक्शन था. उस साल भी बाहुबली की रिलीज के बाद सलमान खान की बजरंगी भाईजान आई थी. दोनों ही फिल्में साल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. ट्यूबलाइट 23 जून को रिलीज़ हो रही है और सोमवार 26 जून को ईद है. यानी सलमान ख़ान को ट्यूबलाइट रिलीज़ होते ही लगातार 5 दिन ऐसे मिलने वाले हैं जब छुट्टी होगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

शाहिद को किस करना किसी ट्रैजेडी से कम नहीं थाः कंगना

बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकीं क्वीन कंगना रनौत अपनी रिलीज हो चुकी फिल्म रंगून के एक किस्से को लेकर सुर्खियों में हैं. वे इसे अपनी ज़िंदगी में किसी ट्रैजेडी से कम नहीं मानती हैं.

अभिनेत्री कंगना ने बताया कि फिल्म रंगून की शूटिंग के दौरान उन्हें कुछ ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ा था, जो उनके लिए ठीक नहीं रहा. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान सर्द मौसम की वजह से शाहिद कपूर को जुकाम हो गया था. उसी दौरान कंगना और शाहिद को एक किसिंग सीन शूट करना पड़ गया. एक तो शाहिद की बड़ी मूंछ वैसे ही इतनी डरावनी थी कि उन्हें देखकर मेरा उनके साथ किसिंग सीन करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी ट्रैजेडी केवल वहीं ख़त्म नहीं हुई. जब मैंने शाहिद से उनकी मूंछों को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि वह उस पर वैक्स लगाते हैं और साथ में उनकी नाक भी बह रही थी, जो उन मूंछों में ही भर जाती थी.

इंटरव्यू के दौरान कंगना ने इस घटना को शूटिंग के दौरान उनके साथ हुई सबसे बड़ी ट्रैजेडी करार दिया. कंगना ने कहा, वैसे भी मुझे फिल्मों में अंतरंग सीन पसंद नहीं हैं. उन्हें शूट करना सबसे मुश्किल काम होता है. आपका किसी के साथ बेहद औपचारिक रिलेशन है और अचानक आपको उसी शख़्स को किस करना पड़ जाता है.

बताया जा रहा है कि रंगून फिल्म में कंगना द्वारा निभाया मिस जूलिया का किरदार ऑस्ट्रेलिया की स्टंट अभिनेत्री मैकी इवांस के असल जीवन पर आधारित है, जिन्हें फियरलेस नाडिया के नाम से जाना जाता है. ■